

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

19 मार्च 1981

खंड 1, अंक 9

अधिकृत विवरण

विशय सूची

वीरवार, 19 मार्च, 1981

पृष्ठ संख्या

| | |
|---|-------|
| तारांकित प्र न एव उतर | (9)1 |
| वाक आउट | (9)2 |
| तारांकित प्र न एवं उतर (पुनरारम्भ) | (9)4 |
| नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नो के लिखित उतर | (9)19 |
| आरांकित प्र न एवं उतर | (9)26 |
| वैयक्तिक स्पष्टीकरण:— | |
| (1) स्थानीय भासन मन्त्री (श्री मांगे राम गुप्ता) द्वारा | (9)28 |
| (2) डा0 मंगल सैन द्वारा | (9)29 |
| (3) श्री रघुनाथ गोयल द्वारा | (9)29 |
| (4) चौधरी वीरेन्द्र सिंह द्वारा | (9)30 |
| वि ेशाधिकार प्र न:— | |
| प्रेस में गलत रिपोर्टिंग संबंधी | (9)30 |

| | |
|---|-------|
| किसानों द्वारा चलाए जा रहे आन्दोलन संबंधी मामला अठाना | (9)31 |
| कमेटी आन गवर्नमेंट अ योरेसिज की 12वी रिपोर्ट पे ा करना | (9)33 |
| कमेटी आन दि वैलफेयर आफ ि ाड्यूल्ड कास्टस एंड ि ाड्यूल्ड ट्राइब्ज की छठी रिपोर्ट पे ा करना | (9)34 |
| वर्ष 1981-82 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ) | (9)34 |
| औचित्य प्र न | |
| निगम/बोर्ड के सभापति या सरकार के अन्य कार्यकर्ताओं के विरुद्ध पदनाम से लगाए गए आरोपों की कार्यवाही से निकालने संबंधीं | (9)50 |
| वर्ष 1981-82 के बजट पर सामान्य चौधरी उदय सिंह दलाल द्वारा चर्चा (पुनरारम्भ) | (9)51 |
| नेमिंग आफ मैम्बर्ज | (9)69 |
| बैठक का स्भागन | (9)73 |

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 19 मार्च, 1981

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9,30 बजे हुई। अध्यक्ष (कर्नल राव राम सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

Mr. Speaker: Hon. Members, Questions Hour.

Appointment of Clerks through S.S.S. Board

***2048. Sh. Bhale Ram:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the number of clerks appointed so far through the Subordinate Services Selection Board during the period from 1-11-1980 to date; and

(b) the number of persons belonging to Scheduled Castes and Back-ward Classes out of those referred to in part (a) above together -with the percentage thereof?

Mr. Speaker: The Hon. Chief Minister has asked for some time to reply this questions and, therefore, *extension

has been granted. The communications received in this connection is as under.

अ०स०पत्र 34 / 11 / 80-बी०एल-1

“ भजन लाल

मुख्य मन्त्री हरियाणा

चंडीगढ़.

मार्च 16, 1981

विशय:- तारांकित प्र न क्रमांक 2048 - अधीनस्थ सेवाएं प्रवरण मण्डल, हरियाणा द्वारा लिपिकों की नियुक्ति बारे।

प्रिय कर्नल साहब

मैं आप का ध्यान उपरोक्त विशय की और आकर्शित करते हुए कहना चाहुंगा कि तारांकित प्र न क्रमांक 2048 विधान सभा में दिनांक 19-3-1981 को उतर हेतु निश्चित हुआ है। इस प्र न द्वारा मांगी गई सूचना राज्य के सभी विभागों से एकत्रित कि जा रही है जिसमें कुछ समय लगने की सम्भावना है। इसलिए

मैं अनुरोध करूंगा कि इस प्रश्न का उत्तर देने हेतु 10 दिन का समय बढ़ा दिया जाए।

आपका

हः—

(भजन लाल)

कर्नल राव राम सिंह,

अध्यक्ष,

हरियाणा विधान सभा,

चंडीगढ़

वाक आउट

श्री भले राम: स्पीकर साहब, पिछली बार भी मैंने चही सवाल अन-स्टार्ड सवाल में तौर पर दिया था। गवर्नमेंट ने उस समय भी एक्सटैन्शन मांगी थी और आज भी एक्टैन्शन मांगी गयी है। (व्यवधान व भाोर) एक महकमे से ही तो पूछना है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो यह इन्फर्मेेशन एक घंटे के अनदन आ सकती है। मैं बता देता हूं कि दो हजार सात क्लर्क्स लिये गये हैं।

मुख्य मन्त्री (चौ० भजन लाल): स्पीकर साहब, 72 महकमो को हमने चिट्ठियां लिखी है। स्पीकर साहब, यह इनफॉर्मेशन आने और उसको कम्पाईल करने में कुछ जो समय लगेगा ही, इसलिये हमने कुछ समय मांगा है।

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, यह क्वै चन इन टाईम टेबल किया गया था और your honour had admitted it. जब ये सवाल का जवाब पूछ रहे हैं तो इनको टाल क्यों रहे है।

चौधरी भजन लाल: टाल कर हमें क्या फायदा है?(तोर व व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: क्वै चन एडमिट करने का तरीका यह है कि जो क्वै चन आता है, उस को मैरिट पर और रूल के अनुसार एग्जामिन करके मैं एडमिट कर लेता हूं, फिर उसको गवर्नमेंट के पास भेजता हू ताकि वह इन्फॉर्मेशन समय पर आ जाए तो मन्त्री जी जवाब दे देते हैं और अगर समय पर न आ पाए तो रूल के अनेसार मन्त्री जी और टाईम मांग सकते हैं और वह टाईम आम तोर पर दे दिया जाता है।

चौधरी संत कबीर: सर, मैं बता दूंगा अगर ये चाहेंगे मगर यह जवाब नहीं देना चाहते।

चौधरी भजन लाल: ऐसी काई बात नहीं है कि हम जवाब नहीं देना चाहते।

Mr. Speaker: Nothing will be recorded on this questions.

श्री भले राम: तो हम प्रोटैस्ट के तौर पर वाक आउट करते हैं।

श्री हीरा नन्द आर्य: -----

चौधरी गंगा राम: -----

फिर मैं भी एज ए प्रोटैस्ट वाक आउट करता हूँ

(At this stage Sh. Bhalle Ram followed by S/Sh. Bhag Mal, Sant Kanwar, Jai Narain and Ganga Ram staged a walk out)

एक आवाज: यह इन्फर्मेंशन तो केवल एस० एस० एस० बोर्ड से आ सकती थी, इसके लिए आपने कितने दिन की एक्सटेंशन दी है?

Mr. Speaker: I have granted 10 days extension. (Interruptions).

Sh. Virender Singh: I have to make one request. (Interruptions) आपने 10 दिन का जो सरकार को टाईम दिया है, इसको आप घटा कर 7 दिन का कर दें ता असका जवाब इसी से इन में आ जाएगा।

खाद्य तथा पूर्ति मन्त्री (श्री लक्ष्मण सिंह): वह तो आलरेडी 10 दिन का टाईम दे चुके हैं।

Sh. Virender Singh: He can reconsider it for which I have made a request.

Chaudhri Ram Lal Wadhwa: You can Sir, very well reconsider it, and give a direction which will be under the rules. So, I would request you honour to give a direction to the Government in this behalf.

Mr. Speaker: I would request the Government to send the answer within 7 days. If the answer is not complete by then तो जितना आन्सर आ जाए, उतना दे दें।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरागम)

Loss in Haryana Roadways Depots

***1948. Sh. Surender Singh:** Will the Minister for Transport be pleased to state-

(a) whether it is a fact that some of the Haryana Roadways depots are running in loss in the State; if so, the names of such depots together with the reasons therefor; and

(b) the steps, if any, taken or proposed to be taken to prevent the loss?

परिवहन मन्त्री (श्री जगन नाथ):

(क) जी हां। इस समय पांच डिपोनामतः जीन्द, सोनीपत, कैथल, भिवानी और सिरसा घाटे में चल रहे हैं। विशेषतया मुख्य कारण यह है कि इन डिपुओं का परिचालन लम्बे मार्गों पर कम है।

(ख) इनकी कार्यकुशलता में सुधार करने के लिए मार्ग के ढांचों में अनुपातन किया जा रहा है ताकि जहां तक सम्भव हो लम्बी दूरी के मार्गों की बांट में एक रूपता लाई जा सकें।

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने प्रश्न के भाग (क) के जवाब में यह कहा है कि इस समय पांच डिपो, जींद, सोनीपत, कैथल भिवानी और सिरसा घाटे में चल रहे हैं और आप भाग (ख) के उत्तर में इन्होंने यह कहा है कि इनकी कार्यकुशलता में सुधार करने के लिये मार्ग के ढांचों में अनुपातन किया जा रहा है, क्या मंत्री महोदय जरा अनुपातन की वयाख्या करेंगे?

श्री जगन नाथ: अध्यक्ष महोदय, सारे डिपो बराबर नहीं हैं। ****

Mr. Speaker: This is no answer and should be expunged. If the Hon. Minister wants to give the answer to the question, he may please do so.

श्री जगन नाथ: जहां तक प्रश्न का सम्बन्ध है, असबारे में यह है कि सारे डिपोओं की स्थिति एक जैसी नहीं है, कुछ डिपो मेन रोड पर है, यानी जी०टी० रोड पर हैं या सेंट्रल जगहों पर हैं और कुछेक कौरनर पर पड़ते हैं। ये पांचों डिपो कौरनर पर पड़ते हैं। आवागमन के हिसाब से ये ठीक ठीक नहीं बैठते इस लिये दन में घाटा चल रहा है।

चौधरी सतबीर सिंह मलिक: क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो 5 डिपुओ में घाटा चल रहा है, इसलिये तो नहीं हैं कि मन्त्री जी के पास इनकी रिपोर्ट मंगवाने और उसे देखने के लिये समय ही नहीं है?

श्री जगन नाथ: स्पीकर साहब, ऐसी बात नहीं है। स्पीकर साहब, मैं मलिक साहब को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मेरे साथ हिसार जेल में रहे थे। * * * *

श्री अध्यक्ष: यह सब एक्सपंज कर दिया जाये।

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, आप इनको चैक करिये नहीं तो फिर हम भी इसी तरह के जवाब देंगे। He is in the habit of making such remarks. (व्यवधान व भाोर)

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): यह तो मजाक की बात है। (व्यवधान व भाोर)

श्री अध्यक्ष: गवर्नमेंट के जो भी यहां पर स्पाक्समैन हैं मैं उनसे रिक्वैस्ट करुंगां कि वे अपना जवाब सिर्फ सवाल तक ही सीमित रखें और जो आपस की दोस्ताना बातें हैं, वे हाउस से बाहर करें। (व्यवधान व भाोर)

चौधरी राम लाल वधवा: यह कोई दोस्ताना बात थोड़े ही है। * *

श्री अधयक्ष: जो इररैलेवेन्ट रिमाक्स आये है, वे एकसपंज कर दिये जायें I must request the Hon. Minister to confine his reply to the question asked by the Hon. Member and the Government should see that only relevant reply is given.

श्री जगन नाथ: अधयक्ष महोदय, इन डिपुओं में घाटा हो रहा है, वह इस प्रकार से हैं।

| | 1978-79 | 1979-80 | 1980-81 |
|--------|--------------|--------------|---------------|
| जीन्द | (-)30.57 लाख | (-)11.52 लाख | (-)21.89 लाख |
| कैथल | (-)15.29 लाख | 2.77 लाख | (-)17.44 लाख |
| भिवानी | (-)13.97 लाख | (-) 0.83 लाख | (-) 24.11 लाख |
| सिरसा | 2.57 लाख | 7.17 लाख | (-) 9.26 लाख |

घाटे का मेन कारण यह है कि इस एक साल के अन्दर 5 बार पेट्रोल, डीजल और स्पेयर पार्ट्स तथा दूसरी चीजों की कीमतें बढ़ी हैं। पिछली बार हालात को देखते हुए, 25% किराया बढ़ाया गया था किन्ती अपाजी इन के मैम्बर ने न तो इस सै इन में और न ही पिछले सै इन में इस किराये को बढ़ाने के बारे में एक भाब्द कहा।

Dr. Mangal Sein: Speaker, sir, he must prove it. It is wrong.

श्री जगन नाथ: उसके बाद अप्रैल के अन्दर फिर 37 पैसे पर लिटर डीजल और पेट्रोल के भाव और बढ़ें जिसके कारण एक दिन में 61 हजार रुपये का लौस हुआ है। फिर भी कुल मिलाकर हमारा महकमा प्राफिट में है।

श्री रिजक राम: स्पीकर साहब, यह देखा गया है कि जहां पर रोडवेज का रेलवेज के साथ कम्पीटी इन है, वे डिपो आमतौर पर घाटे में ही रहते हैं। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जहां पर हरियाणा रोडवेज का रेलवेज से कम्पीटी इन है, वहां पर 25 परसेन्ट किराया बढ़ाने से उन डिपोज का घाटा और बढ़ा है या नहीं?

श्री जगन नाथ: स्पीकर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। घाटा डीजल, पेट्रोल और स्पेयर पार्ट्स की कीमतों बढ़ने तथा लिकेज आफ रैवेन्यू के कारण हो रहा है। हर चीज की कीमत दस-पन्द्रह दिन या महीने के अन्दर बढ़ती जाती है।

श्री अध्यक्ष: चौधरी रिजक राम का क्वै चन चह था कि रेलवे फेयर में और बस फेयर में फर्क होन के कारण तो घाटा नहीं बढ़ा है?

श्री जगन नाथ: स्पीकर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले जितनी सवारियां आती थी उतनी ही अब आ रही है।

श्री बलदेव तायल: स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने बताया है कि डीजल, स्पेयर पार्ट्स तथा अन्य कुछ चीजों की कीमतें बढ़ने के कारण घाटा हो रहा है। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इन चीजों की कीमत तो सारे ही डिपुओं में बढ़ी है फिर केवल इन पांचों डिपुओं में ही लौस का क्या कारण है?

श्री जगन नाथ: स्पीकर साहब, मैंने पहले भी बताया है कि ये डिपो कौरनर में पड़ते हैं। कुछ डिपो ऐसे हैं जिनके पास 250 किलोमीटर से ज्यादा के रुट्स हैं। जैसे चण्डीगढ़ डिपो के पास आने जाने के 38 और 46 लम्बे रुट्स हैं, गुड़गांव डिपो के पास 23,37 बड़े रुट्स हैं और अम्बाला डिपो के पास 12,36 बड़े रुट्स हैं। कैथल और जींद में 5,5 बड़े रुट्स हैं और भिवानी में 13,14 बड़े रुट्स हैं सोनीपत में एक भी बड़ा रुट नहीं है।

श्री मूल चन्द जैन: स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने लौस का कारण लिक्विड बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने कोई प्लानिंग सुकैड या कोई और ऐजेन्सी बनाई है ताकि लिक्विड आफ रैवेन्यू और डीजल तथा स्पेयर पार्ट्स की चोरी को रोका जा सके?

श्री जगन नाथ: स्पीकर साहब, कुछ गड़बड़ तो हो ही जाती है वरना वहां पर जी०एम० होता है और प्लानिंग सुकैड भी होती है। चोरी रोकने के लिए विजिलेंस की भी मदद ली जाती

है। स्पीकर साहब, चोरी रोकने के लिए सरकार पमरी को रोक कर रही है।

श्री देवी दास: मन्त्री महोदय ने अभी बताया कि सोनीपत डिपो में घाटा इसलिए है कि वहां से कोई भी बस लम्बे रूट पर बाहर नहीं जाती है। इस घाटे को कम करने के लिए सरकार क्या पग उठा रही है?

श्री जगन नाथ: स्पीकर साहब, सोनीपत जी०टी० रोड पर पडता है और वहां से अम्बाला, युमनानगर और करनाल डिपुओं की सभी बसे गुजरती है। इसलिए विशेष आवयता नहीं है कि वहां से लम्बे रूटस पर बसें चलाई जाएं। फिर भी यदि आवयकता हुई तो को रोकेंगे कि बड़े रूटस की बसे चलाई जाएं।

श्री सुरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने बताया है कि इन पांच डिपुओं से लम्बे रूटस की पर कोई गाडी नहीं जाती है इसलिए इन डिपुओं में घाटा है। स्पीकर साहब, जीन्द, सोनीपत, कैथल, भिवानी और सिरसा जब से डिपो बने हैं तभी से इनमें छोटे रूटस हैं। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इन डिपुओं में भुरु से ही घाटा है या फायदे में भी रहे है?

श्री जगन नाथ: अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही बताया है कि ये डिपो 1978-79 से घाटे में चल रहे हैं और इसका कारण यह है कि इनके मास कार्ड बड़े रूटस नहीं हैं। स्पीकर साहब, जैसे

रोहतक से एक बस हरिद्वार को जाती है अगर उसको भिवानी से कर दिया जाए, तो रोहतक का डिपो घाटे में हो जाएगा। इस तरह बात वहीं की वहीं रहती है।

Opening of Polytechnic Schools

***1944 Sh. Hira Nand Arya:** Will the Minister of State for Education be pleased to state whether there is any proposal to open three polytechnic school at Loharu ; if so, the progress made so far in this connection?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्रीमति भान्ति देवी): जी हां। प्रश्न नहीं उठता।

श्री हीरा नन्द आर्य: क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेगी कि यह बात ठीक है कि जिस वक्त चौधरी देवी लाल की सरकार थी उस लोहारु में पॉलिटेक्निक स्कूल मन्जूर हुआ था और जब चौधरी भजन लाल की सरकार आई तो उसके लिए इनकार कर दिया गया?

श्रीमती भान्ति देवी: स्पीकर साहब, 29-11-1978 को राज्य सरकार द्वारा इस बारे में भारत सरकार को एक पत्र भेजा गया था जो 17-11-1980 को भारत सरकार से रद्द हो गया।

डा० मंगल सैन: क्या मन्त्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि जुलाई, 1979 से लेकर अब तक हरियाणा में कोई पौलिटैक्निक स्कूल खोला गया है?

श्रीमती भान्ति देवी: स्पीकर साहब, कही नहीं खोला गया है।

चौधरी संत कंवर: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदया से यह जानना चाहता हूँ कि चौधरी भजन लाल जी की सरकार आने के बाद, हरियाणा में पौलिटैक्निक स्कूल खोलने के लिये भारत सरकार से कोई पत्र-व्यवहार किया गया है या नहीं, क्योंकि ये स्कूल भारत सरकार की मन्जूरी के साथ खोले जा सकते हैं।

श्रीमती भान्ति देवी: स्पीकर साहब, मैं आनरेबल मैम्बर को दूँ कि इस बारे में कोई पत्र-व्यवहार नहीं हुआ।

चौधरी हर स्वरूप बूरा: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदया से यह पुछना चाहता हूँ कि जैसा करनाल के अन्दर चौ० भजन लाल जी ने यह कहा था कि हम एजुके ान जो जौब औरिएनटिड बनाना चाहते हैं। इस बात को देखते हुए क्या सैन्ट्रल गवर्नमेंट से पत्र-व्यवहार या जाएगा ताकि कोई पौलिटैक्निक स्कूल खोला जा सके?

श्रीमती भान्ति देवी: स्पीकर साहब, अखिल भारतीय परिशद इस बात का डिस्ीजन करती है। वैसे हम आई०टी०आईज०

से ज्यादा से ज्यादा खोलने का प्रयास करेंगे। वैसे एक पौलिटैक्निक स्कूल खोलने के लिए कम से कम 2 करोड़ की राशि खर्च होती है जो कि आजकल से समय में सम्भव नहीं है।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, अभी डाक्टर मंगल सैन जी के सावल के जवाब में बहिन जी ने फरमाया है कि जुलाई, 1979 से लेकर अब तक कोई नया पौलिटैक्निक स्कूल हरियाणा प्रदेश में नहीं खोला गया है। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस बात की कमी महसूस नहीं करती कि हरियाणा प्रदेश में और पौलिटैक्निक स्कूल खोलने की आवश्यकता है?

श्रीमती भान्ति देवी: अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का जवाब पहले दिया जा चुका है।

श्री अध्यक्ष: मन्त्री महोदय, ने कह दिया है कि एक पौलिटैक्निक स्कूल खोलने पर 2 करोड़ रुपये लगते हैं।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, इस साल की जरूरत हमने पहले महसूस की थी। जैसाकि अभी यहाँ पर बताया गया है कि पौलिटैक्निक स्कूल खोलने के लिए भारत सरकार की स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है। भारत सरकार से हमारा केस रिजेक्ट होकर आ गया है। उसके बाद हमने यह फैसला किया कि हरियाणा में आई0टी0आईज0 और ज्यादा खाली जाएं क्योंकि इनमें ट्रेनिंग देने से कुछ हद तक बेरोजगारी को दूर किया जा सकेगा। पिछले साल हमने तीन नये आई0टी0आईज0

खाले थे और अगले साज हम दो-तीन और खोलने का विचार रखते हैं।

चौधरी वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, अभी मन्त्री महोदया ने यह बताया कि एक पौलिटैक्निक स्कूल खोलने पर 2 करोड़ रुपया लगता है। रोहतक के अन्दर एक छोटू राम पौलिटैक्निक स्कूल है, उसको टेक ओवर करने का मामला सरकार के विचाराधीन था। तो मैं मन्त्री महोदया से यह जानना चाहता हूँ कि दस बारे में सरकार ने अब तक क्या किया है?

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, मैं आनरेबल मैम्बर को यह बताना चाहता हूँ कि प्राईवेट संस्थानों को टेक ओवर करने के लिये सरकार के कुछ नार्मज होते हैं। पहले उस संस्था की मैनतमेंट बाडी की तरफ से सरकार के पास प्रस्ताव आता है। जब तक वह प्रस्ताव सरकार के पास नहीं आता, तब तक सरकार के पास एक प्रस्ताव आता है। जब तक वह प्रस्ताव सरकार के पास नहीं आता, तब तक सरकार उस संस्था को टेक ओवर नहीं कर सकती। अगर आनरेबल मैम्बर इस तरह का प्रस्ताव वहां से हमें भिजवा दें तो उस पर हम सहानुभूति से विचार कर सकते हैं।

श्रीमती डा० कमला वर्मा: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदया से यह पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई प्राईवेट संस्था, जैसा कि यमुना नगर में एम०एल०एन० कालिज खुला हुआ है, इस तरह का पौलिटैक्निक स्कूल खोलना चाहे तो

सरकार ऐसी संस्थाओं को कोई फायनें ियल एड देने का विचार रखती है?

श्रीमती भान्ति देवी: स्पीकर साहब, मेरी बहिन इसके लिये अलग से नोटिस दें तो बताया जा सकता है ।

श्रीमती डा० कमला वर्मा: स्पीकर साहब, मेरे प्र न का जवाब नहीं आया मैंने यह पूछा था कि अगर कोई प्राईवेट संस्था पौलिटैकिनक स्कूल खोलना चाहे या खोला है तो उसके लिए सरकार की ग्रान्ट वगैरह देने की क्या निति है?

श्री अध्यक्ष: इस का जवाब मन्त्री महादया ने दे दिया है कि आनरेबल मैम्बर साहिबा इसके लिये अलग से नोटिस दे तो बता दिया जाएगा ।

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, अगर किसी संस्था की हालत खस्ता है और वह संस्था सरकार को लिखती है कि हमारी हालत खस्ता है, हमें ग्रान्ट दी जाए तो सरकार द्वारा विचार किया जा सकता है ।

श्री मूल चन्द मंगला: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदया से यह पूछना चाहता हूं जैसाकि उन्होंने अभी बताया है कि एक पौलिटैकिनस स्कूल खोलने पर दो करोड़ रुपये का खर्चा आता है । अगर एम०एल०एज० और मिनिस्ट्रों पर सरकार इतना खर्चा कर सकती है तो क्या गरीब लोगों को रोजगार देने के लिए 2 करोड़ की लागत से एक टैक्नीकल कालेज या स्कूल

नही खोला जा सकता जिससे कि लाखों लोगों को रोजगार मिल सकेगा? क्या सरकार इस पर दोबारा विचार करेगी?

(इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया)

चौधरी हुकम सिंह: स्पीकर साहब, माननीय मन्त्री महोदया ने अपने जवाब में कहा है कि लौहारु में भारत सरकार ने टेकनीकल स्कूल खोलने की इजाजत नहीं दी है जबकि दूसरे प्रान्तों में खोलने की इजाजत दे दी है। क्या भारत सरकार के इस बारे में कोई नार्मज या भार्ते हैं, जिनके आधार पर इजाजत दी जाती है? मैं पूछना चाहता हूँ कि इनका केस किन रीजन्ज पर रिजैक्ट हुआ है।

(इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष: चौधरी हुकम सिंह जी का प्रश्न है कि भारत सरकार ने हरियाणा का केस किन रीजन्ज पर रिजैक्ट किया है और दूसरे प्रान्तों में पौलिटेक्निकस खोलने की इजाजत किन भार्तों पर दी गयी है, इस बारे में अगर सरकार जवाब देना चाहे तो दे सकती है।

श्रीमति भान्ति देवी: स्पीकर साहब, इस प्रकार की जानकारी अगर हमारे आनरेबल विधायक जानना चाहते हैं जो

इसके लिये हमें अलग से नोटिस दें, तब दूसरे प्रान्तों का बता देंगे।

सिचाई तथा बिजली मन्त्री (सरदार तारा सिंह): स्पीकर साहब, अगर आप की इजाजत हो जो मैं इसका जवाब दे दूँ क्योंकि यह विभाग पहले मेरे पास हुआ करता था। हम बहुत इच्छुक थे कि हरियाणा में और पोलिटैक्निक सेंटर खोले जाएं लेकिन यह भारत सरकार का पालिसी मैटर है कि आबादी के लिहाज से पहले ही पोलिटैक्निक स्कूल ज्यादा हैं। इसी बिलाह पर हमारी जो एप्लीकेशन थी, वह भारत सरकार द्वारा खारिज कर दी गयी।

श्री मूल चन्द जैन: स्पीकर साहब, मन्त्री महोदया ने बताया कि भारत सरकार द्वारा लोहारु मे पोलिटैक्निक स्कूल खोलने की बात रिजैक्ट कर दी गयी है। जैसाकि अभी मुख्यमन्त्री महोदय ने बताया है कि हम ज्यादा से ज्यादा आई०टी०आई० हरियाणा में खोलने की कोशिश करेंगे क्या सरकार इस पर सहानुभूति से विचार करेगी कि वहां पर एक आई०टी०आई० खोला जाए?

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदया से यह पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई प्राईवेट संस्था अपनी तरफ से पोलिटैक्निक स्कूल खोलना चाहे

जो उसको सरकार कोई ग्रांट देगी और क्या इस बारे में भी भारत सरकार से पूछना पड़ेगा।

श्रीमती भान्ति देवी: इस काम के लिए भारत सरकार की मंजूरी लेना तो जरूरी है ही। जहां तक ग्रांट का संबंध है अगर प्राइवेट संस्थाएँ सरकार का लिखेंगी, तो विचार किया जा सकता है।

श्री भले राम: स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार के नोटिस में यह बात है कि प्राइवेट इंस्टीच्यू ऑफ लड़कों से दाखिले के नाम पर ऐड लेते हैं? क्या सरकार इस बात की तरफ ध्यान देगी ताकि आगे से ऐसा न हाने पायें?

श्रीमती भान्ति देवी: स्पीकर साहब, पहले ऐसी कुछ रिपोर्टें सरकार के नोटिस में आई थीं और पिछले साल हमने इस बात की इंक्वायरी करवायी थी। आपको मैं आश्वासन दिनाती हूँ कि अब की पर एक पैसे की भी ऐसी कोई बात नहीं हो रही है और सारा काम-काज सुचारु रूप से चल रहा है।

10.00 बजे

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता कि लोहारु के पोलिटैकिनक के संबंध में भारत से आखिरी पत्र व्यवहार कब हुआ और उसको रिजैक्ट करने के क्या कारण थे? क्या सरकार उस पर पुनर्विचार करने के लिए भारत

सरकार को लिखेगी और अगर फिर भी न खुल सका तो वहां पर आई0टी0आई0 खोलेंगे।

श्री अध्यक्ष: इस सवाल का जवाब तो पहले ही आ चुका है।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, अगर वहां पर आई0टी0आई0 खोलने की जरूरत हुई तो विचार कर लेंगे।

सरदार तारा सिंह: स्पीकर साहब, जैसे मैंने पहले बताया कि हमने इस बारे में बार-बार स्ट्रेस किया। मैं खुद दो-तीन जगहों पर खोलने के लिये इन्ट्रेस्टिड था। भारत सरकार ने कहा कि यह जौब औरिएंटेड स्कीम है और सारे हिन्दुस्तान में आबादी के हिसाब से ये खोलें जाते हैं। दूसरी बात यह है कि इसके लिये सैन्ट्रल गवर्नमैन्ट ग्रांट भी देती हैं।

Mr. Speaker: Is it 100 % finaced by the Central government or 50%?

Sardar Tara Singh: These are almost finaced by the Central Government.

श्री अध्यक्ष: मैं अपनी तरफ से एक अपील करना चाहता हूं। हाउस मे दोनों साइड से सीनीयर मैम्बर्ज ज्यादा टाईम ले रहे हैं। कृपा करके थोड़ा बैक बैन्चर्ज भी स्प्लीमैटरी पूछने का टाईम दें। दोनों साइड से अगर सीनियर मैम्बर्ज खड़े हो जाते हैं ता

मुझे बड़ा आकवर्ड लगता है कि मैं उनको काल अपौन करु। इसलिये थोड़ा से टाइम बैंक बैन्चर्ज को भी देना चाहिए।

**Construction of Wwater tanks for drinking water in
village Makroki Kanlan**

***2057. Chaudhari Hari Chand Hooda:** Will the Minister⁵ for Food and Supplies be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construction water tanks for drinking purpose in village Makroli Kalan in district Rohtak; if so, the time by which these are likely to be completed?

Food and Supplies Minister (Sh. Lachhman Singh): Yes, In addition to village makroli Kalan in District Rohtak, we have sanctioned the scheme for another 4 village, namely, Ladhot, Barhamanwas, Bastpur and Dharmar.

मकरौली कलां की स्कीम अभी मन्जूर हुई है और एक लाख रुपया इसके लिये दे दिया गया है। पंचायत ज्यों ही जमीन दे देगी, काम भुरु कर दिया जाएगा। अब हुड्डा साहब पर मुनस्सर करता है कि वे कितनी जल्दी जमीन दिलवाते है।

चौधरी हरि चन्द हुड्डा: स्पीकर साहब, जो जवाब हमारे सामने आया है उसमें लिखा है कि “..... No definite time can be given, asit depends upon the time to be taken for according administrative approval and allocation of funds by State

Sanitary board.” अध्यक्ष महोदय, क्या सरदार लछमन सिंह जी बताएंगे * * * * *

श्री अध्यक्ष: जो बात हुड्डा साहब ने मिनिस्टर साहब के बारे में कही है, वह रिकार्ड न की जाए। मैं मैम्बर साहेबान से रिकवैस्ट करुंगा कि मेन क्वै चन से संबंधित ही सम्लीमेंटरी पूछी जाए। The Hon Minister has given the latest information that is available with him.

चौधरी गंगा राम: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि चौधरी देवी लाल जी के टाईम में जिस गांव में कोई वाटर सप्लाई स्कीम बनाई जाती थी तो उस गांव से बैनिफि टायरी भोयर नहीं लिया जाता था। लेकिन अब जिस भी गांव में कोई स्कीम बनाई जाती है तो यह सरकार गांव वालों से बैनिफि टायरी भोयर लेती है जोकि 5-7 लाख रु0 होता है, जिसे गांव वाले दे नहीं सकते। तो क्या सरकार का कोई विचार है कि पहले की तरह कोई भोयर न लिया जाए?

श्री लछमन सिंह: चौधरी देवी लाल के जमाने में तो थोड़ी सख्ती थी कि भोयर जरूर लिया जाए लेकिन अब जो किसी से भी नहीं लेते। मैं हुड्डा साहब को बताना चाहता हूं कि हमने चार गांव और भी ऐड कर दिये हैं जिनमें ये इन्ट्रैस्टिड नहीं थे।

श्री फतेह चन्द विज: स्पीकर साहब, जो जवाब हमारी टेबल पर आया है इसमें लिखा है कि कोई डैफिनिट टाइम नहीं

बताया जा सकता लेकिन दूसरी तरफ मन्त्री जी कह रहे हैं कि जब पंचायत वाले जमीन दे देंगे जो उस पर काम भुरु करवा दिया जाएगा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि दोनों जवाबों में से कौन सा जवाब सही है?

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, यह जवाब पहले का आया हुआ है। इसी महीने की 10 तारीख को सैनेटरी बोर्ड की मीटिंग हुई थी उसमें यह स्कीम सैंकान हो चुकी है। फंडज भी दिये जाते हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, जहां पर पहले से वाटर सप्लाई स्कीम है, वहां पर पांच गैलन पानी प्रति दिन के हिसाब से मिलता है। उसको दस गैलन करने के लिए पिछले तीन चार साल से सरकार जवाब दे रही है कि यह विचाराधीन है। जैसे बापोड़ा की स्कीम है, सरकार इसको कब तक दस गैलन कर देगी?

श्री अध्यक्ष: भिवानी तो फार्वर्ड इलाका है, वहां पर तो पांच गैलन ही काफी है।

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, अब जो स्कीम बनाते हैं वह दस गैलन की ही बनाते हैं। जहां पर पहले पांच गैलन की स्कीम चल रही है, उसको दस गैलन की करना जो फंडज पर डिपेंड करता है। दूसरी बात यह है कि जहां बहुत बुरी हालत हो उन गांवों का हम पानी देने के लिये प्रायोरिटी देते हैं। जैसे हुड्डा साहब के हल्के में चार गांव है उनको हमने ले लिया है। इसी

तरह स्टेट में दूसरे गांव हैं जहां सलाइन वाटर है, हम उनको भी ले रहे हैं।

चौधरी जय नारायण: स्पीकर साहब, 1978-79 में रोहतक जिले के खदकु कलंगा और लालडी गांवों में वाटर स्पलाई की स्कीमें मन्जूर हुई थी लेकिन आज तक उन स्कीमों पर काम चालू नहीं हुआ, क्या बतायेगी कि इन स्कीमों पर कब तक काम चालू हो जायेगा?

(इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया)

चौधरी उदय सिंह दलाल: स्पीकर साहब, इतफाक से चौधरी भजन लाल जी ने मेरे हल्के में वाटर स्पलाई स्कीमें चालू करने के लिए पत्थर रख दिये थे लेकिन इन पर अभी तक काम भुरु नहीं हुआ है। बाई चांस एक ऐसा आदमी बीच में आ गया था जिसने कागज नहीं पढे और काम चालू नहीं किया। उसके आने से डिपार्टमेंट का सिस्टम बिगड़ गया जिसकी वजह से काम चालू नहीं किया। और भी कई किस्म की कमियां डिपार्टमेंट में आ गई हैं। क्या मन्त्री महोदय जी डिपार्टमेंट के सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करेंगे और इन स्कीमों पर चालू करेंगे?

श्री लछमन सिंह: डिपार्टमेंट पहले भी ठीक था और अब भी ठीक है, इसके सिस्टम में कोई खराबी नहीं आई है।

आबकारी तथा कराधान मन्त्री (चौधरी मेहर सिंह राठी): स्पीकर साहब, यही (दलाल साहब) हैं जिन्होंने काम नहीं करने

दिया। (व्यवधान) यही हैं जिन्होंने लोगों को लास पहुंचाया है, सारी जिम्मेवारी इन्हीं पर हैं।(व्यवधान एवं भाोर)

चौधरी संत कंवर: स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय मकरौली कलां गांव मे और बेरी कांस्टीच्यूएंसी के आस पासके गांवों में दोरे पर गये थे और इनके साथ मैं भी था। हमने देखा कि दूर दूर से ओरतें सिर पर घड़े रख कर पानी ला रही थी। यह सब देखने के बाद इन्होंने आ वासन दिया था कि इन जगहों पर वाटर सप्लाई की स्कीमें जल्दी से जल्दी चालू की जायेगीं। मन्त्री साहब ने यह भी देखा कि इन गावों मे खारा पानी है, पीने के पानी की बहुत दिक्कत है। जहां जहां मन्त्री महोदय गये, क्या वहां वाटर सप्लाई की स्कीमें चालू करने का विचार है क्योकि सदियों से ओरतें सिर पर घड़े रख कर पानी ला रही है, जिससे लोगों को बहुत दिक्कत हैं।

श्री अध्यक्ष: आपने कहा कि सदियों से घड़ें सिर पर रख कर ओरतें पानी ला रही हैं। क्या आप समझते हैं कि 15 दिन के अन्दर मन्त्री साहब समस्या हल कर देंगे? बिल्कुल नही कर सकते।

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, यह बिल्कुल ठीक है कि रोहतक डिस्ट्रिक्ट में पीने के पानी की बडी किल्लत है। जब जनता पार्टी की सरकार थी तो उस डेढ़ साल के अर्से में पानी स्कीमों के बारे में कुछ नही हुआ और न किसी स्कीम का पता

चला। अब हम इस को 1 1 में लगे हैं कि जहां भी पानी की किल्लत हैं, उसको जल्दी से जल्दी दूर किया जाएगा। यह महकमा पहले श्री वीरेन्द्र सिंह के पास था, इन्होंने स्कीमों का किसी को पता नहीं लगने दिया।

चौधरी संत कंवर: स्पीकर साहब, रोहतक जिले का सत्याना 1 तो राठी साहब ने किया है।

चौधरी मेहर सिंह राठी: ना 1 तो तुमने किया हैं, मैंने तो डेढ साल में 15 गांवों में वाटर सप्लाई की स्कीमें भुरु की है।

चौधरी जय नारायण: ये स्कीमें तो रोहतक जिले के बहादुरगढ़ एरिये के अन्दर भुरु हुई हैं, इनके इलावा किसी दूसरी जगह भुरु नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज आर्डर।

श्री गुलजार सिंह: क्या मन्त्री जी के नोटिस में यह बात है कि जा स्कीमें पहले कम्पलीट हो गई हैं, उनमें पानी की सप्लाई बहुत कमती है, जहां 5 गैलन पाली की जरूरत है वहां 1 गैलन पानी सप्लाई कम है, क्या सरकार उनकी केपैस्टी बढ़ाने के लिए विचार करेगी? कई कस्बे ऐसे हैं जिनकी आबादी 15 से ज्यादा है लेकिन पानी एक गैलन सप्लाई होता है। ऐसी हालात में क्या सरकार पानी ही केपैस्टी बढ़ायेगी?

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि वाटर सप्लाई का काम अवेलेबिलिटी आफ फण्डज पर डिपेंड करता है। हिसार, रोहतक और अम्बाला कई ऐसी जगहें हैं जहां पानी की किल्लत है। वाटर सप्लाई स्कीमज का आगमेंटे इन तो हम कर दें लेकिन हमारे पास पर्याप्त फण्डज नहीं हैं। पिछले साल इन स्कीमों के लिए 225 करोड़ रुपया रखा था लेकिन इस बजट में 300 करोड़ रुपये हो जाएगा और जब हमारे पास पैसा आ जायेगा, तब काम कर लेंगे।

Mr. Speaker: I have to make one observation about the public health schemes. पिछले दिनों मैंने कुछ देहात और भाहरो का टूर किया था। जहां जहां वाटर सप्लाई स्कीमज हैं, मैंने किसी जगह पर भी सैटिस्फैक्टरी सप्लाई नहीं देखी। टूटियां खराब हैं और पानी की वेस्टेज होती है which is a criminal waste, तो मैं मन्त्री महोदय से कहूंगा कि टूटियां अच्छी क्वालिटी की लगाएं ताकि पानी की वेस्टेज न हो सके।

श्री लछमन सिंह: अगर हम हाथ से प्रैस करने की टूटियां लगायें जो लोग कहते हैं कि दबाते समय हाथ थक जाते हैं और अगर दूसरी किस्म की टूटियां लगा दी जायें तो गांव के लोग तोड़ देते हैं। स्पीकर साहब, आप देखें, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इन टूटियां की निगरानी कैसे कर सकता है? आप इन भाईयों को भी समझायें कि वे टूटियों को न तोड़ा करें।

श्री अध्यक्ष: मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि चौधरी लाल सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं।

श्रम उप मन्त्री(चौधरी लाल सिंह): स्पीकर साहब, आपकी मेहरबानी, आपने मुझे टाईम दिया। पानी का ऐसा मसला है जिसके बगैर इन्सान जिन्दा नहीं रह सकता। जो लोग हरियाणा में बसते हैं, उनको सरकार पानी देना चाहती है और हर एक गांव का सर्वे किया जा रहा है। स्पीकर साहब, हरियाणा में दो किस्म के गांव हैं— प्रोब्लम विलेजिज और नानप्रोब्लम विलेजिज हैं, जो प्रोब्लम विलेजिज है, उनको सरकार जल्दी पानी देने की कोशिश कर रही है। अब रहा टूटियों का सवाल। स्पीकर साहब, टूटियां डिपार्टमेंट लगाता है लेकिन गांव के कुछ लोग या तो टूटियां तोड़ देते हैं या उतार लेते हैं। इस प्रोब्लम को दूर करने के लिए हमने स्कीम बनाई है कि गांवों में जो डिपार्टमेंट के कर्मचारी टूटियां लगाने के लिए जाते हैं, वे टूटि लगाकर, पानी चालू करवा कर गांव के सरपंच या किसी जिम्मेदार आदमी के दस्तखत करवा लेते हैं ताकि वह टूटि की देखभाल कर सके। हमने गांव वालों को हिदायत जारी कर दी है कि अगर कोई टूटि खराब हो जाए तो वे उस खराब टूटि को स्टोर में जमा करवा दें और नई लगवा लें। टूटियों के मसले का पूरा इन्तजाम हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: जब चौधरी लाल सिंह जी की तरफ से इतनी डिटेल में जवाब आ गया है तो और सप्लीमेंटरीज की कोई गुंजाई नहीं है।

श्रीमति सुशमा स्वराज: अध्यक्ष महोदय, मैं सप्लीमेंटरी नहीं पूछना चाहती मैं तो एक और बात कहना चाहती हूँ। चौधरी लाल सिंह जी कल से प्रोब्लम और नानप्रोब्लम की बात कर रहे हैं। मैं मुख्य मन्त्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि लाल सिंह जी स्वयं प्रोब्लम के आते हैं या नौनप्रोब्लम में आते हैं।

चौधरी लाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं सुशमा जी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता था क्योंकि मैं इनकी इज्जत करता हूँ लेकिन अब चूंकि इन्होंने स्वयं बात भुरु की है इसलिए मैं हाअस को बताना चाहता हूँ कि जिस कांस्टीच्यूएन्सी से ये चुन कर यहां आई है जब भी मैं वहां जाता हूँ, ये वहां कभी नहीं मिलती।

Metalled Roads in Barwala And Adampur Constituencies.

***2068. Shri Jai Narain Verma:** Will the Minister for Public Works be pleased to state-

(a) the metalled roads in kilometers constructed in Barwala and adampur constituencies of district Hisar during the period from August, 1979 to date ; and

(b) whether a link road from village Banbhori to Kapro in Barwala area has been sanctioned; if so, the time by

which the construction work on the said road is likely to be started and completed?

लोक निर्माण मन्त्री (कंवर राम पाल सिंह)

| | | |
|-----|-------------|---------------------------------|
| (क) | (i) बरवाला | 9.5 किलोमीटर (फरवरी, 1981 तक) |
| | (ii) आदमपुर | 66.47 किलोमीटर (फरवरी, 1981 तक) |

Shri Verender Singh: Sir, the total money of the State has been spent in adampur Constituency.

कंवर राम पाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये सवाल का जवाब सुनने में इंट्रैस्टिड नहीं हैं। इनको चाहिए कि ये सवाल का पूरा जवाब मुझे देने दें उसके बाद जिस प्वायंट को ये क्लेरिफाई करवाना चाहते हो उसे सप्लीमेंटरीज के द्वारा क्लेरिफाई कर लें।

श्री अध्यक्ष: आप पूरा जवाब सुन लीजिए।

कंवर राम पाल सिंह: स्पीकर साहब, पार्ट (बी) का जवाब इस प्रकार है – हाँ इस स्टेज पर यह बताना कठिन है कि किस समय तक यह सड़क मुकम्मल हो जाएगी।

श्री जय नारायण वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह था कि अगस्त, 1979 से लेकर अब तक बरवाला हल्के में कितनी

सड़के बनी और आदमपुर हल्के में कितनी सड़के बनी। इन्होंने जवाब दिया है कि—

श्री अध्यक्ष : जवाब सबने सुन लिया है। आप प्र न पूछें।

श्री जय नारायण वर्मा: अध्यक्ष महोदय, इन्हाने बताया है कि बरवाला हल्के में 9.5 किलामीटर सड़के बनी है लेकिन मुझे संदेह है कि ये आकड़े गलत है। क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि वहां कौन सी सड़के बनाई गई हैं? इसके अलावा अध्यक्ष महादय, पार्ट (बी) के जवाब मे इन्होंने बताया कि बनभोरी से कापडू सड़क मंजूर तो हो चुकी है परन्तु इसको बनाने का टाईम बताना कठिन है। क्या मन्त्री महोदय बताएगे कि यह सड़क कब मंजूर हुई थी और उसकी मंजूरी होने के बाद से लेकर आज तक यह कितनी बनाई गई है?

श्री अध्यक्ष: ये साढे नौ किलामीटर सड़को का ब्योरा मांगते हैं।

कंवर राम पाल सिंह: स्पीकर साहब, डिटेल जो इस वक्त मेरे पास नहीं है। अगर मैम्बर साहब चाहेंगे तो बाद में दे दी जाएगी। इन्होंने तो सवाल मे यही पूछा था कि बरवाला और आदमपुर हल्कों में कितनी लैथ की सड़के बनी है, वह मैने बता दिया हैं।

श्री अध्यक्ष: इसका ब्यौरा आप मैम्बर साहब को कृप्या दस दिन के अन्दर अन्दर भिजवा दें।

श्री जय नारायण वर्मा: अध्यक्ष महोदय, ये सड़के बनी ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष: मैंने उन्हे कह दिया है कि ये साढे नौ किलोमीटर सड़के कहां बनी हैं, इसकी डिटेल् डिपार्टमेंट दस दिन के अन्दर आपको प्रोवाइड कर दें।

श्री जय नारायण वर्मा: धन्यवाद। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मेरे प्र न के पार्ट (बी) का जवाब भी इन्होने नहीं दिया है।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, कंवर राम पाल जी जब जवाब पढ ही रहे थे तो कुछ माननीय सदस्यों ने आपत्ति उठाई कि आदमपुर मे तो 66ण47 किलोमीटर सड़के बन गई लेकिन बरवाला में कमवल 9.5 किलामीटर सड़के बनी हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने फैसला किया है कि 31 मार्च, 1981 तक हरियाणा प्रान्त के हर गांव को पक्की सड़क से मिला दिया जाएगा। जिस हल्के में पहले कम सड़के बनी थीं उसमें कुदरती तौर पर ज्यादा सड़के बननी थी। बरवाला हल्के के तकरीबन सारे गांव सड़कों से मिलें हुए हैं इसलिए वहां कम सड़के बनीं और आदमपुर में ज्यादा सड़के बनीं क्योंकि वहां पहले गांव छुटें हुए थे। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, कालका हल्के में एक साल में 60

किलोमीटर सड़के बनी हैं। ऐसा नहीं है कि आदमपुर में जानबुझ कर सड़के ज्यादा बनाई गई हों और किसी दूसरे हल्के के साथ भेदभाव की नीति बरती गई हों। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह कही कि ये सड़के कोन से गांव में बनी हैं और बाकी की सड़कें कब तक बन जाएगीं। इसके बारे में अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले कहा कि आज से पूरे बारह दिन के बाद दे 1 में हरियाणा प्रान्त पहला प्रान्त होगा जिसमें कोई गांव ऐसा नहीं होगा जो पक्की सड़क से नहीं मिला हुआ नहीं होगा। (ट्रैजरी बेंचिंग से प्र संसा) इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, इनकों मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि श्री भागी राम जी लोक दल के एम0एल0ए0 हैं और इनके हल्के मे 59.97 किलोमीटर सड़कें बनी है।

कामरेड भांकर लाल : स्पीकर साहब, रसूलपुर खेड़ी सड़क को मन्जूर हुए जकरीबन बारह महीने हो गए हैं। क्या मंत्री जी बताएंगे कि उस पर आज तक काम क्यों भारू नहीं हुआ?

श्री बलदेव तायल: अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्य मंत्री जी ने बताया कि 31 मार्च, 1981 तक क्योंकि हर गांव को सड़क से जोड़ना जरूरी था इसलिए आदमपुर के हल्के मे 66.47 किलोमीटर सड़के बनी और दूसरी जगह कम सड़कें बनी। लेकिन क्या वे बताएंगे कि इनमें डबल लिंक रोड़ज कितनी हैं और सिंगल लिंक रोड़ज कितनी हैं?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी सदन को बताया कि श्री भागी राम जी के हल्के में भी लगभग 60 किलोमीटर सड़के बनी हैं। अध्यक्ष महोदय, हो सकता है कि कहीं डबल लिंक भी बना हो क्योंकि कई जगह मिसिंग लिंक्स थे। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि बालसमंद से आदमपुर आने के लिए 45 मील का सफर तय करना पड़ता था लेकिन अब नई सड़क बनने से 20 किलोमीटर का फासला ही रह गया है। इसी तरह से बालसमंद और भी ताल की सड़क बनने से 20 किलोमीटर का फासला कम हो गया है जबकि पहले रोड़ से यह फासला ज्यादा था। लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हो सकता है ऐसी डबल लिंक सड़के भी बनी हों वरना ज्यादातर सिंगल लिंक सड़के ही बनी हैं।

Shri Baldev Tayal: Speaker Sahib, my question remains unreplied. My question was, as to how many kilometers of single and double roads have been constructed in Adampur constituency? If the Chief Minister dares to give reply.....

Mr. Speaker: Reply has already been given by the Chief Minister.

Shri Baldev Tayal: Speaker Sir. my submission is that 90 percent of the roads are double link roads.

Mr. Speaker: Details are not with him.

श्री रघुनाथ गोयल: स्पीकर साहब, कैथल हल्के में गियूंग नाम की एक सड़क हैं। वह मजूर है और चौधरी देवी लाल जी के वक्त में अस पर मिट्टी भी पडी थी लेकिन अब वह मिट्टी बह गई है। क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि वह कब तक बनेगी?

Kanwar Ram Pal singh: Separate notice is required.

Mr. Speaker: Hon. Members, Question Hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज़ पर रखे गए तारांकित
प्र नों के लिखित उत्तर

Bus Depot at Jhajjar

***1974. Chaudhri Ude Singh Dalal:** Will the Minister for Transport be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to convert the Jhajjar Sub-Depot of the Haryana Roadways into a full-fledged Bus-Depot?

परिवहन मंत्री (श्री जगन नाथ): जी नहीं।

'Mrit Sanjivni Sura'

***2015. Chaudhari Ram Lal Wadhwa:** Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to state-

(a) the total number of licences issued/renewed by the Excise and Taxation Department for the manufacturing/sale of 'Mrit Sanjivni Sura' after 12th July, 1980 to-date, togetherwith the names and addresses of the licensees, separately;

(b) the total number of licences of 'Mirt Sanjivni Sura' cancelled and refused renewal after 12th July, 1980 togetherwith the names and addresses of applicants/licensees, sep9arately and

(C) whether there is any proposal under consideration of the Governement to impose total ban on the nanufacturing/sale of 'Mirt Sanjivni Sura' in the State; if not, the reason therefor?

आबकारी तथा काराधान मंत्री (चौधरी मेहर सिंह राठी):

(क) "मृत संजीवनी सुरा" बनाने/बेचने का कोई नया लाईसैंस 12 जुलाई, 1981 के बाद नहीं दिया गया है। इस तिथी के बाद नवीनकरण किए गए पुराने लाईसैंसों के बारे में विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

(ख) कोई नहीं।

(ग) जी नहीं। इस वित्त वर्ष के आरम्भ में दो लाईसैंस को "मृत संजीवनी सुरा" बनाने से रोका गया था। उनमें से एक ने कथित आदे 1 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और उस आदे 1 के विरुद्ध "स्टे" प्राप्त कर लिया। यह मामला अभी तक सुप्रीम

कोर्ट में लम्बित हैं। मामले के “सब-जुडिस” होने की स्थिति में सरकार “मृत संजीवनी सुरा” के उत्पादन या बिक्री को बन्द करने के लिए किसी कार्यवाही पर विचार नहीं कर रही हैं।

विवरण

12 जुलाई, 1980 के बाद “मृत संजीवनी सुरा” बनाने/बेचने के लिए नवीनकरण किए गए पुराने लाईसेंसों के बारे में:-

| क्रमांक | लाईसेंस का नाम तथा पता |
|---------|--|
| 1. | मैसर्ज दिल्ली फार्मेसी, करनाल। |
| 2. | मैसर्ज अत्रैय फार्मास्यूटिकल, चमन बाग, करनाल। |
| 3. | मैसर्ज संजीवनी रिसर्च लैबोरेटरीज, गोहाना। |
| 4. | मैसर्ज विसको फार्मा, सब्जी मण्डी रोड, सोनीपत। |
| 5. | मैसर्ज वी. के. आयुर्वेदिक फार्मेसी, माडल कालोनी, यमुनानगर। |
| 6. | मैसर्ज भाक्ति फार्मेसी, गांव व डाक फरल (कुरुक्षेत्र)। |
| 7. | मैसर्ज अ गोकुल आयुर्वेदिक फार्मेसी, निसिंग (करनाल) |

| | |
|-----|---|
| 8. | मैसर्ज डाबर (डा. एस.के.वर्मन) प्राईवेट लि० फरीदाबाद । |
| 9. | वैद्य सत्य प्रका 1 मै० कामधान आयुर्वेदिक फार्मैसी, सोनीपत । |
| 10. | श्री खजान सिंह महता मै० गेवर्ट कैमीकल रिसर्च लैबोरेटरिज़, करनाल |
| 11. | प्रोप्राईटर चावला फार्मैसी, करनाल । |
| 12. | मैसर्ज आन्नद फार्मैसी, गन्नौर । |

Construction of Bridge

***1993. Chaudhri Jagdish Kumar Baniwal:** Will the Minister for Irrigation & Power be pleased to state whether the construction of bridge at Sahuwal-II on the Ban Mandori Minor Near RD 47,000 or 48,000 in district Sirsa has been started ; if not, the reasons therfor?

Irrigation & Power Minsiter (Sardar Tara Singh):
The work has not yet started.

The tenders for this work were called but the constructor did not take up the work. Tenders have been recalled. The work is likely to be completed by 6/81.

Marketing Mandis in the State

***1997. Swami Adityavesh:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state the constituency wise number of Agricultural Produce Marketing Mandis constructed in the State during the years 1979-80 and 1980-81 to date, separately?

कृषि मंत्री (श्री भाम ार सिंह): वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 में जहां पर मण्डियों का निर्माण कार्य चलाया गया है, के सम्बन्ध विवरण निर्वाचन क्षेत्रवार सदन के पटल पर रखे जाते हैं।

विवरण - 1

निर्वाचन मण्डियां जहा वर्ष 1979-80 में निर्माण कार्य चलाया गया है।

नई मण्डियां

| क्रमांक | जिला | निर्वाचन क्षेत्र | मण्डियों की संख्या |
|---------|---------|------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | अम्बाला | कालका | 1 |
| 2 | अम्बाला | नारायणगढ | 1 |
| 3 | अम्बाला | छछरौली | 1 |

| | | | |
|----|----------|---------|----|
| 4 | करनाल | इन्द्री | 1 |
| 5 | करनाल | असन्ध | 1 |
| 6 | करनाल | असन्ध | 1 |
| 7 | सोनीपत | राई | 1 |
| 8 | रोहतक | रोहतक | 1 |
| 9 | रोहतक | कलानौर | 1 |
| 10 | हिसार | बरवाला | 1 |
| 11 | हिसार | नारनोंद | 1 |
| 12 | सिरसा | ऐलनाबाद | 1 |
| 13 | फरीदाबाद | हसनपुर | 1 |
| | | जोड़ | 13 |

वर्तमान मण्डियां

| क्रमांक | जिला | निर्वाचन क्षेत्र | मण्डियों की संख्या |
|---------|---------|------------------|--------------------|
| 1 | अम्बाला | छछरौली | 1 |

| | | | |
|---|-----------|------------|---|
| | | रादौर | 1 |
| 2 | भिवानी | तो ाम | 1 |
| | | चरखी दादरी | 1 |
| 3 | फरीदाबाद | पलवल | 1 |
| | | हसनपुर | 1 |
| | | बल्लबगढ़ | 1 |
| 4 | गुड़गांवा | गुड़गांवा | 1 |
| | | पटौदी | 1 |
| | | सोहना | 1 |
| 5 | हिसार | हिसार | 1 |
| | | आदमपुर | 1 |
| | | टोहाना | 1 |
| | | रतिया | 1 |
| | | टोहाना | 1 |
| 6 | जीन्द | जुलाना | 1 |

| | | | |
|----|-------------|----------|----|
| | | सफीदों | 1 |
| 7 | करनाल | पानीपत | 1 |
| | | समालखा | 1 |
| | | नोलथा | 1 |
| 8 | कुरुक्षेत्र | पेहवा | 1 |
| | | कैथल | 1 |
| | | पुण्डरी | 1 |
| | | गुहला | 1 |
| | | पुण्डरी | 1 |
| 9 | सोनीपत | सोनीपत | 1 |
| | | गन्नोर | 1 |
| 10 | सिरसा | दरबाकलां | 1 |
| | | सिरसा | 1 |
| | | डबवाली | 1 |
| | | जोड़ | 30 |

| | | | |
|--|--|----------|----|
| | | कुल जोड़ | 43 |
|--|--|----------|----|

विवरण – 2

निर्वाचन मण्डियां जहां वर्ष 1980–81 में निर्माण कार्य चलाया गया है

नई मण्डियां

| क्रमांक | जिला | निर्वाचन क्षेत्र | मण्डियों की संख्या |
|---------|-------------|------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | अम्बाला | मुलाना | 1 |
| 2 | करनाल | घरौडां | 1 |
| 3 | कुरुक्षेत्र | भाहबाद | 1 |
| 4 | सिरसा | दरबाकलां | 1 |
| 5 | फरीदाबाद | बल्लभगढ | 1 |
| | | जोड़ | 5 |

वर्तमान मण्डियां

| क्रमांक | जिला | निर्वाचन क्षेत्र | मण्डियों की संख्या |
|---------|-----------|------------------|--------------------|
| 1 | अम्बाला | अम्बाला भाहर | 1 |
| 2 | फरीदाबाद | बल्लभगढ | 1 |
| | | पलवल | 1 |
| | | हसनपुर | 1 |
| 3 | गुड़गांवा | गुड़गांवा | 1 |
| | | पटोदी | 1 |
| | | सोहना | 1 |
| 4 | हिसार | जाखल | 1 |
| | | टोहाना | 1 |
| | | हिसार | 1 |
| | | आदमपुर | 1 |
| | | फतेहाबाद | 1 |
| | | रतिया | 1 |
| 5 | जीन्द | कलायत | 1 |

| | | | |
|---|-------------|----------|----|
| 6 | करनाल | पानीपत | 1 |
| | | नौलथा | 1 |
| | | समालखा | 1 |
| | | जुडंला | 1 |
| 7 | कुरुक्षेत्र | पेहवा | 1 |
| | | कैथल | 1 |
| | | पुन्डरी | 1 |
| | | गुलहा | 1 |
| 8 | सिरसा | डबवाली | 1 |
| | | रोडी | 1 |
| | | सिरसा | 1 |
| 9 | महेन्द्रगढ | रिवाड़ी | 1 |
| | | जोड़ | 26 |
| | | कुल जोड़ | 31 |

Complaints of irregularity in the allotment of plots of HUDA at Faridabad.

***2006. Shri Mool Chand Mangla:** Will the Minister for Finance be pleased to state-

(a) whether any complaints have recently been received by the Government regarding the irregularity committed in the allotment of plots belonging to HUDA AT Faridabad; and

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative the names and addresses of the persons who have given the representation togetherwith action so far taken thereon?

वित्त मन्त्री (चौधरी खुराँद अहमद):

(क) नही ।

(ख) प्र न ही उत्पन्न नही होता ।

iring and Lathi charge in the State

***2086. Smt. Dr. Kamla Verma:** Will the Minister for Home be pleased to state-

(a) the number of places where the police resorted to firing and made lathi charge from January, 1980 to Januar, 1981 in the State; and

(b) the district-wise number of persons who died and were injured by the said firing and lathi charge, separately?

गृह मन्त्री (श्री कन्हैया लाल पोसवाल):

| | | | |
|-----|---------------|----|---------------|
| (क) | (1) गोली चलाई | -- | 12 स्थानों पर |
| | (2) लाठी चलाई | -- | 2 स्थानों पर |

(ख) 12 स्थानों पर जहां पुलिस ने गोली चलाई, 4 व्यक्ति मारे गये तथा 32 घायल हुए। उन 2 स्थानों पर जहां पुलिस ने लाठी चलाई, कोई आदमी नहीं मारा गया और 27 व्यक्ति घायल हुए। जिलानुसार ब्यौरा निचे दिया जाता है:—

| जिला | जितने स्थानों पर गोली चलाई गई | जितने आदमी मारे गये | जख्मी हुये | जितने स्थानों पर लाठी चलाई गई | जितने आदमी मारे गये | जख्मी हुये |
|-------------|-------------------------------|---------------------|------------|-------------------------------|---------------------|------------|
| कुरुक्षेत्र | 1 | 1 | — | 1 | — | 8 |
| करनाल | 3 | 1 | — | — | — | — |
| सिरसा | 3 | 1 | 24 | — | — | — |

| | | | | | | |
|-----------|----|---|----|---|---|----|
| हिसार | — | — | — | 1 | — | 19 |
| गुंडगांवा | 2 | — | 7 | — | — | — |
| फरीदाबाद | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| सोनीपत | 2 | — | — | — | — | — |
| जोड़ | 12 | 4 | 32 | 2 | — | 27 |

अतारांकित प्र न एवं उत्तर

T.A. drawn by the officers in Election Department

464. Sh. Mool chand Jain: Will the Minister for Development and Panchayats be pleased to state the total amount of travelling expenses (T.A.) charged by various officers in Election Department on account of official tours during the years 1979-80 and 1980-81 (up-to date)?

विकास मन्त्री (राव दलीप सिंह): वाछित सूचना निम्नप्रकार हैं:—

| | |
|---------------|---------------|
| 1979—80 | 1981—81 |
| 8729—15 रूपये | 7162—50 रूपये |

T.A. Drawn by officers in Rehabilitation Department

465. Sh. Mool Chand Jain: Will the Minister for Revenue be pleased to state the total amount of travelling expenses (T.A.) charged by various officers in Consolidation and Rehabilitation Department on account of official tours during the years 1979-80 and 1980-81 (upto-date)?

राजस्व मंत्री (चौधरी भोर सिंह): चकबन्दी एवं पुनर्वास विभाग के विभिन्न अधिकारियों द्वारा सरकारी दौरे पर वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 (अब तक) के दौरान यात्रा भत्ता (टी.ए.) के रूप में चार्ज की गई कुल राशि निम्नलिखित हैं:-

| | 1979-80 | 1980-81 |
|----------------|---------|---------|
| | रूपये | रूपये |
| चकबन्दी विभाग | 32,744 | 56,260 |
| पुनर्वास विभाग | 19,352 | 22,275 |

T.A. drawn by the officers in Architecture Department

466. Shri Mool Chand Jain: Will the Minister for Public Works be pleased to state the total amount of travelling expenses (T.A.) charged by various officers in Architecture Department on account of official tour during the year 1979-80 and 1980-81 (upto date)?

लोक निर्माण मन्त्री (कंवर राम पाल सिंह): वास्तुकला विभाग के विभिन्न अधिकारीयों द्वारा वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 में सरकारी दौरे के लिये यात्रा भता की कुल राशि निम्नप्रकार है:-

| वर्ष | रूपये |
|----------------------|-----------|
| 1979-80 | 15,256.60 |
| 1980-81 (28-2-81 तक) | 11,364.30 |

T.A. drawn by the officers in Jails Department

467. Shri Mool Chand Jain: Will the Minister for Jails and Dairy Development be pleased to state the total amount of travelling expenses (T.A.) charged by various officers in Jails Department on account of official tours during the year 1979-80 and 1980-81 (upto date)?

जेल तथा डेरी विकास मन्त्री (चौधरी विठ्ठल राम वर्मा): वर्ष 1979-80 में 24,218 रूपये तथा वर्ष 1980-81 में 30,970 रूपये 60 पैसे।

House Rent Allowance drawn by the Chairman of Haryana Agro Industries Corporation.

473. Dr. Mangal Sein: Will the Minister for Agriculture be pleased to state-

(a) whether the present Chairman of Haryana Agro Industries Corporation is Drawing House Rent allowance every month;

(b) if the reply to part (a) above be in affirmative the amount of said allowance being drawn per month together with the date since when it is being drawn; and

(c) the residential address of the Chairman referred to above together with the date since when he is residing there?

कृषि मन्त्री (श्री भामदेव सिंह):

(क) तथा (ख) हरियाणा एग्रो इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन के चेयरमैन ने मकान किराया नहीं लिया है लेकिन दिनांक 12-9-79 जब से उन्होंने निगम के अध्यक्ष का कार्यभार सम्भाला है तब से 500 रुपये प्रतिमास की दर से रिहायगी भता जो कि उन्हें देय है, जे रहे हैं।

(ग) निगम के अध्यक्ष, जब भी चण्डीगढ़ में होते हैं तो वे विधायक आवास में निवास करते हैं।

श्री अध्यक्ष: अब श्री हीरा नन्द आर्य अ योरेन्सिज़ कमेटी की रिपोर्ट पे आ करेंगे।

कामरेड भांकर लाल: स्पीकर साहब, चण्डीगढ में। * * *

* * *

श्री अध्यक्ष: भांकर लाल जी जो कुछ बोल रहे हैं, वह रिकार्ड न किया जाये।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण

(i) स्थानीय भासन मन्त्री (श्री मांगे राम गुप्ता) द्वारा स्थानीय भासन मन्त्री (श्री मांगे राम गुप्ता): स्पीकर साहब, मैं कुछ अरज करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष: आप किस विषय पर बोलना चाहते हैं?

श्री मांगे राम गुप्ता: मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा कल हाउस में जीन्दके बारे में एक बात कही गई और उसमें मेरा भी जिक्र हुआ। मेरी कोस्टीच्यूएन्सी जीन्द है। स्पीकर साहब, हरियाणा में एक कहावत है कि किसी तेली ने जाट को कहा कि जाट रे जाट तेरे सिर पर खाट। जब जाट ने यह बात सुनी तो उसने भी तेली रे तेली सिर पर कोहलू। तेली कहने लगा भाई यह बात तो फिट नहीं बैठीं जाट ने कहा अगर फिट नहीं बैठी तो बोझ से तो मरेगा। यहां भी ऐसा ही हाल हो रहा है। यहां हाउस में खड़े होकर कुछ भी कह दिया जाता है। आदरणीय मंगल सैन जी ने एक बात कही कि

जीन्द की फर्म का फार्वर्ड ट्रेनिंग कस बिजनैस करती छें। जहां तक जीन्द की फर्म का संबंध है, वह रजिस्टर्ड फर्म हैं, उसके पास लाईसैंस हैं। इसी प्रकार से राजकोट में, दिल्ली में, पंजाब में अमृतसर, धुरी, लुधियाणा और राजस्थान में हनुमानगढ़ में यह काम चलता है। हरियाणा में हिसार, जीन्द और रोहतक में चलता है। जहां से मंगल सैन जी चुन कर आये हैं, वहां भी चलता है। उचाना और कैथल में भी चलता था लेकिन अब बंद हो गया है।

स्पीकर साहब, मैं विरोधी पक्ष के नेता श्री मूलचन्द जैन जी और जनता पार्टी के नेता श्री बलदेव तायल जी को अपनी तरफ से अधिकार देता हूं कि वे बे एक इन्कवायरी करायें। अगर यह बात साबित हो जाये कि इस फर्म ने एक कार और तीन लाख रुपया किसी मन्त्री को भेंट किया है तो मैं मन्त्रीमंडल से ही नहीं बल्कि मैम्बरशिप से भी अस्तीफा दे दूंगा। इन भाईयों को तकलीफ यह है कि जब से मैं रूलिंग पार्टी में आया हूं तब से इनकी आमदनी बन्द हो गई। 25 साल से वह कम्पनी रन कर रही है। लेकिन एक साल से जब से मैं रूलिंग पार्टी में आया हूं जब से पहले चौधरी देवी लाल के आदमी और फिर डा० मंगल सैन के आदमी इस फर्म पर नाजायज दबाव डाल कर पैसे लेते रहे। मेरे रूलिंग पार्टी में आने के पचास साल उन लोगों को पैसा मिलना बंद हो गया। इसी कारण से झूठे एलीगेशन लगाये जा रहे हैं।

(ii) डा० मंगल सैन द्वारा

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब मैं भी पर्सनल एक एक्सेम्प्लेनेशन देना चाहता हूँ। इन्होंने सदन में कहा कि जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पर भी सट्टा चलता है। रोहतक में चलता हो या किसी और जगह चलता हो तो वह गलत है। वह जुर्म है, वह कानूनन बन्द होना चाहिए। सरकार उसके बारे में एक एक्सेम्प्लेनेशन क्यों नहीं लेती? एक एक्सेम्प्लेनेशन लेना चाहिए रोहतक और जीन्द में भी बन्द होना चाहिए। कहीं भी चलता है, वह बन्द होना चाहिए। इन्होंने कल कहा कि हमने चिट्ठी लिखी हुई है, उसका जवाब आयेगा तो फिर देखेंगे। मेरा कहना यह है कि जो हमारे पर इल्जा जगा है, वह सरासर गलत है।

(iii) श्री रघुनाथ गोयल द्वारा

श्री रघुनाथ गोयल: स्पीकर साहब, मैं पर्सनल एक्सेम्प्लेनेशन देना चाहता हूँ कि मेरे हल्के कैथल में सट्टा नहीं चलता बल्कि कैथल के लिए मांगे राम जी ने कहलवा कर भेजा था कि सट्टा चालू कर दो।

(iv) चौधरी बीरेन्द्र सिंह द्वारा

चौधरी बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, चूंकि यहाँ पर उचाना का नाम लिया गया है। इसलिए मैं भी पर्सनल एक्सेम्प्लेनेशन देना चाहता हूँ। हमारे एक साथी ने तीन-चार

जगहोंका नाम लिया हैं कि वहां सट्टा चलता हैं। उचाना का भी उन्होंने नाम लिया। अगर वहां चलता है तो बन्द होना चाहिए। मैं दावे से कहता हूं कि जीन्द के बारे में यह कहना कि वह रजिस्टर्ड फर्म है गलत है। वह नाजायज हैं, इल्लीगल हैं।

गृह मन्त्री (श्री कन्हैया लाल पोसवाल): मैं हाउस को वि वास दिलाना चाहता हूं कि जहां पर भ इल्लीगल सट्टा होगा वहां हम रेड करायेंगे। जो भी इल्लीगल काम करेगा, उसको चैक करेंगे और गिरफ्तार करेंगे।

वि ोशाधिकार प्र न—

प्रैस में गलत रिपोर्टिंग संबंधी

डा० मंगल सैन: मैंने आज एक प्रिविलिज मो ान दिया हैं और यह मामला बड़ा सीरियस हैं। प्रैस ने हाउस के बिजनैस की ट्रांजैक् ान के ऊपर रिफ्लैक् ान किया हैं। कल मैंने जो उशा भार्मा के बारे में प्रिविलिज मो ान दी थी कि उसने मुझे टैलीफोन किया है।

Mr. Speaker: I have received your second privilege motion and i will take immediate action on it.

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैंने अपनी दूसरी प्रिविलिज मोशन में प्रेस के खिलाफ लिखा है कि प्रेस ने रिपोर्टिंग गलत की है।

Mr. Speaker: I will take immediate action on your motion.

श्री कंवल सिंह: मांगे राम गुप्ता जी ने अपनी पर्सनल एक्सप्लेनेशन में कहा है कि जा आरोप डा० मंगल सैन जी ने लगाये हैं उसकी इन्कवायरी बाबू मूलचन्द जैन और बलदेव तायल जी की कमेटी को रैफर कर दिया जाना चाहिए।

Mr. Speaker: Please do not refer to any allegations and counter allegations made in the House.

श्री कंवल सिंह: स्पीकर साहब, इन्होंने औफर किया है।

Mr. Speaker: No allegations and counter-allegations can be levelled against anybody in the House. Unless anything is given to me in writing, I will not take any action.

किसानों द्वारा चलाए जा रहे आन्दोलन सम्बन्धी मामला उठाना

कामरेड भांकर लाल: अध्यक्ष महोदय, आज 200 के करीब गरीब किसान बाहर खड़े हैं।

श्री अध्यक्ष: आप किस विषय पर बोलना चाहते हैं।

कामरेड भांकर लाल: अध्यक्ष महोदय, आज लगभग 200 किसान चण्डीगढ़ में आए हुए हैं और वे अपना आन्दोलन कर रहे हैं। ये किसान 2 महीने से अपना भ्रान्तिपूर्ण आन्दोलन चला रहे हैं लेकिन सरकार उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही हैं। इस प्रकार के आन्दोलन लोहारू और दूसरी जगहों पर भी चल रहे हैं। मैं आपके द्वारा मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि व उनसे बात करें और जायज मांगें मानें।

श्री अध्यक्ष: मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी उनसे जरूर मिलेंगे और उनकी बात सुनेंगे।

मुख्यमंत्री (चौधरी भजन लाल): यदि उनका भ्रान्तिपूर्ण आन्दोलन है तो हम उनकी बात जरूर सुनेंगे।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष: आप किस विषय पर बोलना चाहते हैं।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से चण्डीगढ़ में किसानों का एजीटे इन चल रहा है उसी प्रकार से भ्रान्तिपूर्वक एजीटे इन लोहारू के अन्दर भी दो महीने से चल रहा है। वहां के किसानों की मांगें हैं कि उन्हें 12 घण्टे बिजली दी जाये। वहां पर इस आन्दोलन के कारण महावीर नाम का एक किसान गोली से मारा गया है। लेकिन सरकार अक तक चुप बैठी है कोई कार्यवाही नहीं कर रही। मैं आपके माध्यम से सरकार को

कहना चाहता हूं कि उस मरने वाले किसान को कुछ मुआवजा दिया जाए। मेरी सरकार से यह भी प्रार्थना है कि उन किसानों के साथ बातचीत की जाए और उस एजिटे इन का कार्ड हल निकाला जाए।

श्री अध्यक्ष: मैं समझता हूं कि अगर कोई डैपुट इन आएगा तो मुख्यमंत्री जी उनसे जरूर मिलेंगे।

श्री बलदेव तायल: अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ आपका एक ही मिनट लेना चाहता हूं। मैं श्री मांगे राम गुप्ता जी, जो मंत्री हैं उनके साहस के लिए उन्हें बधाई देता हूं मैं उन्हें मुबारिकबाद देता हूं कि उन्होंने यहां खड़े होकर कहा है कि अपोजि इन के मैम्बर मेरे बारें में इन्कवायरी कर लें। अध्यक्ष महोदय, मैं उन्हें बधाई देता हूं कि यहां पर जितने मंत्री हैं उनमें से कम से कम एक मंत्री की जो यह बात कहने की हिम्मत हुई है। मैं चाहूंगा कि जिस प्रकार से मांगे राम गुप्ता जी ने सदन में कहा है कि अगर उनके खिलाफ आरोप साबित हो जाएंगे तो वे मंत्री पद से ही नहीं बल्कि एम0एल0ए0 िप से भी अस्तीफा दे देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि इसी प्रकार का आचरण दूसरों मैम्बरों को भी करना चाहिए। मैं उनका इस बात के लिए दोबारा धन्यवाद करता हूं। मैं समझता हूं कि कमेटी बैठाने की कार्ड आव यता नहीं हैं।

श्री मूल चन्द जैन: अध्यक्ष महोदय, मैंने पंजाब प्रिएम्पान (हरियाणा रिपीलिंग) बिल का नोटिस दिया था, उसका क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष: बाबू जी वह एडमिट कर लिया है।

श्री वीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, यहां चण्डीगढ़ के अन्दर पिछली 16 तारीख से किसान एजिटेन कर रहे हैं। 64 आदमीयों को परसो गिरफ्तार किया गया है। स्पीकर साहब, उनकी मांग है कि एम0आई0टी0सी0 जो पक्के खाल बनाती है उसका पैसा उनसे न लिया जाए। ये सारी रात को सर्दी में मरते रहें हैं। मुख्यमंत्री जी को और सरकार को किसानों की मांगों को सुनना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि उनकी जो जायज मांगे हैं, वह मान लें।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी वीरेन्द्र सिंह जी ने और दूसरे कुछेक साथियों ने कहा है कि करीब दो महीने से किसान एजिटेन कर रहे हैं और कुछ किसान चण्डीगढ़ में भी अपनी मांगों के लिए एजिटेन कर रहे हैं। इनका कहना है कि मुख्यमंत्री को और सरकार को उनकी मांगों को मानना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि वे भी मंत्री थे और इनके पास 2 साल और 6 दिन इरिगेन एंड पावर डिपार्टमेंट रहा। आज ये कहते हैं कि एम0आई0टी0सी0 जो पक्के खाल

बनाती है, उसका खर्चा माफ होना चाहिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जब वे मंत्री थे तो क्या इन्होंने कभी इस खर्च को माफ किया था? अध्यक्ष महोदय, हमने जिन किसानों के पास अढाई एकड़ से कम जमीन है उसका खर्चा बिल्कुल माफ कर दिया है और जिन किसानों के पास अढाई एकड़ से जमीन से ज्यादा है, उनसे आधा पैसा लेते हैं यानी आधा उनका भी माफ किया है।

श्री वीरेन्द्र सिंह: आप गलत ब्यानी कर रहे हैं। हमने प्रत्येक किसान का 33% खर्चा माफ कर दिया था।

चौधरी भजन लाल: आपने अपने समय में एक पैसा भी किसानों के खर्चे का माफ नहीं किया था। आज आप किसानों को आन्दोलन करने के लिए भड़का रहे हैं। लेकिन आज किसान इतना जागरूक हो चुका है कि वह आपके बहकावे में आ कर एजीटे न नहीं करेंगा। आज का किसान समझने लग गया है कि ये लोग अपने स्वार्थ के लिए हमें भड़का रहे हैं। मैं फिर चही कहता हूँ कि आज का किसान इतना भोला नहीं है कि वह आपके चक में आ कर कुछ गलत काम करें।

श्री वीरेन्द्र सिंह: यह बिल्कुल गलत ब्यानी कर रहे है।

चौधरी भजन लाल: मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज की सरकार ने किसानों के लिए किया है उतना आज से पहले किसी भी सरकार ने नहीं किया हम किसानों की बात सुनने के लिए सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक तैयार हैं।

उनके साथ बातचीत करने के लिए 24 घण्टे सरकार के द्वार खुले हुए हैं। उनकी समस्या का समाधान आपके पास नहीं, सरकार के पास है।

Mr. Speaker: Now zero hour is over.

चौधरी संत कंवर: आन ए प्वांयट आफ आर्डर सर, स्पीकर साहब,

श्री अध्यक्ष: आप किस की इजाजत से बोल रहे हैं?

चौधरी संत कंवर: स्पीकर साहब, मैं आपकी इजाजत से बोल रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष: श्री संत कंवर जी आप कृपया बैठ जाईए, otherwise, I will name you.

चौधरी संत कंवर: स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हूँ *

* * * * *

श्री अध्यक्ष: यह रिकार्ड न किया जाये।

कमेटी आन गवर्नमेंट अ योरेंसिज की 12वी रिपोर्ट पे । करना

श्री अध्यक्ष: अब श्री हीरा नन्द आर्य, कमेटी आन गवर्नमेंट अ योरेंसिज की 12वी रिपोर्ट पे । करेंगे।

श्री हीरा नन्द आर्य (चेयरमैन, कमेटी आन गवर्नमेंट अ योरेंसिज): मैं कमेटी आन गवर्नमेंट अ योरेंसिज की वर्ष 1980-91 की 12वी रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं।

कमेटी आन दि वैलफेयर आफ रि इड्यूल्ड कास्टस एंड रि इड्यूल्ड ट्राइब्ज की छठी रिपोर्ट पे आ करना

श्री अध्यक्ष: अब कैप्टन मांगे राम कमेटी आन दि वैलफेयर आफ रि इड्यूल्ड कास्टस एंड रि इड्यूल्ड ट्राइब्ज की छठी रिपोर्ट पे आ करेंगे।

कैप्टन मांगे राम (चेयरमैन, कमेटी आन दि वैलफेयर आफ रि इड्यूल्ड कास्टस एंड रि इड्यूल्ड ट्राइब्ज): मैं कमेटी आन दि वैलफेयर आफ रि इड्यूल्ड कास्टस एंड रि इड्यूल्ड ट्राइब्ज की वर्ष 1980-91 की छठी रिपोर्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं।

वर्ष 1981-82 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्ष: अब वर्ष 1981-82 के बजट पर चर्चा रित्यूम होगी। कल जब हाउस एडजर्न हुआ था ता श्री रण सिंह मान बोल रहें थे वे अब अपनी स्पीच जारी कर सकते हैं।

श्री रण सिंह मान(बाढड़ा): स्पीकर साहब, कल जब हाउस एडजर्न हुआ, उस समय मैं यह अर्ज कर रहा था कि सरकार की नीयत अगर वाकई गरीब लोगों की इमदाद करने की होती तो (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य चौधरी हरस्वरूप बूरा पदासीन हुए) किसान की, गरीब खेतीहार मजदूर की और कारीगर की माली हालत इस कदर कमजोर न होती कि वह कर्जा चुकान के अपने आपको असमर्थ महसूस करता। हमारे वित्त मंत्री जी ने इस हाउस में अपना जो बजट पे 1 किया हैं, उसमें इस मद के लिए कुछ भी पैसे का प्रोवीजन नहीं किया गया हैं जोकि इनको करना चाहिये गि। चेरमैन साहब, सरकार अपने मुलाजिमां को उनकी रिटायरमेंट के बाद पेंशन की सुविधा देती है ताकि उनकी जिन्दगी के आखिरी दिन सुखमय बीत सकें। अब तो यहां तक भी हो गया है कि विधायकों को भी पेंशन के दायरे में ले लिया गया हैं लेकिन यह एक बड़ी ही अजीब बात हैं कि खेत के अन्दर काम करने वाले किसान, खेतीहार मजदूर और कारीगर को जिन्होंने इस दे 1 और समाज के लिये काम किया हैं, समाज की खुहाली के लिए कमर तोड़ मेहनत की है, उनको उनकी जिन्दगी के आखिरी दिनों में सुविधा देने के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया हैं। आजकल यह तो सब को पता हैं कि रोजगार सीमित है और मैं समझता हूं कि एक सामान्य आदमी के बच्चों के लिए नोकरी पाना आज के जमाने में बड़ा ही मुश्किल हैं। मेरा कहना यह है कि युवकों को जब तक रोजगार नहीं मिलता उनका बेरोजगारी भत्ता देने का इन्तजाम करना चाहिए

था। अभी पक्के रोजगार नहीं मिलता उनको बेरोजगारी भत्ता देने का इन्तजाम करना चाहिए था। अभी पक्के खालों के खर्चकी बात यहां आयी और सवाल उठाया गया। यह सवाल अब ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि उनकी रिकवरी अब भुर्रु हो रही है। इसलिए सरकार को मैं यह निवेदन करने जा रहा हूँ कि आज किसान आन्दोलित हैं, वे अपनी मांगों को लेकर बड़े एजिटेटिड फील कर रहे हैं, मैं वित्त मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि राजनैतिक विरोध से थोड़ा दूर हट कर किसानों की जो समस्याएं हैं, उनके उपर वे सहानुभूतिपूर्वक गौर करें। चैयरमैन साहब, देहाती क्षेत्र में जो खेतीहार मजदूर और गरीब लोग हैं, उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए पिछली सरकार ने एक स्कीम भुर्रु की थी जिसका नाम काम के बदले अनाज रखा गया था। अब इस सरकार ने उसका नाम बदल कर राष्ट्रीय देहात रोजगार कार्यक्रम रखा है और उसे चालू रखने का निर्णय किया है। मैं इस बारे में एक अर्ज करना चाहता हूँ। चैयरमैन साहब, आज कुछ इलाकों में विशेषकर सार्वजनिक निर्माण के जो कार्य हैं, जो सरकार द्वारा करवाये जाते हैं, वे एक तरह से बिल्कुल बन्द पड़े हैं लगातार सूखा की स्थिति भी वहां पर बनी हुई है। विशेषकर भिवानी और उसके आस पास के इलाकों में खेतीहार मजदूरों, किसानों और गरीब लोगों के पास न तो खेतों में करने के लिए कोई काम है और न ही वहां पर कोई सार्वजनिक निर्माण के कार्य हो रहे हैं जिससे कि वे अपनी रोजी-रोटी कमा सकें यह जो राष्ट्रीय देहात रोजगार कार्यक्रम बनाया गया है, मैं चाहता हूँ कि

उसका दायरा बढ़ाकर उसमें बड़ी-बड़ी योजनाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए और हर गांव में एक कमेटी बनाई जाये। उस कमेटी में उन लोगों को भी शामिल किया जाना चाहिए जिन लोगों ने वहां पर काम करना है। इस कार्यक्रम में जिन लोगों को रोजगार मिलना है, उनको भी गांव की जो कमेटी इस बारे में बननी है, उसमें शामिल किया जाना चाहिए। पहले जो गांवों में इस तरह के काम हो रहे थे, वे अब बन्द हो गये हैं।

चौधरी राम लाल वधवा: चेयरमैन साहब, मेरा व्यवस्था का प्र न हैं। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि श्री आर्य जी ने जो अभी गवर्नमेंट अ योरेन्स कमेटी की रिपोर्ट हाउस में पे ा की है, उसकी कापी हमें नहीं पहुंची है। मेरा ख्याल यह है कि उसकी कापी अभी तक किसी भी मैम्बर को नहीं हैं जो कि प्रेजेन्ट हो चुकी है।

श्री सभापति: रामलाल जी, वह रिपोर्ट अभी प्रिन्ट होनी बाकी है। उन्होंने तो सिर्फ टाईप्ड कापी दी है।

चौधरी राम लाल वधवा: चेयरमैन साहब, इस बारे में रूल्ज़ तो क्लियर हैं कि जो भी कागज़ हाउस की टेबल पर रखे जाते हैं, उनको सभी सदस्यों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए।

श्री सभापति: वह आपको बहुत जल्द ही मिल जाएगी।

चौधरी राम लाल वधवा: इस बारे में तो मुझे पूरा वि वास है कि जब वह प्रिन्ट हो जायेगी तो मिल ही जायेगी

लेकिन मेरा तो प्वायंट आफ आर्डर यह था कि जब वह रिपोर्ट अभी प्रिन्ट नहीं हुई, तो हाउस में कैसे पे 1 कर दी गई?

श्री सभापति: आपका प्वायंट आफ आर्डर, तो मैंने सुन लिया है। टाईप्ड कापी हाउस की टेबल पर रखी जा सकती है। जैसे ही वह प्रिन्ट हो जाएगी, आप के पास उसकी कापी आ जाएगी।

11.00 बजे

श्री रणसिंह मान: सरकार को यह चाहिए था कि इस राष्ट्रीय देहात रोजगार कार्यक्रम को जा कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम की जगह भुरु किया गया है, बढाकर बडे-बडे कामों को भी हाथ में लेती ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मुहैया हो सकता। मेरा विचार यह है कि इस बारे में इस दस्तावेज में कुछ भी नहीं है। मैं वित्त मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि जैसे आपने मेवात विकास बोर्ड की स्थापना की है उसी तरह से विशेषकर भिवानी जैसे इलाकों का विकास करने के लिए डैजर्ट डिवैल्पमैन्ट बोर्ड की स्थापना भी की जानी चाहिए। यह जो वर्तमान स्कीम है, यह लोगों को किसी भी तरह से रोजगार नहीं दे पायेगी। केवल दस सैन्स में कि थोड़ासे कर्जा मिल जाने से लोगों रोजगार देने का ताल्लुक है, उसको पुरा करने के लिए इस राष्ट्रीय देहात रोजगार कार्यक्रम को बढाया जाना चाहिए था। मेरा कहना यह भी है कि यह जो काम के बदले अनाज कार्यक्रम की

बजाय आपने राष्ट्रीय देहात रोजगार कार्यक्रम भुरु किया है, इस कार्यक्रम के अधीन काम ऐसे इलाकों में भुरु किया जाना चाहिए जहां पर खेती का काम बिल्कुल ही नहीं बचा है ताकि वहां के लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें। चेयरमैन साहब, इसी तरह से पिछड़े हुए इलाकों का भी जिक्र किया गया है। राज्य के विकास के असन्तुलन को दूर करके संतुलित विकास करने के लिए कुछ कदम सरकार उठाने की बात करती हैं। सरकार यह भी दावा करती है कि यह जनहित की सरकार है लेकिन इसने पिछड़े हुए क्षेत्रों को ध्यान में नहीं रखा, इसने तो राजनैतिक आधार को ज्यादा ध्यान में रखा है। मैं उदाहरण के तौर पर बता सकता हूँ, चोधरी खुरीद अहमद भी इस बात से सहमत होंगे जैसे भिवानी का इलाका है, इस इलाके के सर्वे की जितनी रिपोर्ट्स हैं, उनमें उस इलाके की जमीन की पैदावार उसकी किस्म, वहां पर पानी की मात्रा और उसकी भौगोलिक स्थिति वगैरह यह बताती है कि भिवानी का इलाका भी महेन्द्रगढ़ जिला के समान पिछड़ा हुआ है। बिजली बोर्ड ने एक फैसला किया था। उस फैसले से हमें कोई तकलीफ नहीं है कि उसने कुछ इलाकों को राहत दी है। यह फैसला अखबार में भी आया था जो हमने पढ़ा था। हमें खुशी इस बात को जानकर हुई थी कि बिजली बोर्ड के इस फैसले से पिछड़े हुए इलाकों के कुछ लोग तो लाभान्वित होंगे लेकिन मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि भिवानी जिले की ओर राजनैतिक द्वेष के कारण कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मैं आशा करता हूँ कि सरकार का ध्यान इस ओर दिलाने के बाद वह इस

बात पर पुनर्विचार कर लेगीं। चेयरमैन साहब, इसी सन्दर्भ में एक बात की और सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं, जब चौधरी देवी लाल की सरकार थी उस समय भिवानी में ट्यूबवैल्ज की गहराई के हिसाब से टैरिफ रिलीफ दी गई थी। उस समय भी हमने यह मांग की थी कि गहराई का हिसाब न रखकर सभी तरह के कुओं पर टैरिफ रिलीफ लागू होनी चाहिए। गहराई की पाबन्दी हटनी चाहिए। चेयरमेन साहब, उस समय यह किया गया था कि अगर कोई कुआं पचास फुट गहरा है तो उसको इतना पैसा देना पड़ेगा और जो अस्सी फुट गहरे है उनका भाायद 120 रूपया प्रतिमाह देना पड़ेगा लेकिन इस बार बिजली बोर्ड ने बिना ख्याल किए कि कुओ की गहराई कितनी है, महेन्द्रगढ़ में तो कन्सै इन दे दिया है लेकिन भिवानी को इग्नोर कर दिया हैं जबकि ये दोनों इलाके साथ साथ लगते है। चेयरमैन साहब, यदि हम कम्पेयर करें तो महेन्द्रगढ़ की जमीन भिवानी से बेहतर है और महेन्द्रगढ़ मे पैदावार भी भिवानीके लिहाल से ज्यादा होती हैं। मैं समझता हूं कि सरकार इस बारै में पुनर्विचार करेगीं।

चेयरमैन साहब, अब मै मैचिंग ग्रांट के बारे मे कहना चाहता हूं। चेयरमैन साहब, लोकतान्त्रिक व्यवस्था में राजनैतिक विरोध को जन विरोध में नही बदलना चाहिए। लोगों ने अढाई साल पहले अपने खून पसीने की कमाई, मैचिंग ग्रांट लेने के लिए सरकार के पास जमा करवाई थी, लेकिन चेयरमैन साहब, आज तक सरकार की से मैचिंग ग्रांट नही दी गई है।

श्री सभापति: क्या पैसा जमा करवा रखा है?

श्री रण सिंह मान: जी हां। चिड़िया गांव में लड़कियों का स्कूल बनना था और उसके लिए गांव वालों ने 1.28 लाख रुपया जमा करवाया था। मैचिंग ग्रांट को शामिल करके 2.56 लाख रुपया बन जाता है लेकिन आज तक उस स्कूल की कंस्ट्रक्शन का कोई काम शुरू नहीं किया गया है। चैयरमैन साहब, लोगों ने बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा करके मुख्य मंत्री तथा दूसरे मंत्रियों को दिया था। मेरी प्रार्थना है कि सरकार इस तरफ ध्यान दे और लोगों की निराशा को दूर करें। बस में थोड़ी ही देर में खत्म कर दूंगा। चैयरमैन साहब, जैसा कि मैंने कहा है कि बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया जाए और जिस समय तक उनको रोजगार नहीं दिया जाता तब तक उनका बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। इसी तरह से बुढ़ापे की पेंशन भी दी जानी चाहिए। जहां पर सूखा है वहां तकावी और सहकारी कर्ज माफ किए जाए और जो भेद-भाव राजनैतिक आधार पर किया जाता है वह बन्द किया जाए। जनता की बिजली की जो मांग है वह पूरी की जाए। एम0आई0टी0सी0 खाले पक्का करने का खर्चा खुद वहन करें। इन मांगों को लेकर भिवानी में किसान आन्दोलन कर रहे हैं। चैयरमैन साहब, इस आन्दोलन ने बहुत ज्यादा सीरियस और नाजुक मोड़ तब लिया जब लोहारू का वाका हुआ। चैयरमैन साहब, पिछले साल से बिजली की सप्लाई बहुत कम हो गई है जब दस होर्स पावर की मोटर जल जाए तो उसकी रिपेयर पर

बहुत ज्यादा खर्चा आता है इस बात से किसान बहुत ज्यादा बेचैन थे। चेयरमैन साहब, इस वर्ष अचानक 15 फरवरी को लोवोल्टेज इतनी हो गई कि एक ही पावर हाउस के निचे सौ से अधिक मोटरें जल गईं और लोगों का ऐजीटे इन सामूहिक धरने के रूप में बदल गया। चेयरमैन साहब, 19 फरवरी को जो वाका हुआ जिसमें एक मौत हो गई थी, उसके बारे में मैं सरकार से तीन सवाल पूछना चाहता हूँ पहली बात तो यह है कि जिस दिन यह वाका हुआ उस दिन के बारे में मैं सरकार का कहना है कि रोड़ ब्लाक कर दी गई थीं वहा पावर हाउस के सामने एक खम्बा पड़ा हुआ था जिसको किसी आदमी ने खिसका कर सड़क के सामने डाल दिया था। मैं सरकार से पुछना चाहता हूँ कि उस वक्त वहां पर कितने आदमी थे। दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूँ कि उस वक्त वहां पर कितने वाहन खड़े हुए थे जो रोड़ ब्लाक होने के कारण रूक गए थे और कितने वाहनो को नुकसान हुआ? तीसरी बात मैं यह पुछना चाहता हूँ कि अश्रु गैस छाडनें से लेकर गोली चलाने के ऐक इन तक क्या किसी कोई चेतावनी लोगो को दी गई थी? तीन सवाल हमारे दिमाग में हैं जिसके बारे में सरकार स्पष्टीकरण दे। चेयरमैन साहब, किसान मजदूर संघर्ष समिती, न्यायिक जांच की मांग कर रही हैं। मैजिस्ट्रेट की जांच से कोई बात बनने वाली नहीं है चेयरमैन साहब, जिस आदमी की मौजूदगी में गोली चली हो और उसी स्तर का मैजिस्ट्रेट उस घटना की जांच करे यह न्याय व्यवस्था पर एक कलंक है इसलिए किसान मजदूर संघर्ष समिति यह मांग करती है कि मैजिस्ट्रेट की जांच

के स्थान पर न्यायिक जांच होनी चाहिए और मुझे आता है कि सरकार मैजिस्ट्रेट की जांच के स्थान पर न्यायिक जांच कराएगी।

चेयरमैन साहब, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। वैसे तो सरकार ने डी०ए० की एक किताब सरकारी कर्मचारियों को दे दी है और इनकी भलाई के लिए सरकार ने अपने कुछ और इरादे जाहिर किए हैं। चेयरमैन साहब, व्यवहार में यह बात नहीं है बल्कि इसके उल्टे हैं। सरकार कर्मचारियों की विभिन्न यूनियन्ज़ में भेदभाव पैदा कर करके आपस में लड़वा रही हैं और अपना मतलब साध रही हैं। विभिन्न यूनियन्ज़ में फुट डालकर कुछ को अपने पक्ष में कर लेती हैं, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। यूनियन के जो सच्चे प्रतिनिधी हैं, उनको स्वीकार करना चाहिए और उनमें किसी तरह का भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। लोकतान्त्रिक तरीके से उनको बुलाकर जो भी समस्याएं हैं, उनको निपटाना चाहिए। किसी भी राज्य के विकास के लिए कर्मचारियों का सहयोग बहुत जरूरी है। चेयरमैन साहब, मैं इतना ही कहकर समाप्त करता हूँ।

चौधरी रिजक राम(राई): चेयरमैन साहब, वित्त मंत्री महोदय ने 1981-82 का बजट पेश किया है इसके अन्दर उन्होंने लोगों की भलाई के लिए कुछ तजवीजें रखी हैं मैं उनके लिए वित्त मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूँ

श्री सभापति: चौधरी साहब, आप माइक का इस्तेमाल करें क्योंकि कुछ सुनाई नहीं दे रहा है और रिपोर्टर्ज को भी सुनने में दिक्कत आ रही है।

चौधरी रिजक राम: बहुत अच्छा जी। चेयरमैन साहब, इन्होंने ट्रैक्टरों के लिए बजट में रूपया रखा है। मैं यह महसूस करता हूँ कि आज हरियाणा में जितने भी ट्रैक्टर इस्तेमाल हो रहे हैं, उनको चलाने वाले और उन के जो मालिक हैं, वे उन ट्रैक्टरों के बिगाड़ और सुधार से वाकिफ नहीं हैं। पर अन्दाजा लगाया जा सकता है कि हरियाणा में और दूसरी जगहों पर एक ट्रैक्टर लगभग 12 साल तक चलता है। सब से ज्यादा रूपया किसान को उनकी रिपेयर पर खर्च करना पड़ता है। आठ-तीन साल पहले इस प्रश्न का निरीक्षण किया गया था और अन्दाजा लगाया गया था कि एक ट्रैक्टर की मरम्मत पर कम से कम 5 हजार रूपये सालाना खर्च आता है तो 12 सालों में आप खुद ही देख लीजिए कि कम से कम 60 हजार रूपया खर्च होगा।

चेयरमैन साहब, इससे आगे मैं बताना चाहता हूँ कि इस बजट में एम.आई.टी.सी. के लिए भी प्रावधान किया गया है। पक्के खालों पर सरकार जो खर्च कर रही है, उस पर भी रियायत दी गई है। ये ऐसी बातें हैं, जिससे किसानों को काफी लाभ पहुंचेगा। इसके लिए वाकई वित्त मंत्री, चौधरी खुरीद अहमद बधाई के पात्र हैं। इसके साथ-साथ चेयरमैन साहब, सरकार ने जो प्राईवेट कालेजों के लिए 95 परसेंट ग्रांट का प्रावधान रखा है,

उससे कालेजो को काफी सहायता मिलेगी। यह कदम जो सरकार ने उठाया है, यह सचमुच मे ही सराहनीय हैं। लेकिन एक बात मैं उनको यह कहना चाहता हूं कि 1977 के आम चुनाव के बाद यह चौथा बजट है जा इस विधान सभा में प्रस्तुत किया गया है और चौथे ही वित्त मंत्री हैं पहले सतबीर सिंह मलिक आये, उसके बाद बाबू मूल चन्द जी जैन आए और फिर तायल साहब और अब श्री खुर शिद जी वित्त मंत्री है। बाबू जी ने बहुत ही जल्दी जल्दी काम किया और चार पांच महीने मे ही चले गये। अब मुझे इस बात का भी खद है कि कही भाई खुर शिद भी उसी रिवायात का िकार न हो जाएं। कहीं यह बात न हो जाए कि अगला बजट कोई दूसरा वित्त मंत्री पे ा करें। भाई खुर शिद जी इस रिवायात को तोड़ सकें तो अच्छा है। इन्होंने यह रिवायात जारी रखने की को ि ा तो बडी की थी क्योकि जिस दिन यह बजट पे ा होना था, उस दिन चे लेट हो गये थे। जब मुख्य मंत्री बजट पढने के लिए खड़े हुए तो देवेन्द्र भार्मा और दुसरे साथी इनको पकड़ कर लाये। जहां तक मुख्य मंत्री जी का ताल्लुक है, चाहे कोई नाराज हो या खु ा हो, इनको तो 15-20 सालों तक इस पद पर रखना ही पडेगा इन्होंने जो इतने लम्बे चौड़े लोगों के साथ वायदे कर रखे हैं, व 15-20 सालो तक ही पूरे हो सकेंगे। चेयरमैन साहब, चौधरी भजन लाल से पहले चौधरी देवी लाल जी इस प्रदे ा के मुख्य मंत्री थे। वे बड़े ही कार्यकु ाल थे और जिस धुन मे लग जाते उसमें ही जुटे रहते थे लेकिन थे बहुत भोले। उनके समय की एक बात मुझे याद आ गयी, बाबू मूल चन्द जैन

भी मेर समर्थन करेंगे। कुरुक्षेत्र जिले मे चौधरी ई वर सिंह जी के गांव का मुखराल सरपंच चौधरी ई वर सिंह के पास आया और कहने लगा कि मेरे को चौधरी देवी लाल जी से मिला दो। चौधरी ई वर सिंह ने कहा कि वे सुबह के समय एम.एल.एज. होस्टल में आते है आप वहा पर मिल लेनां वह बड़ा खुा हुआ और बड़े चाव के साथ सुथरे कपड़े पहन कर सुबह होस्टल में मिलने के लिए गया। वह पांच सात मिनट मे ही वापिस आ गया। चौधरी ई वर सिंह ने पूछा कि मिल आये भाई? कहने लगा कि उनके अपने गांव के सरपंच उनकी तरह ही बड़े लम्बे चौड़े कद के है, वे भी वहां पर बैठे थे वह कहने लगे कि आपने चौधरी देवी लाल जी को मुख्य मंत्री छांट कर अच्छा नही किया क्योंकि वे सभी लम्बे कद के थे और मैं छोटे कद का था। मैं पिछे खडा रह गया। वे मुझे देख नही पाए इसलिए मिल नही सका। (हंसी एवं भाोर) चेयरमैन साहब, इस के बाद जहां तक एम0एल0एज0 होस्टल का ताल्लुक है, वहां पर बहुत कम जगह हैं। वहां पर एम0एल0एज0 से मिलने वाले लोगो का तातां लगा रहता हैं। आपको भी इस बात का तजर्बा है इसलिए मेरी आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना है कि एम0एल0एज0 होस्टल के साथ एक धर्म ाला बना दी जाए। इसके लिए बजट के अन्दर पैसा तो रखा नही गया हैं लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी के पास पैसा बहुत हैं, पैसे की कमी नही है। खुर गीद अहमद साहब हज करके आए हैं और खुदा की इबादत हासिल करके आये हैं। (हंसी व भाोर) मुख्यमंत्री जी के पास पैसा बड़ा है, उनका भाग्य बड़ा बलवान हैं।

चाहे कहीं पर बैठे हो, जिस प्रकार लोग महन्तों को पुजते हैं, चढावा चढाते हैं उसी तरह से उन्हें भी चढावा चढता है। इसलिए रूपय की कमी नहीं है।

चेयरमैन साहब, इससे आगे मैं बजट की अगली बातों पर आता हूँ। चौधरी खुरीद अहमद जी ने बजट स्पीच देते हुए इस बात का जिक्र किया कि 49 करोड़ रूपय का सरकार को घाटा है। लेकिन उन्होंने बचत की जो प्रस्तावित बातें हैं, उन पर अमल करके घाटे को पूरा करने की बात कहीं है कि इस तरह से घाटा पूरा किया जाएगा। चेयरमैन साहब, भावना तो उनकी अच्छी है और हमें आशा भी रखनी चाहिए कि जो उन्होंने बात कही भावद ठीक हो। कुछ और भी मद ऐसी हैं, जिनसे बचत खासी हो जाएगी। अगर रावी व्यास के पानी को फैसला न हुआ तो उस के लिए जो खर्चा रखा गया है, वह बच जाएगा। पक्के खालो के लिए जो रूपया है, उसमें से भी कुछ रूपया लोगों से वसूल होना है। यह रूपया जो सरकार पहले खर्च करेगी और बाद में कुछ वसूल होगा। इसलिए कुछ बचत तो स्वाभाविक तौर पर हो जाएगी। लेकिन मैं यह समझ नहीं पाया कि यह 49 करोड़ रूपय का घाटा जो है, वह किस तरह से पूरा किया जाएगा? इसलिए चेयरमैन साहब, पिछले बजट में सरकार ने नान-प्लान के तहत 291 करोड़ रूपये की राशि निर्धारित की थी लेकिन अब नान-प्लान एकसपेन्डीचर की फिगर 331.41 करोड़ रूपये से भी ज्यादा है यानि लगभग 40 करोड़ रूपया सरकार ने ज्यादा खर्च किया है।

इस ज्यादा खर्च का वित्त मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कारण यह बताया है कि एक ता सरकारी कर्मचारियों के मंहगाई भते के कारण खर्चा बढा है और दूसरे जो नेचुरल कलैमिटीज के कारण नुकसान हुआ हैं, उसके कारण खर्च बढा है मैं उन्हे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर भाई खुर पीद ने अपने काम को ठीक ढंग से चलाना हैं, तो जो पहले रिवायत चली हुई है, उसको बन्द करना होगा। मुख्य मंत्री महोदय जहो भी जाते हैं, वे किसी भी विभाग के अफसर से नहीं पूछते, वित्त मंत्री जी से भी नहीं पूछते कहीं 50 लाख रूपये की ग्रांट मन्जूर कर आये, कहीं पर हस्पतालों के लिए मन्जूरी दे आये और कहीं पर नई सब तहसील बनाने की घोशना कर आये। चेयरमैन साहब, इस काम के लिए एक सब कमेटी बैठी थी। उसने जिस जिस जगह पर तहसील या सब तहसील बनाने के लिए सिफारि ा की थी, इन्होंने उससे 8-10 फालतु ही बना दीं। जहां पर जरूरत थी वहां जो बनाई नही, दूसरी जगहो पर बना दी। चेयरमैन साहब, खरखोदा के लिए कमेटी की रिक्मेन्डे ान थी, लेकिन वहो पर तहसील न बनाकर किसी दूसरी जगह पर बना दी गयी रोज हम अखबारों मे पढते हैं कि मुख्यमंत्री जी वहां वहां गए और यह मंजूर कर आए। कैथल के बारे में भी जिला बनाने के लिए भाोर था। (तोर) चेयरमैन साहब, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री स जी ने जो अब तक वायदे किये हैं अगर उनको पूरा किया जाए तो 350 करोड़ रूपये और खर्च करना पड़ेगा। मैने सरकारी अफसरों से पूछा है कि मुख्यमंत्री जी जो वायदे करते हैं क्या आप उनका रिकार्ड

रखते हो जो मुझे बताया गया कि अगर सभी वायदों को पूरा किया गया जो इतना खर्च होगा। इसलिये अगर सारे वायदों को पूरा किया गया तो बजट में और भी घटा होगा। अगर ज्यादा घाटा नहीं दिखाना है तो इन वायदों को पूरा किया गया जो बजट में और भी घाटा होगा। अगर ज्यादा घाटा नहीं दिखाना है जो इन वायदों को पूरा किया गया जो बजट में और भी घटा होगा। अगर ज्यादा घाटा नहीं दिखाना है तो इन वायदों को कम करने की कोशिश करें। चेयरमैन साहब, वित्त मंत्री जी ने एक सुझाव रखा है कि अगले साल सरकारी नौकरियों में लये कर्मचारियों को नहीं लगाया जाएगा इलैक्ट्रान तो चाहे मई जून में हो या उससे आगे हो लेकिन एक बात जरूर है कि जो भी काम इस साल किया जाएगा वह इलैक्ट्रान को ध्यान में रख कर किया जाएगा। इसलिए उसको सामने रखते हुए मंत्रीमण्डल भी और मुख्य मंत्री भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि लोगों की डिमांड ज्यादा से ज्यादा पूरी की जाएं। चेयरमैन साहब, आप हैरान होंगे कि जब लोकसभा के इलैक्ट्रान हुए तो बहुत से लड़कों ने हमें बताया कि हम मुख्य मंत्री जी से मिले थे। उन्होंने हमें कहा कि सोनीपत के हल्के में जाकर काम करो और करनाल के हल्के को जरूर ठीक तरीके से संभालना। आपको नौकरियां दी जाएगी। * * * * (विधन) तो चुनाव नजदीक हैं और कोई भी सरकार ऐसी नहीं हो सकती जो इस बात पर ध्यान न दे(विधन)

श्री सभापति: ब्याह भादी के बारे में जो बात की गई है, वह एक्सपंज कर दी जाए।

श्री बलदेव तायल: चेयरमैन साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर हैं। एक्सपंज इन का एक रूल है। उसके अन्दर यह लिखा हुआ है कि अगर कोई भाब्द डैफेमेटरी था या डेरागेटरी हो, वह एक्सपंज हो सकता है लेकिन इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है और किसी मन्त्री ने इस बार में प्रोटेस्ट भी नहीं किया।

श्री सभापति: चेयर अगर किसी भाब्द को डैफेमेंटरी समझें तो उसे एक्सपंज किया जा सकता है। रूल 116 बड़ा क्लियर है उसे मैं पढ देता हूँ।

“If the Speaker is of opinion that a word or words has or have been used in debate which is or are defamatory or indecent or un-parliamentary or undignified, he may, in his discretion, order that such word or words be expunged from the proceedings of the Assembly.”

Shri Baldev Tayal: I have to submit that it is all right that if, in the opinion of the Chair, a word is defamatory or indecent or indecent or un-parliamentary or undignified that word or words can be expunged. This word is neither defamatory nor derogatory. How can it be expunged?

Mr. Chairman: The rule says that if the word is defamatory or indecent or unparliamentary or undignified, it can be expunged. This word was indecent. Therefore, I have ordered to expunge it. Please be seated.

Shri Baldev Tayal: I do not challenge your authority.

Mr. Chairman: Please take your seat. I have given my ruling.

चौधरी रिजक राम: चेयरमैन साहब, एक तरफ तो यह सरकार कहती है कि हमन बेरोजगारी को खत्म करने के लिये पूरे प्रबन्ध कर दिये हैं और दुसरी तरफ स्कूल को अपग्रेड किया जा रहा है। कालेजों से आज ग्रेजुएट्स और एम0ए0 बहुत तदाद में आ रहे हैं। इसके अलावा पॉलिटैकनिक और आई0टी0आईज0 से भी बहुत से डिप्लोमा होल्डर आ रहे हैं आप देखें कि दस साल अप्रैल में अकेले जो मैट्रिक पास करके आएंगे उनकी संख्या कितनी होगी और उधर सरकार कहे कि हम तो किसी को साल भर नौकरी नहीं देंगे तो यह बात ठीक नहीं। इसलिए मैं अर्ज करता हूँ कि ऐसी हालत में भी अगर सरकार यह कहे कि इस साल हम नई भरती नहीं करेंगे जो यह कोई ठीक बात नहीं है। इनको जो बल्कि नौकरीयों के दरवाजे और खोलने चाहिए। खर्च को कम करने के और भी तरिके हैं जैसे जहा पर फिजूल खर्ची हो रही हो, उसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए न कि इस बात पर कि नई भरती नहीं की जाएगी। दूसरी बात चेयरमैन साहब, मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपका देहातों से पूरा संबंध है और बेरोजगारी की समस्या सब से जटिल और संकट पैदा करने वाली समस्या है। आप देखे कि वित्तमंत्री जी ने अपनी बजट स्पीच में बताया कि हरियाणा में 36 प्रति शत लोग ऐसे हैं जो गरीबी की

रेखा से नीचे है आपको मालूम है कि गरीबी की रेखा के नीचे का क्या मतलब है। 1960-61 कह कीमतों के आधार पर जो लागू गरीबी की रेखा से नीचे थे उनका एक महीने का खर्चा 20 रूपय निकाला गया था तो आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि जिस आदमी को 20 रूपये महीना मिलता हो उसकी क्या हालात होगी? इसी तरह से 1960-61 की मर्दम भूमारी के वक्त हरियाणा में 66 प्रति ात किसान ऐसे थे जिनके पास पांच एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं थी लेकिन जब 1975 में सर्वे किया गया जा 75 प्रति ात लोग ऐसे थे जा पांच एकड़ या उससे कम भूमि के मालिक थे और उसमें से 29 प्रति ात लोग ऐसे थे जिनके पास सिर्फ अर्ध एकड़ या उससे कम जमीन थी। आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि एक एकड़ वाले भूस्वामी ही क्या हालत हो सकती है? स्माल फार्मर्स डिवेलप एजेंसी ने भी उनको कार्ड राहत नहीं दी। इसके अलावा देहात में बसने वाले जो हरिजन हैं, दस्तकार हैं या दूसरे लोग हैं उनकी हालत भी बहुत खराब है। आज से 30 साल पहले देहात में कुछ भाई मोची का काम करते थे, कुछ कुम्हार भाई बर्तन बनाने का काम करते थे और लोहार भाई लाहे का काम करते थे लेकिन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ने उन सबके धन्धे बंद कर दिये। (घंटी) चेरमैन साहब, अभी तो मैंने भूमिका बांधी है, आपने घंटी बता दी। मैं अर्ज कर रहा था कि आज दे ा में जितने दस्तकार हैं, वे बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज के कारण बेकार हैं और दिनो-दिन गरीब होते जा रहे हैं। 85 फीसदी लोग जो देहातों में रहते हैं, इनमें से बहुत बड़ी संख्या सर्विसिज में है, चाहे स्टेट

सर्विसिज में हों, चाहे सैन्ट्रल सर्विसिज में हो और चहे म्यूनिसिपल कमेटीज में काम करते हों, कहने का मतलब यह हैं कि ये लोग 85 परसेंट लोग भाहरों में ऐसे हैं जिनके कारखाने है या तजारत का काम हैं में गरीबों को दबाते हैं। जहां तक हरिजनो का सवाल है, आप महकमों में जाकर जांच पड़ताल कर लें कि इंड्यूल्ड कास्टस की रिजर्वें इन किसी भी महकमें में पूरी नहीं हैं। 85 परसेंट आबादी जो देहातों में रहती है इनमें करोड़ों की तादाद हरिजन भाईयों की हैं। इनमें बड़ी बैचेनी फैली हुई है और परिणाम यह हो रहा है कि विशय को यहीं पर समाप्त करता हूं। दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आज देहात में लाखों लोगों की तादाद में पढ़े लिखे बेराजगार नौजवान है जिनको मां-बाप ने बड़ी कठिनाई से पढाया है। कठिनाई इसलिए होती है क्योंकि 85 परसेंट आबादी के पास जायदाद बहुत कम है इसलिए पूरा खर्चा देकर अपने बच्चों को पढा नहीं सकते। जिन्होंने पढाया है उन्होंने अपना पेट बांधकर बच्चों का तालीम दी है। इस ख्याल से कि बच्चे पढ़-लिख कर सहायता तो क्या करनी थी उल्टा मां-बाप पर बोझ बने हुए है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। मैं सरकार का इस तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो गरीब आदमी देहात में हैं, चाहे हरिजन है, चाहे किसान हैं, चाहे मजदूर हैं इनको सर्विसिज मिलनी चाहिए। इन गरीब बच्चों में काबिल से काबिल कैंडिडेट्स मौजूद हैं लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो बड़े बड़े सरमायेदार और पूजीपति है, वे अपने असरो-रसूख

के बल पर, धन की ताकत के बल पर नौकरियां ले जाते हैं और देहात के गरीब कैंडिडेट्स नौकरियों से महरूम रह जाते हैं। देहातों के लड़के, जिन्होंने फर्स्ट क्लास में इम्तिहान पास किया हुआ होता है और नौकरी के लिए, सरकार के दरवाजे खटखटाते फिरते हैं, वे तो सर्विसिज़ से महरूम रह जाते हैं और असरो-रसूख वाले अमीर आदमियों के बच्चे, जिनके पास पैसे की ताकत है, थर्ड डिविजन में पास होने के बावजूद भी नौकरियां ले सकते हैं। आज लियाकत के वेसिज़ पर सर्विसिज़ नहीं दी जाती। अगर धन की ताकत की वजह से गरीबों को नौकरियों में हिस्सा नहीं मिलता तो जहां तक मैं समझता हूँ, भूमि-कान्ति के अलावा इस समस्या को हल करने का और कोई चारा नहीं। (तालियां)

श्री सभापति: आर्डर प्लीज आर्डर। (व्यवधान)

चौधरी रिजक राम: चेयरमैन साहब, आज सर्विसिज़ का सिलैब इन धन के ताकत के बल पर होता है। दूसरा आर्टिकलिया रह जाता है कि सिलैब इन करते समय यह देखा जाता है कि यह आदमी अमुक इलाके से ताल्लूक रखता है या नहीं, अमुक जाति से ताल्लूक रखता है या नहीं। अगर वह उस पार्टिकुलर दलाके या जाति से ताल्लूक रखता हो तो उसकी सर्विसिज़ में प्रेफरेंस दी जाती है। इस सिस्टम में मुताबिक किसी की लियाकत या नालायकी का कोई अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता। जो कैंडीडेट्स उस पार्टिकुलर इलाके और जाति से बिलोंग करते हैं उनको ले लिया जाता है और बाकियों को नज़रअन्दाज कर दिया

जाता है, यह इन्साफ की बात नहीं है। चेयरमैन साहब, अभी-अभी सब-जजिज का सिलैकान हुआ..... (व्यवधान)

Finance Minister (Chaudheri Khurshid Ahmed):

Mr. Chairman, the case of selection of sub-judges is pending in the Court and it can not be discussed here.

Mr. Chairman: Chaudhari Rizaq Ram Ji, this matter is sub-judice I will request you not to discuss it here.

Chaudhri Rizaq Ram: All right, sir, I leave this point. चेयरमैन साहब, मैं दूसरी बात पर आता हूँ सरकार ने दो हजार से ज्यादा आबादी वाले देहातों में कुन्यूमर्ज स्टोर्ज खोलने का एलान किया था जिन के लिए हाल ही में सेल्जमैन की भर्ती हुई। सरकार ने 2300 सेल्जमैन की सिलैकान की, लेकिन चेयरमैन साहब, आप जानकर हैरान होंगे कि 2300 की सिलैकान में दो बिरादरियों के ही लड़के लिए गए हैं और दूसरी बिरादरियों को इग्नोर कर दिया गया। ये कैंडीडैट्स हरियाणा से ही नहीं लिए गए बल्कि राजस्थान और यू0पी0 के भी लिए गये हैं। चेयरमैन साहब, जात-बिरादरी के आधार पर, इलाकाई तौर पर पक्षपात करके सेल्जमैन की भर्ती करना हमारे नौजवानों के साथ निहायत पक्षपातपूर्ण कार्यवाही है। यही नहीं, चेयरमैन साहब, 2300 सेल्जमैन में से सोनीपत जिले के सिर्फ 15 लड़के लिए गए, क्या यह इलाकाई पक्षपात नहीं? सोनीपत जिले से न कोई असिस्टेंट मैनेजर लिया और न कोई सुपरवाइजरी स्टाफ लिया केवल 15 सेल्जमैन लिए और मामला साफ कर दिया। अगर इस तरहसे

हरियाणा के देहाती लड़को के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया गया तो हरियाणा का भविष्य क्या होगा, यह आप सब जानते हैं। आज लाखों लड़के स्कूलों और कालेजों से पढ कर निकल रहे हैं। जब ये अपनी एजुकेशन पूरी करके आते हैं तो इनके दिल में पहले ही यह भावना होती है या डाल दी जाती है कि सरकारी अफसर जात-बिरादरी और इलाकाई-पक्षपात के आधार पर सिलैक्ट करके आते हैं। चेरमैन साहब, मैं पूरे विवास के साथ कह रहा हूँ कि जो सर्विसिज में भर्ती करने वाले आफिसर हैं, वे पक्षपातपूर्ण भावना से काम काम लेते हैं। वे अपनी जेबों में ब्लैक अप्वायंटमेंट लटर्ज तैयार डाले रखते हैं और जब किसी ने सिफारिश की तो फौरन उसका नाम भर देते हैं। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) डिप्टी स्पीकर साहब, एस0एस0एस0 बोर्ड के द्वारा सर्विसिज में भर्ती की जाती है। आम आदमी काम ध्यान एस0एस0एस0बोर्ड की तरफ नहीं जाता, लेकिन मैं दो बातों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। बोर्ड ने कुछ असामियों की भर्ती करनी थी और इस भर्ती में ऐसे कंडीडैट्स को चुना गया जिनकी दरखास्तें भी एस0एस0एस0 बोर्ड में वसूल नहीं हुई थी और टैस्ट में भी शामिल नहीं हुए थे। इस सिलसिले में मेरे पास सुचना है। (व्यवधान) लोगों ने कम्प्लेंट्स की हुई हैं। (व्यवधान) तो डिप्टी स्पीकर साहब, मैं ज्यादा न कहता हुआ, यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां तक बेरोजगारी का सवाल है, इसको दूर करने के उद्देश्य से सर्विसिज में पक्षपात नहीं करना चाहिए। आखिर में बैठने से पहले एक बात और अर्ज कर दूँ कि पिछले दिनों 2

जनवरी को मुख्य मन्त्री जी राई में गए थें, चौधरी जगन नाथ जी भी साथ थे। इन्होंने वहां ऐलान किया कि हरियाणा सरकार ने फैसला किया हैं कि जो भी पढे लिखे अन-एम्पलायड लड़के हैं उनमे जो एम0ए0 पास है उनको 100 रूपये महीना और जो बी0ए0 पास है। उनको 75 रूपये महीना अन-एम्पायमेंट अलाउन्स दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री (चौधरी भजन लाल): मैंने ऐसा कोई एलान नहीं किया। (विघ्न)

चौधरी रिजक राम: इन्होंने ऐसा ऐलान ना भी किया हो तब भी मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि इन्हे अब ऐसा करना चाहिए। चौधरी खुर पीद अहमद जी के बारे में सभी जानते हैं कि वे फराख दिल और रंगीन मिजाज के आदमी हैं इसलिए उन्हें ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। (विघ्न) डिप्टी स्पीकर साहब, अपने दे 1 में महाराष्ट्र और बंगाल आदि कई प्रान्तों ने अनएम्पलायड लोगों के लिए इस तरह का अलाउन्स मुकर्रर किया हैं। यह अलाउन्स चाहे 100 रूपये का हो, 75 रूपये का हो या भाबदों के साथ डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका भुक्रिया अदा करता हूं।

चौधरी जय नारायण(कलानौर, अनुसूयित जाति): डिप्टी स्पीकर साहब, समय देने के लिए मैं आपका धन्यावाद करता हूं। वित्त मन्त्री, चौधरी खुर पीद अहमद जी ने हाउस के सामने 49

करोड़ रूपये का बजट रखा है। इन्होंने बड़ा खोखला और बेजान बजट पेश किया है। (विधन) यही नहीं हाउस को गुमराह करने की कोशिश भी की गई है। इन्होंने कहा है कि अपने खर्च में कमी करके इस घाटे को पूरा करेंगे। डिप्टी स्पीकर साहब, असल में यह घाटा 49 करोड़ का नहीं, 70 करोड़ का है। यह हिसाब 34-35 पृष्ठों की है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके नाटिस में यह बात लाना चाहता हूँ कि हरिजनों के अन्दर भी 5-7 परसेंट ऐसे लोग हैं जो ज्यादा फायदा उठाते हैं। हरिजनों के अन्दर कम से कम 35-36 बिरादरियां हैं लेकिन बजट का या हाउस द्वारा पास किए गए पैसे का ज्यादा फायदा एम0एल0एज0, मिनीस्टरर्ज या बड़े पदाधिकारी ही उठा लेते हैं और जो गरीब हरिजन है उन तक यह पैसा नहीं पहुंचता। ब्याह भाादी के अन्दर पैसों की जब बौछार करते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो झोली लेकर उपर ही उन पैसों को थाम लेते हैं। इसी तरह से हरिजनों के लिए पास हुए पैसे को केवल पांच सात प्रतिशत लाग ही हजम कर जाते हैं और गरीब हरिजन, जो देहात के अन्दर बसने वाला है, उस तक यह पैसा बिल्कुल नहीं जाता। डिप्टी स्पीकर साहब, पैसा चाहे मकान बनाने के लिए हो, ट्यूबवैल लगाने के लिए हो या चाहे किसी और काम के लिए हो सबमें यही बात है। इसलिए मैं आपके द्वारा सरकार से कहना चाहता हूँ कि वह गरीब तबके की तरफ भी ध्यान दे। हमें आजाद हुए तकरीबन 32-33 साल हो गए हैं लेकिन आप रिकार्ड निकाल कर देख लें हर डिस्ट्रिक्ट में, ऐडवाइजरी कमेटी जो ग्रांट बांटती है, उसमें एक ही वर्ग के

आदमी होते हैं। जबकि हरिजनों में बालमिकी है, धानक हैं और चमार भाई भी हैं। इन लोगो को एक पैसा तक नहीं मिलता क्योंकि भाई, भतीजे, चाचे और ताउ के नाम पर सारे का सारा पैसा दूसरे वर्ग में डिवाइड हो जाता है। इसी तरह का मामला नोकरियों में है डिप्टी स्पीकर साहब, इस बजट में किसानों के बारे में भी ज्यादा बढा चढा कर कहा गया है। ये कहते हैं कि पहले गन्ने का भाव 13 रूपये क्विंटल था लेकिन अब 26 रूपये क्विंटल कर दिया गया है। डिप्टी स्पीकर साहब, इसमें कोई भाक नहीं कि पिछले साल गन्ने का भाव सरकार ने 13 रूपये क्विंटल निर्धारित किया था लेकिन उस वक्त चीनी का भाव भी अढाई और तीन रूपये किलो था। इस साल चीनी आठ नौ रूपये किलो बिक रही है इसलिए गन्ने का भाव कम से कम 40 रूपये क्विंटल होना चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहब, किसानों के साथ बहुत ही ज्यादा खिलवाड़ या जा रहा है। बिजली के रेट को ही आप देख लें। देहात में बसने वाले गरीब लोगो और व्यापारियों आदि के उपर तो बोझ डाल दिया गया है लेकिन बडे बडे पुजीपतियों को बड़ी रियायते दी गई हैं। इसी तरह से बेरोजगारी का मामला है। हमारे प्रदे के अन्दर हर साल तकरीबन एक लाख नौजवान पढ-लिख कर तैयार हो जाते हैं लेकिन यह सरकार केवल बीस हजार आदमीयों को ही रोजगार दे पाती है इस तरह से इस सरकार के राज मे 80 हजार के करीब नोजवान हर साल बेराजगार हो जाते हैं। उनकी मदद करना सरकार का फर्ज बनता है। जिस तरीके से दूसरी स्टेटो मे बेरोजगार आदमियों को भता दिया जाता है उसी

तरीके से इस सरकार को भी उन लोगों को भत्ता जरूर देना चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहब, फूड एंड सप्लाइज महकमे का भी बुरा हाल है। आज किसान को चार या पांच सीमेंट के कट्टों के लिए दर दर की ठोकरे खानी पडती हैं जबकि ब्लैक मै तीस रूपये का कट्टा पचास और साठ रूपये में खुला मिलता है। (विधन) एम0आई0टी0सी0 और इरीगे 1न डिपार्टमेंट के बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन यह बात ठीक नहीं है कि ब्लैक में 60 रूपये के हिसाब से जितने सिमेंट के कट्टे लेना चाहो ले सकते हैं।

डिप्टी स्पीकर साहब, ये कहते हैं कि हमने हरिजनों को बहुत ज्यादा उपर उठाना है। लेकिन इस बात की एक और मिसाल में आपको बताना चाहता हूँ। डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में रोहट एक गांव है। वहां हरिजनों ने 50-60 साल पहले से पक्के मकान बना रखे हैं। लेकिन यह सरकार उन मकानों का गिरवाना चाहती है। वे लोग प्रधान मंत्री श्रीमति इन्दिरा गांधी से भी मिलें हैं।

एक तरफ तो यह सरकार हरिजनों के लिए आंसू बहाती है और दूसरी तरफ गरीब हरिजनो के मकानों को, जिनको बनाये हुए आज से 50-60 साल हो गये हैं गिराने के आदे 1 जारी करती हैं। इस विशय में आप बे 1क पता कर लें, सरकार ने आर्डर जारी कर रखें हैं।

ला एन्ड आर्डर की पोजिशन के बारे में जा क्या बताऊं, उसका ता दिवाला ही निकाला हुआ है। डबवाली केस की रिपोर्ट आज हाउस के सामने आयी हुई है। आपको मालूम है कि भीला बहन के साथ किस तरह से बलात्कार किया गया। उधर बैठे भाईयों के नोटिस में मैं एक बात लाना चाहता हूँ। जब रिवासा कान्ड हुआ और उस समय रिवासा कान्ड कमेटीके जो प्रधान बने हुए थे, आज वही कांग्रेस की सरकार में मंत्री बने बैठे हैं। कांग्रेस सरकार के टाईम में पीपली, रिवासा और नगीना कान्ड हुए। उन कान्डों में जितना अत्याचार हरिजनों के साथ हुआ है वह किसी से छिपा नहीं है। आज यह सरकार हरिजनों के लिए आसूँ बहा रही है। मैं तो यह कहूँगा कि जितना अत्याचार हरिजनों के साथ हुआ है आज से पहले कभी नहीं हुआ था। हिन्दूस्तान में 32 साल तक कांग्रेस की सरकार रही। उस दौरान एक गरीब मजदूर को तीन और चार रूपये मजदूरी मिलती थी लेकिन अठ्ठाईस साल जनता पार्टी की सरकार रही उसी के दौरान हमने निर्णय किया कि कम से कम आठ या दस रूपये डेली वेजिज पर काम करने वाले मजदूर को मिलने चाहिए। (गोर) आप भ्रान्त रहें यह जनता सरकार की देन है कांग्रेस की सरकार ने तीस इक्तीस साल में हरिजनों के लिए कितनी चौपाल बनवाई। परन्तु जनता सरकार ने दो साल के अन्दर ही कांग्रेस सरकार से तीस गुना चौपाले ज्यादा बनाई है।

इसी प्रकार से जो हमारे स्वीपर भाई हैं व जो काम करते हैं उसको कोई भी दूसरा करने के लिए तैयार नहीं हैं। किसी आदमी को दो हजार रुपये भी दिये जाए तो भी वह उस काम को करने के लिए तैयार नहीं होगा। हमारी जनता पार्टी की सरकार आने के पचास उन गरीब स्वीपरो को पचास रुपये अधिक मजदूरी के दिये गए। यानि उनकी पचास रुपये महीना पे बढ़ायी।

काम के बदले अनाज की स्कीम भी हमारी सरकार की तरफ से चालू की गई थी लेकिन आज की सरकार ने उस सारी की सारी स्कीम को बन्द कर रखा है। उस स्कीम से गांव के गरीब लोगों का भी भला होता था। ओर गांव का भी सुधार हो जाता था। लेकिन यह कांग्रेस सरकार जा हरिजनों के लिए ता नौ-नौ मन के आंसू बहाती है और किसानों से हमदर्दी दिखाती है, वह इन दोनो वर्गों के लिए कुछ नहीं कर रही है।

लोहारू के किसानो ने बिजली की मांग की लेकिन उनको उसके बदले मे लाठी और गौली मिली। इसी प्रकार से कुरुक्षेत्र वि विविधालय के विधार्थियों ने मांग की थी उनको भी यही मिला। इस सरकार के हथकंडो को हमार हरिजन भाई जो इसी सरकार मे मिनिस्टर हैं, वे भी जानते हैं लेकिन अपनी कुर्सी को कायम रखने के लिए वे कुछ नहीं कहना चाहते।

अब मैं आपके द्वारा सरकार के नाटिस में यह भी लाना चाहता हूँ कि जब से कांग्रेस का राज रहा है तब से आज तक हरिजनों के लिए जो रिजर्वेशन की हुई है, वह पूरी नहीं हुई। हरिजनों के लिए बीस परसेंट कोटा मुकर्रर किया हुआ है। मुझे चार साल इस हाउस का मैम्बर बने हुए हो गये। मैंने चार साल के रिकार्ड को देखा है हरिजन दस परसेंट भी नहीं है। अगर यह सरकार हरिजनों का बीस परसेंट कोटा पूरा दिखा दिया दे तो मैं अस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। क्लास फोर को छोड़ कर किसी भी क्लास का कोटा पूरा नहीं है। क्लास फोर में भी इसलिए कोटा पूरा है कि जिस काम को हमारे बाल्मिकी भाई करते हैं, उसको कोई दूसरा करने को तैयार नहीं हैं। इसलिए उसमें वह कोटा पूरा है वरना और किसी भी जगह रिजर्वेशन पूरी नहीं है। इस सरकार ने दमदमा बना रखा है कि हरिजनों का बीस परसेंट कोटा है। मुझे इनके कामों को देख कर रोना तो बहुत आता है परन्तु इस सरकार पर हमारी बातों का कोई असर नहीं होता। (विधन) नोटिस में लाना हमारा फर्ज बनता है लेकिन काम तो सरकार ने करना है। रोहतक में चौधरी भजन लाल गये तो उनके बारे में चौधरी हर स्वरूप बूरा ने बड़ी बढा-चढा कर कर बातें कहीं। हमने भी सोचा था कि नये नये मुख्यमंत्री बने हैं, ईमानदारी से काम करेंगे और दल नहीं बदलेंगे। इन्होंने यह भी कहा कि जनसंघी भाई बड़े डिस्प्लिन के होते हैं, वे भी हमारे साथ हैं। लेकिन जब भजन लाल जी दल बदल गये जा हमने उसी वक्त अस्तीफा दे दिया क्योंकि हम तो सिद्धान्त के आदमी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रदे 1 मे भ्रष्टाचार बहुत ही ज्यादा बढता जा रहा है। एक कांग्रेसी कार्यकर्ता ने डिटेल मे हर मिनिस्टर और विधायक को पत्र लिखा है * * * * (10र) यह एक कांग्रेसी कार्यकर्ता ने हर विधायक को पत्र भेजा हुआ है। मै अपनी तरफ से नही कह रहा हूं बल्कि हर मैम्बर का पत्र आया है।

गृह मंत्री (श्री कन्हैया लाल पोसवाल): यह बात एक्सपंज होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: चेयरमैन के बारे में जो कुछ कहा गया है, वह एक्सपंज कर दिया जावे।

चौधरी जय नारायण: आप चाहे तो चिट्ठी भी पे 1 कर सकता हूं।

चौधरी राम लाल वधवा: डिप्टी स्पीकर साहब, सवाल यह है कि एक चीज लिख कर सभी मैम्बरों को दी जा चुकी है और वह किसी डिपार्टमेंट से कन्सर्न रखती है। फिर किसी चेयरमैन या किसी अफसर का भी नाम नही लिया जा रहा है तो वह एक्सपंज नही होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि जो * * * * *। यह बड़ा सिरियस मैटर है। अगर किसी डिपार्टमेंट के बारे में यह भी न कहा जाये तो फिर कैसे काम चलेंगा।

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठिए। (10र)

चौधरी राम लाल वधवा: डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। अगर हम किसी डिपार्टमेंट का यहां नाम लेते हैं और वहां पर जो कार्ड मैनेजिंग डायरेक्टर या चैयरमैन लगा हुआ है, उसके बारे में बिना नाम लिए हुए कुछ कहते हैं तो वह बात कैसे एक्सपंज हो जाएगी? ऐसा करने से तो यह प्रथा पड़ जाएगी कि हम किसी डिपार्टमेंट के बारे में बात भी नहीं कर सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: उन्होंने डिपार्टमेंट का नाम लेने के साथ-साथ पार्टिकुलरली यह भी कहा है कि वहां चैयरमैन के दामाद लगे हुए हैं।

चौधरी राम लाल वधवा: वह तो ठीक है लेकिन उन्होंने उसका नाम जो नहीं लिया। (विघ्न)

Shri Baldev Tayal: Mr. Deputy Speaker, Sir, the whole question is that suppose I want to level allegations against a person or an officer, having definite material and proof that such and such person is corrupt. What is the remedy.....

Mr. Deputy Speaker: You can give in writing.

Shri Baldev Tayal: No, Sir, there is no rule which requires that the Member should give it in writing. One alternative available is to go to the Hon. Chief Minister and bring it to his notice. But what is the other alternative we have, if we want to bring it to the notice of the House itself

that such and such man is corrupt and that such and such officer is accepting bribe?

If the allegations are vague or are of no material value, the certainly the Chair is entitled to expunge them. But if a definite allegation is levelled against a person or an officer, I think, this House is entitled to know as to who is the officer who takes bribe and is corrupt. Even in this House when allegations have been levelled against the Minister they have not been expunged. My submission to you, Sir, is only this that will be unnecessarily defending those officers or chairmen of corporations, who are corrupt, if reference3s made to them even by designation are expunged under the garb of this rule.

12 बजे

डा० मंगल सैन: इस सदन मे माननीय सदस्य ने किसी का भुभ नाम नही लिया हैं। जिस पत्र के बारे में वे कह रहे है, वह सभी एम०एल०एज० को दिया गया हैं। चीफ मिनिस्टर को दिया हैं ओर उसकी कापी प्राईम मिनिस्टर को भी भेजी गई हैं। वह कांग्रेस का वर्कर हैं। आपके पास भी पत्र आया होगा।

श्री उपाध्यक्ष: मेरे पास कोई पत्र नही आया।

डा० मंगल सैन: आपके पास आया होगा। आप अपने कागजों को देख लें।

श्रीमति सुशमा स्वराज: यह बात जो माननीय सदस्य कह रहे थे क्या आपने उसकी एक्सपंज किया है।

श्री उपाध्यक्ष: हां एक्सपंज किया हैं।

ओचित्य प्र न-

निगम/बोर्ड के सभापति या सरकार के अन्य कार्यकर्ताओं के विरुद्ध पदनाम से लगाए गए आरोपों को कार्यवाही से निकालन संबंधी।

श्रीमति सुशमा स्वराज: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। उपाध्यक्ष महोदय, कई दिनों से इस सदन में यह परम्परा चली आ रही है कि जब कोई निश्चित आरोप किसी के खिलाफ लगाए जाते हैं तो उस पर सत्ताधारी पक्ष के लोग बोलने लग जाते हैं और उसे एक्सपंज करने के लिए कहा जाता है। चेयर द्वारा भी यह कहा जाता है कि इस प्रकार के आरोप नहीं लगाने चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि यह पार्लियामेंटरी डैमोक्रेसी है। इस हाउस के अन्दर बैठने का अधिकार केवल उन्हीं लोगों को है जो जनता द्वारा चुन कर भेजे जाते हैं। मैं आप की एक बात कि जिन अधिकारीयों, कर्मचारियों या चेयरमैनो के खिलाफ किसी किस्म के निश्चित आरोप लगाये जाते हैं तो उस को सुनने के लिए उस विभाग से संबन्धित मंत्री यहां पर बैठता है। अगर इस प्रकार के आरोप नहीं लगाये जाएंगे तो फिर किसी

भी चेयरमैन या महकमें के बारे में चर्चा नहीं हो सकती क्योंकि कोई भी चेयरमैन या अधिकारी हाउस में नहीं बैठता यहां पर एक किस्म से परम्परा सी चल पड़ी है कि जब इस प्रकार की बातें कही जाती हैं तो उन्हें एक्सपंज कर दिया जाता है। मैं आप को बताना चाहती हूँ कि अगर किसी के खिलाफ आरोप लगाये जाते हैं तो उस विभाग से संबन्धित मंत्री अपना जवाब दे सकता है। इन्होंने खादी बोर्ड के चेयरमैन के बारे में कुछ बातें कही हैं। उसका नाम नहीं लिया है। खादी बोर्ड इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट के नीचे आता है। अगर किसी प्रकार की कोई गलत बात हो तो उसका जवाब इन्डस्ट्रीज मिनिस्टर दे सकजे हैं। इसलिए मैं आप से गुजारि । करती हूँ कि एक्सपंज करने की रूलिंग को आप रिकन्सिडर करें। ये भाब्द एक्सपंज नहीं होने चाहिए। मैं आप को यह भी कहना चाहती हूँ कि अगर किसी पर निश्चित तौर पर आरोप लगाये जाते हैं तो वे भाब्द एक्सपंज नहीं होने चाहिए।
This is my point of order and I want your definite fuling on it.

Mr. Duputy Speaker : I reserve my ruling and I will give it later on.

वर्ष 1981-82 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

चौधरी जयनारायण: डिप्टी स्पीकर साहब, जब सन् 1979 में चौधरी भजन लाल मुख्यमंत्री बने थे तो इन्होंने कलानौर के अन्दर 25 बैड का एक हस्पताल बनाने की घोशणा की थी उस हस्पताल को बनाये जाने के लिए पिछले साल के बजट में भी

घोशणा की गई थी। लेकिन आज तक उस हस्पताल का काम चालू नहीं हुआ और न ही उस हस्पताल को बनाये जाने के लिए कोई ईंट आदि रखी गई है। मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा था कि गुडाना और कलाना माईनर को भी भीघ्र बनवा दिया जाएगा लेकिन वहां का काम भी अभी तक नहीं हुआ है। इसी प्रकार से कलानौर के अन्दर जितनी सड़के बन रही हैं उन सब पर काम ठप्प हो गया है। इस देश के अन्दर बेरोजगारी दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। प्रदेश में काफी बेरोजगारी है इसी प्रकार से एम0आई0टी0सी0 जो खालें बनाती है, उन पर किसान अपना खर्चा माफ कराने के बारे में एजीटान कर रहे हैं। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और यह खर्चा बिल्कूल माफ करना चाहिए। मुख्यमंत्री महोदय को उनकी बातें ध्यान से सुननी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, आप ने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए आप का धन्यावाद करते हुए मैं अपना स्थान लेता हूं।

कैप्टन मांगे राम(झज्जर—अनुसूचित जाति): डिप्टी स्पीकर साहब, आज सदन में वर्ष 1981-82 के बजट पर चर्चा हो रही है। इस चर्चा पर मैं भी अपने कुछेक ख्यालात प्रकट करने के लिए खड़ा हूं। सबसे पहले तो मैं फाईनैन्स मिनिस्टर और उनके स्टाफ को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बजट को बड़ी लगन और मेहनत के साथ बनाया है, यह बजट बड़ा सराहनीय और बड़ा रंगीला है।

डिप्टी स्पीकर साहब, इस बजट के अन्दर कर्मचारियों को भी कुछ राहत दी गई है। हमारी सरकार ने सितम्बर, 1980 की महंगाई भत्ते की देय कि त भी कर्मचारियों को दी है। यह राशि 1 फरवरी के मास तक तो कर्मचारियों के जी०पी०एफ० में जमा कर दी जाएगी और मार्च से नकद भुगतान किया जाएगा। यह हमारी सरकार ने बड़ा सरहानीय काम किया है।

सतबीर सिंह मलिक जी ने जो बजट अपने समय में पेश किया था ता उसका विरोध बाबू मूल चन्द जैन जी ने और कई अन्य सदस्यों ने किया था। उसके बाद बाबू मूल चन्द जैन जी ने जो बजट पेश किया था। उसका विरोध सतबीर सिंह मलिक ने और संत कंवर जी ने किया था। उन्होंने उस बजट किसान विरोधी बजट कहा था। इनके बाद, जब से चौधरी भजन लाल जी के मुख्य मंत्री बने हैं पिछले साल लाला बलवंत राय तायल जी ने बजट का इस बार विरोधी पक्ष के सदस्यों ने विरोध प्रकट नहीं किया और न ही वाक आउट किया। इस से साफ प्रतीत होता है कि इन्होंने भी इस बजट को स्वीकार किया है।

इस बजट के अन्दर 49 करोड़ रुपये के करीब घाटा है। इस घाटे को हमारी सरकार सैन्ट्रल असिस्टैंस तथा अन्य तरीकों से पुरा करने की कोशिश करेगी।

जो बजट सतबीर सिंह मलिक जी ने पेश किया था उस के बारे जैन साहब ने तो यह कहा था कि इस बजट को

पुराने आकड़ें उठा करके रख दिया है। इसलिए मैं फाईनैंस मिनिस्टर चौधरी खुरीद अहमद और उन के स्टाफ को दोबारा मुबारिक बाद देता हूं।

बाबू मूल चन्द जैन जी ने इस बजट का हरिजन विरोधी बताया है और सतबीर सिंह जी ने इसे किसान विरोधी बजट बताया है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस बजट का न तो किसान विरोधी मानता हूं और न ही हरिजन विरोधी मानता हूं। मैं अपने सच्चे दिल से कहता हूं कि हरियाणा के अन्दर जब से चौधरी भजन लाल मुख्यमंत्री बने है, 80 प्रतिशत जातपात का जहर दूर हो गया है। यह इनकी कोशिश है कि हरियाणा के अन्दर जातपात बिल्कूल समाप्त हो जानी चाहिए।

श्री मूल चन्द जैन: थोड़ी देर पहले जब आपके पड़ोसी रिजकराम जी बोल रहे थे उस समय आप क्यों नहीं बोलें।

कैप्टन मांगे राम: प्रत्येक एम0एल0ए0 को अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है। इस बजट के अन्दर जो घाटा दिखाया गया है इसे देखकर घबराना नहीं चाहिए। हमारी सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के लिए 1800 करोड़ रुपये रखे हैं जो पहली योजना से तकरीबन तीन गुना है। इससे पहले इतना अधिक पैसा किसी भी पंचवर्षीय योजना में नहीं रखा गया है। हमारी केन्द्रीय क्षेत्र योजना 30 करोड़ 10 लाख रुपयेकी है। हमारे राज्य का 1981-82 का टैनटेटिव प्लान 290 करोड़ रुपये का है जबकि

पिछले साल यह प्लान 253 करोड़ 78 लाख रुपये का था। उससे पहले सिर्फ रसूख से सैंटर से ज्यादा पैसा लायी हैं ताकि हमारी हरियाणा स्टेट की ज्यादा तरक्की हो सके और यहां पर ज्यादा काम हो सके। हमारी स्टेट की 80 प्रति तत अबादी जो कि खेतीबाड़ी पर निर्भर करती हैं, के लिये बजट का 40 प्रति तत हिस्सा रखा गया है। मेरे इलाके के लागों की सिर्फ एक ही आवाज थी कि उनका ज्यादा बिजली दी जाये। झज्जर तहसील और साल्हावास के हल्कों में भी बिजली की कमी रही हैं पिछले दिनों बारि त भी नही हुई, थर्मल प्लान्टस भी कुछ खराबी के कारण बन्द हो गये और इंजीनियर्ज की स्ट्राईक के बावजूद चौधरी भजन लाल की सरकार ने बड़ी हो त्तियारी से काम किया और सिचुए तन का बिगड़ने से बचाया।(व्यवधान) जो फरीदाबाद और पानीपत के थर्मल प्लान्टस खराब हो गये थें, उन्हे हरियाणा स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन ओर दूसरे स्टाफ ने बड़ी फूर्ती से ठीक कर दिया इसके लिये मैं चौधरी भजन लाल जी को मुबारिकबाद देता हूं। इसके अलावा मैं चौधरी भजन लाल जी से यह दरखास्त करूंगा कि एस0वाई0एल0 के पानी का मामला भी जल्दी ही सरदार दरबारा सिंह से मिलकर सैटल कर दें ताकि बिजली और पानी की जो प्रदे त में कमी हैं, वह दूर हो सके। झज्जर और साल्हावास को इलाका ऐसा है जो सूखा है और रेतीला हैं। इस पानी आने से इस इलाके के लागो को पानी मिलेगा तो झज्जर साल्हावास नहर द्वारा चरखी दादरी के रेतीले खेतों मे भी अनाज पैदा होगा। इसलिए मैं चौधरी भजन लाल से

जी से यह रिक्वैस्ट करूंगा कि इस मामले को जल्दी से जल्दी हल करवाने की कृपा करें। एक बात और मैं अपनी सरकार से कहना चाहता हूँ कि महेन्द्रगढ़ में जिस नहर से इलैक्ट्रिसिटी चार्जिज में स्पे गल कन्सै गन दिया गया है, उसी तरह से झज्जर साउथ जाकि उतना ही रेतीला इलाका है और फ्लड इफैक्टिड एरिया है, उसको भी दिया जाना चाहिये। मैं चौधरी भजन लाल जी से यह रिक्वैस्ट करूंगा कि जिस तरह से उन्होंने यह कन्सै गन महेन्द्रगढ़ को दिया है, असी तरह से यह कन्सै गन झज्जर को भी दिया जाना चाहिये। डिप्टी स्पीकर साहब, आपको यह पता है कि झज्जर फ्लड इफैक्टिड एरिया है, वहां पर पिछली दफा 10-12 गांव पानी में डूब गये थे। जो जमीन बाढ के वक्त पानी में डूब गयी थी उसको एक्वायर करके एक भिडावास झील बनायी गयी है। जब वहां पर बाढ से तीन चार गांव तो बहुत ज्यादा अफैक्टिड हैं एक तो है चढवाना, दूसरा है खापड़वास और तीसरा मुंडाडा है। इस झील के बनाते वक्त विलेज चढवाना की जमीन एक्वायर की गयी है। चढवाना से मुंडाडा गांव को जाने वाले रास्ते पर जहां नहर कैनल और भिडावास लेक मिलती है वहां पर एक पुल बनना चाहिये। इसके अलावा खापड़वास से मातन गांव के बीच में भी पुल बनना चाहिये। इसके अलावा अहरी गांव के पास भी एक साइफन की जरूरत है। या तो वहां पर पुल बना दिये जायें या साइफन बना दिये जाये ताकि लोगों की गाड़ियां आराम से इधर उधर आ जा सकें। एक सुलोधा गांव है, वहां पर ड्रेन न0 8 के ऊपर पुल बनाना चाहिए ताकि लोगों को

आने जाने का रास्ता मिल सकें मैं इरीगे एन एण्ड पावर मिनिस्टर साहब से रिक्वैस्ट करूंगा कि व जरा इस बारे में ध्यान दें और इन्हें जल्दी से जल्दी बनवाने की कृपा करें। इससे ज्यादा मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ अभी पिछले दिनों हमारे फाईनैस मिनिस्टर चौधरी खुरीद अहमद और चीफ मिनिस्टर चौधरी भजन लाल जी हमारे झज्जर में गये थे वहाँ पर जो गेदरिंग हुई थी, उसको तो उन्होंने देख ही लिया था। वहाँ पर एक ही डिमान्ड थी कि झज्जर को इंडस्ट्रियली बैकवर्ड डिक्लेयर करवाया जाये। मुझे बेहद खुशी है कि चौधरी भजन लाल जी ने झज्जर तहसील को भी नारायणगढ़ और कालका वगैरह के साथ इंडस्ट्रियली बैकवर्ड एरिया करने के लिये भारत सरकार को रिक्वेस्ट करके केस भेजा है। मैं यह जानता हूँ कि जब चौधरी देवी लाल इस प्रदेश के मुख्य मंत्री होते थे और डा० मंगल सैन जी इण्डस्ट्रीज मिनिस्टर हुआ करते थे, उस समय भी ये लोग वहाँ पर वायदा करके आये थे कि इस तहसील को इंडस्ट्रियली बैकवर्ड डिक्लेयर करवा देंगे डाक्टर साहब ने सिर्फ यकीन ही नहीं दिलाया था कि इस तहसील को इंडस्ट्रियली बैकवर्ड कर दिया जायेगा बल्कि डिक्लेयर भी कर दिया था कि यह आज से ही हो गयी है लेकिन जब भारत सरकार को केस भेजा गया तो वहाँ से केस रिजेक्ट होकर आ गया। (व्यवधान) तब तो नहीं हुआ लेकिन अब मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि चौधरी भजन लाल जी ने जो इस तहसील को इंडस्ट्रियली बैकवर्ड डिक्लेयर करने के लिये केस भेजा है, वह सिरें चढ़ जाएंगे।

चौधरी राम लाल वधवा: केस तो हमने भी भेजा था। मन्जूर नहीं हुआ, यह अलग बात है।

कैप्टन मांगे राम: झज्जर एक बहुत बड़ा भाहर है। पुराने पालिटिक्लियंज को तो पता है कि झज्जर को जिला बनाने की मांग थी। अगर वह जिला बन जाता है तो उसमें कोसली और बहादुरगढ तहसीलें होती। जिला जो क्या बनना था लेकिन उस के कुछेक गांव निकाल कर पटोदी से मिला दिए।(विघ्न) मुझे खुशी है कि गुहला तहसील बनायी गयी है लेकिन मेरा कहना यह है कि झज्जर जिसकी भारु से जिला बनाने की मांग थी, उसमें से ये लोहारी, पाटौघा और सुलतानवाली खेडी गांव निकाले गये है, ये नहीं निकाले जाने चाहिए थे। इसके अलावा मेरी मांग यह भी है कि झज्जर के लिये कोई न कोई रेलवे लिंक दिया जाना चाहिये। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टैन्ट मांग है, वह यह है कि जा झज्जर में 24 बैडज का हस्पताल बना हुआ है, उसको 50 बैडज का बनाया जाये। इस बारे में चौधरी भजन लाल जी से ने हमें यकिन भी दिलाया था कि इसे 24 से बढ़ाकर 50 बैडज का कर दिया जायेगा। इसी तरह से झज्जर में आई0टी0आई0 और 132 के0वी0 का पावर सब स्टे न अव य बनाया जाये। जब कोसली जो कि झज्जर तहसील से कम इम्पोर्टैन्ट जगह है, वहां पर पावर सब स्टे न अव य बनाया जाना चाहिये ताकि खेतों को पानी देने के लिए और डामैस्टिक कन्जप न करने वाले लोगो को सुविधा हो सके। झज्जर दिल्ली दरवाजे, मुहल्ले में पानीकी कमी

है क्योंकि अब ऊंचाई पर है। हमारे मुख्य मंत्री और चौधरी खुरीद अहमद साहब वहां पर यह एलान करके आये थे कि पानी की समस्या कल करने के लिए 2 लाख रूपया देंगे। पता नहीं वह पैसा इन्होंने अभी तक भेजा है या नहीं?

वित्त मंत्री (चौधरी खुरीद अहमद): वह पैसा चला गया है।

कैप्टन मांगे राम: अगर चला गया है तो आप का बहुत-बहुत धन्यावाद। इसके लिये भी सरकार बधाई की पात्र है। इसके अलावा फौजियों के बारे में भी बात करना चाहता हूँ। फौजियों के बारे में गवर्नर साहब ने अपने एड्रे में भी पढा था। रोहतक के फौजियों की री-युनियन में गांव पत्र का जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि मैं आपकी बात सरकार से जरूर कहूंगा कि जिस तरह से रोहतक में डिफेंस कालोनी हैं, उसी तरह से झज्जर में भी एक डिफेंस कालोनी बनायी जानी चाहिये। मैं मुख्य मंत्री महोदय से यह अपील करूंगा कि वे इस मामले पर फौरन विचार करें और वहां पर फौजी लोगों के लिये कोई न कोई डिफेंस कालोनी बनायी जायें।

एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि 1-1-1973 से पहले जो फौजी पैन्शन पर आये हैं, उनकी पैन्शन आज रिटायर होने वाले फौजियों की पैन्शन के मुकाबले मैं बहुत कम हैं। आज जो फौजी रिटायर होता हैं, उसकी पहले से दोगुनी पैन्शन बनती

हैं। इस बारे में प्राईम मिनिस्टर साहब से हमारे मुख्य मंत्री महोदय जी ने बात करने के लिये कहा था, मुझे आता है कि वे जल्दी ही इस बारे में उनसे बात करेंगे। इसके बाद मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जिस तरह से हरिजनों और बैकवर्ड क्लासिस की फाइनेंशियली मदद करने के लिये आपने कारपोरेट एन्ज बनायी है उसी तरह से मैं यह चाहूंगा कि एक्स-सर्विसिज की भलाई के लिये भी एक कारपोरेट एन्ज बनाई जानी चाहिये। इसके लिये सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिये। डिप्टी स्पीकर साहब, रोहतक जिला फौजियों का जिला है। वहां पर बड़े-बड़े रिटायर्ड फौजी अफसर रहते हैं। तीन जनरल वहां पर है। एक तो मेजर जनरल दरियाव सिंह दूसरे है मेजर जनरल एस0एस0 कल्याण और तीसरे है लैफ्टीनैन्ट जनरल के0 के0 सिंह जिस वक्त लोक सभा के स्पीकर श्री बलराम झाखड़ वहां पर आये तो लोगों की एक ही डिमांड थी कि फौजियों के लिये एक कालोनी बननी चाहिये। इसके अलावा उनकी रिजर्व एन्ज के बारे में यह कह दिया जाता है कि सूटबल आदमी नहीं पाये गये। कई बार सरकारी अफसर कहते हैं कि हमें सूटबल आदमी नहीं मिलते। इस बारे में मैंने लिखकर भी मुख्य मंत्री महोदय को दिया है। मुझे आता है कि मुख्य मंत्री महोदय उस पर विचार करेंगे। इसके अलावा मैं फोरैस्ट का भी जिक्र करूंगा। फोरैस्ट डिपार्टमेंट को भी मैं बधाई देता हूँ कि उसने बहुत ज्यादा पौधे और सफेदे वगैरह के दरख्त लगाये हैं जो पहले कट गये थे। जो कमी थी, उसको इसने अब पूरा कर दिया है। इसी तरह से स्ट्रीट लाईट के बारे में

मैं यह कहना चाहूंगा कि गांवों में भी स्ट्रीट लाईट दी जानी चाहिये मुझे आता है कि इस बारे में सरकार लोगों की पूरी मदद करेगी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब हमारे पुराने साथी मास्टर शिव प्रसाद जी ने कहा कि बिजली है ही नहीं, ये तो थोथे खम्बे खड़े कर रखे हैं। मैं उनसे कहूंगा कि हाथ लगाकर देखो, साथ ही न लटक जाओ जो मुझे कहना। यह खम्बे चौधरी भजन लाल जी के लगाए हुए हैं जो तयारी से होथ लगाना। जरा छू कर जो देखो थोथे ही या भरे हुए हैं।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं मैडिकल कालेज हस्पताल रोहतक के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। यह एक ऐसा इंस्टीच्यूट है जहां हरियाणा से और हरियाणा के बाहर से लोग इलाज कराने के लिए आते हैं। इसके अन्दर मैडीकल इक्यूपमेंट की कमी है जिसको दूर करना बहुत जरूरी है। सरकार को मेरा सुझाव है कि इस कालेज के लिए अगर वह पच्चीस लाख रुपये का हर साल प्रोवीजन कर दे तो यह बीमारी चार साल में दूर हो सकती है और चार साल के अन्दर सारे इक्यूपमेंट खरीदे जा सकते हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, वहां पर एक मैकेनाइज्ड लांडरी की भी जल्दी से जल्दी बनाने की आवश्यकता है। इसके अलावा वहां पर पेडरियाटिक सर्जरी, बरन्ज एण्ड प्लास्टिक सर्जरी, निरी सर्जरी एंड हर्ट सर्जरी के लिए अलग अलग थिएटरज होने चाहिए। पोस्ट ओपरेटिव पेनेन्ट्स के लिए एक स्पेशल वार्ड होना चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहब, ग्लाकोज वाली बात कल भी क्वैश्चन

आवर में आई थी और आवासन दिया गया था कि वहां ग्लोकोज प्लांट लगा दिया जाएगा। मेरी प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी ग्लोकोज प्लांट लगाया जाए।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं ला एण्ड आर्डर के बारे में कहना चाहता हूँ। हमारी पुलिस का जो स्टैंडर्ड है और डिस्प्लिन हैं उस तरह का स्टैंडर्ड और डिस्प्लिन किसी और जगह की पुलिस का नहीं है। कल यहां पर कहा जा रहा था कि पुलिस की कोई जरूरत नहीं है, यह कितनी गलत बात है। कई लोग जा यहां तक कहते हैं कि फौज की कोई जरूरत नहीं है, इस तरह की बातें कैसे मानी जा सकती हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, हमें अपनी पुलिस के काम पर गर्व है। डिप्टी स्पीकर साहब, हरियाणा, पंजाब दिल्ली और महाराष्ट्र की पुलिस का मुकाबला नहीं कर सकता। जब यहां पर लोक दल का राज था जो एक दफा चौधरी भोर सिंह और परमानन्द तुली श्री जगजीवन राम को रोहतक लाए थे। वहां पर धंवन्तरी गर्ज हाई स्कूल का कोई फंक्शन था। जब श्री जगजीवन राम रोहतक बाहर से स्टेज की ओर आ रहे थे तो रास्ते में कालेज के लड़कों ने पथराव करके उनकी कार के भीने तोड़ दिये गन्दे नारे लगाये, काले झण्डे दिखाये। वे स्टेज की जगह के बाहर भागे मचा रहे थे, पुलिस ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। (व्यवधान) चौधरी भजन लाल वहां मौजूद थे। इन्होंने कहा कि इस गुण्डागर्दी के खिलाफ एक्शन लिया जाए और अगर नहीं लिया जाएगा जो मैं रिजाइन कर दूंगा (व्यवधान) मेरा कहना यह

है कि बाहर से किसी भी पार्टी का नेता आए हमको उसको सुनना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। जो आदमी भारत का रक्षा मंत्री हो जो जनता का इतना बड़ा लीडर हो, उसका सम्मान करना चाहिए लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं किया गया। अक तो इस प्रदेा में ला एण्ड आर्डर की हालत पहले से बहुत अच्छी है।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। जिन पुलिस स्टेशनों की बिल्डिंग्स की हालत खराब है और जो बिल्डिंग्स फ्लड में टूट गई थी उनकी फौरन मरम्मत करानी चाहिए। हालत यह है कि हमारे यहां के दफा 304 के मुलजिम बेरी जाते हैं क्योंकि हमारे यहां के पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग टूटी हुई है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इतना ही कहकर समाप्त करता हूँ। धन्यावाद।

चौधरी सतबीर सिंह मलिक (नौलथा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट की तुलना, एक ऐसी बदसूरत औरत से करने जा रहा हूँ जिसको फाइनेंस सैकेटरी ने बहुत अच्छी तरह से सजा करके, बिन्दी लगा कर, पाउडर लगाकर और अच्छी साड़ी पहना कर मियांजी की मारफत हाउस के अन्दर पैसा किया है। उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट को पढ़ने के बाद दो चीजें हमें मिलती हैं। इस बजट की मारफत मियांजी ने अपने पुराने साल की कारगुजारी को दर्शाया है और बताया है कि पिछले साल में उनकी क्या-क्या कारगुजारी रही है। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) उपाध्यक्ष महोदय, यह ऐसा कन्फ्युज्ड बजट है, ऐसा बजट हरियाणा और

ज्वायंट पंजाब के अन्दर कभी भी पें 1 नहीं हुआ होगा। स्पीकर साहब, इस बजट स्पीच के अन्दर ये खुद मानते हैं कि नै 1 नल प्रोडक्ट 4.5 प्रति 1त निचे आई हैं। दूसरी बात उन्होन मानी है कि पर-कैपिटा इन्कम में गिरावट आई हैं। यही नहीं इस सरकार ने यह भी माना है कि 36 प्रति 1त आबादी गरीबी की रेखा से निचे हैं। स्पीकर साहब, 36 प्रति 1त लोग कौन हैं? ये वे लोग हैं जिनको दो वक्त की रोटी नहीं मिलती, जिनको कपड़ा नहीं मिलता। इस सरकार ने यह भी माना है कि रेट आफ इन्फले 1न बढ़ा हैं। फिर यह सरकार और खास तौर पर बूरा साहब कहते हैं कि यह बड़ा प्रोग्रेसिव बजट है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब इन्फले 1न बढ़ा हो, पर-कैपिटा इन्कम घटी हो, 36 परसेन्ट लोग पावर्टी लाईन से नीचे हों, ऐसी हालत में भी उस बजट को प्रोग्रेसिव बजट कहा जाए। इसका मतलब है कि इनको पता ही नहीं हैं कि यह सिलसिला क्या बनने जा रहा है ओर बजट होता क्या है और यह सरकार क्या करने जा रही है। इस बजट स्पीच की मारफर इस सरकार को वायदों की सरकार बनाया जा रहा हैं। सरकार कह रही है कि हम यह करेंगे हम फलां चीज करेंगे (1ोर एव व्यवधान)। स्पीकर साहब, इन्होन कहा है कि मेवात में डिसपैनसरिज़ खोलेंगे। डिस्पैन्सरिज़ खोलन से किसी स्टेट की डिवैन्पमेंट नहीं हो सकती हैं। डिवैन्पमेंट तो जो तीन-चार चीजें ऊपर कहीं है, उनको दूर करने से होती हैं। स्पीकर साहब, पिछली सरकार की कुछ नितियां जिनमें गरीबों का भला हो सकता था, वे इस सरकार ने छोड़ दी हैं। मैचिंग ग्रांट की स्कीम को हरियाणा

के अन्दर हमारी सरकार ने भुरु किया था। उस स्कीम से यह फायदा था कि देहात के जो लोग डिवैल्पमेंट चाहते थे वे मैचिंग ग्रांट लेकर अपने इलाके भी डिवैल्पमेंट कर लेते थे। जब से चौधरी भजन लाल की सरकार आई है उसने वह स्कीम छोड़ दी हैं। हमारी सरकार के वक्त में जो लोगों ने मैचिंग ग्रांट के लिए पैसा दिया था वह भी हज्म हो गया है। स्पीकर साहब, क्या इसी को प्रोग्रेसिव बजट कहते हैं, क्या इसी से गरीबों की गरीबी दूर हो करेगें? हमारे वक्त में फूड फार वर्क की स्कीम चालू थी। उससे यह फायदा था कि गरीब लोगों को खाने के लिए अनाज भी मिल जाता था और देहात की डिवैल्पमेंट भी हो जाती थी। जब से चौधरी भजन लाल की सरकार कुर्सी पर आई है इसने एक किलो गेहू भी फूड फार वर्क के लिए नहीं किया।

स्पीकर साहब, इससे आगे अब मैं डेयरी डिवैल्पमेंट स्कीम के बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने दो करोड़ रूपया इस स्कीम के लिए रखा था कि इस राशि से छोटे-छोटे यूनिट्स स्थापित किए जाएंगे लेकिन भजन लाल की की सरकार आने पर इस स्कीम पर बिल्कूल पानी फेर दिया गया। इस स्कीम को बन्द कर दिया गया। इसका असर यह हुआ कि जिन लड़को ने इस के लिए ट्रेनिंग ली थी, वे बेचारे मारे-मारे फिर रहे हैं और उनको नोकरियां भी नहीं दी गई। जब बैंको से लोन की बात आती है तो यह कहते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है। असल बात तो यह है कि चे जो बैंकस है, ये देहाती लोगों को पैसा देना

चाहते ही नहीं। हमने स्पीकर साहब, पहले एक प्रोपोजल रखी थी कि यह जो कोओप्रेटिव बैंक और लैंड मार्टगेज बैंक है इनको देहात के लोगों को कर्जा देना चाहिए। इस बारे में एक कमेटी मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में हमने बनाई थी और उसमें यह निर्णय लिया गया था कि देहाती बैंको को और फायनेन्स किया जाए और इन दोनों बैंक बना दिया जाए। जो अन-एम्पलायड लोग हैं, उनको इसके नौकरियां दी जाए। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि उस में चौधरी भजन लाल भी थे लेकिन इन्होंने इस तरफ किसी प्रकार को ध्यान नहीं दिया। यह कहा जा सकता कि इन कामों के लिए, उनके पास समय नहीं है वे तो इन ***** की तरफ ही, जो यहां पर बैठे हैं ध्यान दे रहे हैं, देहात के लोगों की कठिनाई को देखने के लिए उनके पास समय नहीं है। (गौर एवं व्यवधान)

लोक निर्माण राज्य मंत्री (श्रीमति भाकुन्तला भगवाड़िया):

स्पीकर साहब, मैम्बर साहब, इधर बैठने वाले सभी आनरेबल मैम्बरज मैम्बरज को ***** कह रहे हैं, यह उनका भाग नहीं देता। यह भावद एक्सपेंज होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: यह लफ्ज एक्सपेंज किया जाए।

चौधरी सतबीर सिंह मलिक: स्पीकर साहब, इस सरकार ने बजट स्पीच में इस बात का इतारा किया है कि वे क्राप इं गोरैन्स करेंगे लेकिन इसके बजट में कोई पैसा निर्धारित नहीं

किया गया है। कब करेंगे कहां से करेंगे, इस बारे में कुछ नहीं बताया गया है। यह भी नहीं बताया कि क्या इसकी रूपरेखा होगी और कब वह तैयार होगी। हमारी सरकार जो इस बारे में पूरी तरह से जागरूक थी कि किसानों की आप की इं गोरेंस करेंगे लेकिन अब मीयां जी ने अपनी बजट स्पीच के अन्दर कहीं कोई इ ारा नहीं दिया कि हम कहां से क्राप इं गोरेंस करेंगे।

जिस वक्त हमारी सरकार थी, तब एक कमेटी बनायी गयी थी। चौधरी भजन लाल, ब्रिगेडियर रण सिंह और मैं, उस कमेटी के मँबर थे। उस वक्त यह फैसला किया गया था कि हम किसानों से एक रूपया पर एकड। के हिसाब से क्राप इं गोरेंस का जमा करवाएंगे ओर अब इस सरकार ने यह किया है कि 20 रूपये प्रति एकड के हिसाब से किसानो से क्राप इन्सोरेंस का जमा करवाया जाएगा। इन्होंने जो 49 करोड़ रूपये का घाटा दिखाया है उसको इसी तरह से किसानों से जजिया के रूप में लेकर पूरा करेंगे (गोर ओर व्यवधान) स्पीकर साहब, ये कहते है कि हमारी सरकार किसानों की भलाई के लिये हैं किसानों की हितकारी है। मैं तो यह कहता हूं कि यह सरकार किसान विरोधी सरकार है, किसानों को मारने पर तुली हुई है।

स्पीकर साहब, अब मैं कुछेक बातें बिजली के बारे में भी कहना चाहता हूं। आज हरियाणा के अन्दर बिजली की समस्या बड़ी भारी समस्या का रूप धारण किये हुए हैं। किसानों को केवल दो घण्टे ही ट्यूबवैलो के लिये बिजली मिलती है और गरीब

किसानों का इसके बदले में, लाईन का खर्चा, मीटर का खर्चा, मीटर रिडिंग का खर्चा बिल के रूप में यूर्हीं फालतू भरना पड़ता हैं जो कि एक किस्म का उसके ऊपर बोझा है। स्पीकर साहब, जो सरकार गरीब किसानों को बिजली मुहैया नहीं कर सकती, उसको किसानों से बिलों की रिकवरी करने का भी कोई हक नहीं हैं।

स्पीकर साहब, इससे आगे मैं इस सरकार के कारनामों की चर्चा करना चाहता हूं। पिछले दिनों इस सरकार ने किसान रैलीके नाम से एक पाखण्ड रचाया था। स्पीकर साहब, आपको याद होगा कि एक किसान रैली पहलै भी हुई थीं। उस रैली में लोग अपने घरों से खर्चा करके भामिल होने के लिए आये थे। इस सरकार ने क्या किया? पटवारीयों और बी०डी०औ० की इस काम के लिये डियूटी लगाई गई कि आप आदमी इक्ट्ठे करके भेजो। स्पीकर साहब, ऐसा ही हुआ, लोगों को घरों से जबरदस्ती निकाल कर दिल्ली भेजा गया और लोगों के ट्रकों का जबरदस्ती इस्तेमाल किया गया। यह एक किस्म की किसानों के नाम से क्राफ्तान थी जो इस सरकार ने भी है और गरीब किसानों को हर प्रकार से एक्सप्लायट किया हैं (गौर एवं व्यवधान) स्पीकर साहब, यह सरकार तो किसानों का खून कर रही हैं यह किसान विरोधी सरकार हैं (गौर एवं व्यवधान) जो जो कारनामे इस सरकार ने किये हैं, उन्को ब्यान नहीं किया जा सकता।

स्पीकर साहब, क्र० 1 न जो इस सरकार ने जगह जगह पर पहुंचा दी है। जो ईमानदार अफसर थे, उनको भी इस सरकार ने बेईमान बना दिया है। अफसर सच्चे दिल से, ईमानदारी से इस प्रान्त की सेवा करना चाहते हैं लेकिन इस सरकार ने उन्हें क्र० 1 के रास्ते पर ला कर खडा कर दिया है। इस सरकार ने उन्हें मजबूर किया कि वे क्र० 1 बनें। एक पानीपत का उच्च आधिकारी है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। उसको इसक बात के लिए मजबूर कर दिया गया कि वह 10 हजार रूपया चीफ मिनिस्टर के सचिवालय के, नम्बर दो के आदमी को दें। मैंने उस आदमी को कहो कि आप तो बड़े ईमानदार आदमी थे, आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? तो वे कहने लगे कि मैं टैलीफोन पर नहीं बता सकता, मैं भाम को आपके घर आकर बताऊंगा। उसने ट्रांसफर के लिये ऐप्लीके 1 न दी कि मेरी ट्रांसफर कर दी जाए, मैं इस काम के लिए धन इकठ्ठा नहीं कर सकता लेकिन उसकी ट्रांसफर भी नहीं की गयी। वह कहने लगा कि जब सरकार मुझे खुद ही क्ररने पर तुली हुई है तो फिर मैं भी अपने हाथ क्यों न धो लूँ? इस प्रकार स्पीकर साहब, वह ईमानदार अफसर भी इस सरकार के राज मे क्र० 1 हो गया।(1 म भोम की आवाजें आईं)

मुख्यमंत्री (चौधरी भजन लाल): आप नाम जो बता दो कि वह कौन अफसर है? (1 म एव व्यवधान)

चौधरी सतबीर सिंह मलिक: स्पीकर साहब, वह पानीपत का सब-डिविजन का सब से बडा अधिकारी है। इससे ज्यादा मैं

और नहीं कहना चाहता। (गोर एव व्यवधान) इस सरकार ने एक ईमानदार अफसर को खुद दबाव डाल कर क्रुप्ट किया है। इस सरकार के राज में किसी ईमानदार अफसर को ईमानदार नहीं रहने दिया जाता।

इसके बाद स्पीकर साहब, मैं बताना चाहता हूँ कि मियां जी ने अपने बजट में 50 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया है। मेरी समझ में नहीं आता कि ये इस घाटे को कैसे पूरा करना चाहते हैं। 12 करोड़ रुपये के लगभग तो ये सरकारी नोकरियों में लगे हुए कर्मचारियों को निकालने से करेंगे। एक तरफ तो ये अन-इम्प्लायमेंट की बात करते हैं और दूसरी तरफ रिट्रैन्चमेंट करने पर तुले हुए हैं। इस सरकार के लिए यह बड़ी भार्म की बात है। जो देहाती लोग पढ़े-लिखे लोग हैं, अपनी खुान पसीने की कमाई कर रहे हैं, उनके लिये इस सरकार के पास कोई समाधान नहीं है। दूसरी तरफ इन्होंने जातिपाति के आधार पर बिना नोईयो की जाकि राजस्थान से हैं, यू0पी0 से है, 50 परसेन्ट सरकारी नौकरीयों में भर्ती की गयी है। देहातो में रहने वाल जो अन-इम्प्लायड लोग है, उनकी प्रोबलम साल्व करने में ये बिल्कूल असमर्थ रहे हैं। (गोर एव व्यवधान) मैं मियां जी को कहना चाहता हूँ कि ये जो आपकी कारपोरै इन घाटे में चल रही है, आखिर कब तक इन को अपने पावों पर खड़ा करने की कोशिश करते रहोगे? अगर वही कारपोरै इन आज प्राईवेट सैक्टर में होती तो करोड़ों रुपये को मुनाफा कमाती। अब जो यह सरकार घाटे में

चल रही हैं, यह घाटा सरकार को न होता। इस घाटे को दूर करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि इन सभी कारपोरेशन के हैड क्वार्टर चण्डीगढ़ की बजाये हरियाणा में बनाये जाएं। वहां जोन से कैपिटल अलाउंस खर्चा बचेगा। इसके अलावा हरियाणा के लडको को नौकरियां भी मिलेगी। इस समय कोर्पोरेशन में 90 प्रतिशत लोग पंजाब, हिमाचल और दूसरे प्रदेशों के लगते हैं क्योंकि इनमें जो अफसर हैं वे कहीं पर अपने भाई को, कहीं पर अपने भतीजे को या और रिश्तेदारों को लगा देते हैं। आपको हैरानी होगी, मैं मिसाल दे सकता हूँ कि एक एक खानदान के दस दस आदमी लगे हुए हैं जो इन अफसरों के रिश्तेदार हैं। इस तरह से हरियाणा के पैसे के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पैसा तो हरियाणा का है और नौकरियां दूसरे प्रान्तों के लोगों को दी जा रही हैं। अगर इन कोर्पोरेशन के हैडक्वार्टर हरियाणा में जाएंगे तो आपके सेल्ज टैक्स की भी बढ़ोतरी होगी, और वहां पर लोगों के मकान भी किराए पर चढ़ेंगे जिससे उनको भी कुछ आमदनी होगी। ऐसा करने से जो आप यहाँ पर कैपिटल अलाउंस देते हो वे भी बन्द हो जाएंगे। अगर आप घाटा पूरा करना चाहते हैं, तो जो दूसरे प्रान्तों के लोग लगे हुए हैं उनको निकाल कर करें। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमने हिसार के अन्दर एक बिजली बोर्ड की कालोनी बनाई थी और हां ये रिफिट करने के आर्डर भी कर दिये थे लेकिन अब उस कालोनी को बेचा जा रहा है। ये कहते हैं कि हम पंचकूला के अन्दर नई कालोनी बनाएंगे। फिर यह कहते हैं कि पीछे जो बिजली

की कमी हुई वह बिजली कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से हुई। मैं मुख्य मंत्री को उनसे बात करनी चाहिए थी तथा उनकी दिक्कत को दूर करना चाहिए था। अगर मुख्य मंत्री साहब उनकी बात सुनते तो यह बिजली को नुकसान न होता। जब हम सरकार में थे तो उस वक्त भी बिजली कम थी, हमने पानीपत का थर्मल प्लांट चलाया। उस वक्त किसानों को 24 घण्टे बिजली मिलती थी, लेकिन आज नहीं मिल रही है। इसका कारण यह है कि किसान रैली के नाम पर जो ढकोसला हुआ, उसके नाम पर करोड़ों रूपया इन्डस्ट्रियलिस्ट्स से लिया गया है। पानीपत के अन्दर एक राइस भौलर है, सारे देहात की बिजली काट कर उसको दे दी गई है। हमने एक्सीशन और डी० सी० को इस बारे में जानकारी दी तो उन्होंने कहा कि आगे से ठिक कर देंगे। (विघ्न) मांगे राम जी नये नये वजीर बने है ये भी ऐसे काम करने लगे हैं। (गोर) यही नहीं उससे पहले हरि सिंह नलवा एम० पी० और कुछ दूसरे अधिकारी राइस भौलर के मालिक के यहां जाकर खाना भी खाकर आए हैं। एम० पी० और सरकार के वजीर उस राइस भौलर के घर जाएं और देहातों की बिजली काट कर उसको दें, यह कहां का इन्साफ है। करोड़ों रूपये लेकर इन्होंने हरियाणा के किसानों को बेच दिया।

श्री अध्यक्ष: मलिक साहब, अब आप वाइंड-अप करें।

चौधरी सतबी सिंह मलिक: स्पीकर साहब, मैं वाइंड-अप ही करने जा रहा हूं। स्पीकर साहब, बदरपुर पावर हाउस में

हरियाणा का 33 प्रति अत हिस्सा है लेकिन इनको वहां से 9 प्रति अत से ज्यादा बिजली नहीं मिल रही है। हमारे वक्त में वहां से पूरी 33 प्रति अत बिजली मिला करती थीं इन्होंने दुर्गा को खुा करने के लिये दिल्ली को बिजली दे दी। ऐसा करके इस सरकार ने हरियाणा के साथ गददारी की है। किसानों की हमदर्दी की बात मियां साहब भी करते हैं और मुख्य मंत्री जी तो करते ही हैं। ये जब भी देहात में जाते हैं तो कहते हैं कि मैं जाट हूं और जब मेवात में जाते हैं तो कहते हैं कि मैं मुस्लमान हूं। (गोर) एक तरफ तो ये किसानों की बात करते हैं और दूसरी तरफ लोहारू के अन्दर किसानों के ऊपर गोली चली। वहां के किसान यही चाहते थे कि हमें बिजली और पानी मिले। पानी का तो जिस दिन से भजन लाल की सरकार बनी है इन्होंने भट्ठा बिठा दिया है। जो नहरे इन्होंने पक्की करवाई है, आज उनमें गीदड़ बिया रहे हैं। यह सरकार किसान विरोधी सरकार है। भाई खुर गीद ने एक काम जरूर अच्छा किया है कि इन्होंने मेवात बोर्ड बनाया। बड़ी खु गी की बात है। मैंने भी वह इलाका देखा है और वहां की खु गीहाली के लिये ऐसा जरूर होना चाहिए था। लेकिन स्पीकर साहब, महेन्द्रगढ़, झज्जर, दादरी और लोहारू के इलाकों की आज भी बदतर हालत है। आज अगर ये डिवलपमेंट करने की बात करते हैं तो इनको ऐसी सब जगहों पर ऐसे बोर्ड बनाने चाहिए थे और सभी जगहों को खु गीहाल करना चाहिए था। स्पीकर साहब, मैं कुछेक बातें और कहना चाहता हूं। हमारे मुख्य मंत्री जी बड़े कल्चर्ड आदमी हैं ओ कल्चरल प्रोग्रामों में काफी

दिलचस्पी लेते हैं। लेकिन पता नहीं इन्होंने बजट में कल्चरल प्रोग्रामों के लिए पैसा क्यों नहीं रखा? या तो ये सम्मेलितरी डिमांड के जरिये बाद में पैसा लेंगे या इनके पास कोई दूसरा ढंग होगा। जैसे खुरीद भाई बता रहे थे कि हमारे मुख्य मंत्री के हाथ में ऐसी रेखा है कि चारों तरफ से पैसा बरसता है। इसलिए हो सकता है कि कल्चरल प्रोग्रामों के लिये पैसा देने का इनके पास कोई दूसरा रास्ता हो। मैं हाउस में एक बात बताना चाहता हूँ कि चौधरी भजन लाल जी जब से चीफ मिनिस्टर बने हैं, तब से ये किसी जाति विशेष के अधिकारियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। उनकी कन्फिडेंसियल रिपोर्ट्स को ये जान बूझ कर खराब करवा रहे हैं। यही नहीं यह भी बर्दाश्त हो जाता लेकिन हमारे एम0एल0ए0 पोजलू साहब, जिसको सस्पेंड किया हुआ है। उनको मुख्य मंत्री ने अपने दफतर के अन्दर कहा कि अगर ज्यादा बात करेगा तो मैं बिनाई हूँ और तुम्हें बिनाईओ से गोली से मरवा दूंगा।(गोर)

चौधरी बीनेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मेरा प्वांचट आफ आर्डर है। स्पीकर साहब, इन्होंने किसी विशेष जाति का कौन से ठेका लिया हुआ है। ये उस जाति के कौन से ठेकेदार है? ये बे-बुनियाद बात कर रहे हैं। मैं उस समय मौजूद था, ये बिल्कूल गलत बात कह रहे हैं।(गोर)

चौधरी सतबीर सिंह मलिक: स्पीकर साहब, अगर ये बिनाई होकर ऐसा काम कर सकते हैं तो हमारी जाटनीयां बांझ

नहीं हो गई थी उन्होंने भी बहुत से जाट बेटे पैदा किये हुए हैं। अगर आपने किसी एम0एल0ए0 के ऊपर कोई ज्यादाती करने की कोशिश की तो बदला लिया जाएगा। अगर इस तरह से किसी एम0एल0ए0 को थ्रेट दिया जाएगा और उसके खिलाफ गलत केसिज़ दर्ज करवाये जाएंगे तो इनके हक में अच्छा नहीं होगा। डेमोक्रेसी के अन्दर इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज़ वाईड—अप।

चौधरी सतबीर सिंह मलिक: स्पीकर साहब, भजन लाल सरकार जब से बनी है तब से सारे हरियाणा में कांड पर कांड हो रहे हैं। यह कांडों की सरकार है और इसका जन्म भी कांडो से ही हुआ है। इस सरकार के भासनकाल में जितने कांड हुए हैं उतने कभी नहीं हुए, हिन्दुस्तान की हिस्ट्री में यह एक मिसाल है। कहीं कालावाली का भाराब कांड और कहीं कुरुक्षेत्र कांड स्पीकर साहब, क्या क्या गिनाऊ, जितने कांड इस सरकार के टाईम में हुए हैं, उतने पहले कभी नहीं हुए, आप बैठे एक हिस्ट्री उठाकर देख लें। (व्यवधान) स्पीकर साहब, होम मिनिस्टर साहब ने एक सवाल के उत्तर में कहा था कि इस साल 103 केसिज़ रीप हुए हुए हैं। (व्यवधान) इन्होंने खुद फिगर दी थी। मेरे कहने का मजलब यह है कि प्रदेश में ला एंड आर्डर की हालत बहुत खराब है। (घंटी)

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जाइए, अब श्री ई वर सिंह बोलेंगे।

चौधरी सतबीर सिंह मलिक : आप मुझे एक मिनट ओर दे दें। मैं एक मिनट के अन्दर खत्म कर दूंगा।(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं आप बैठ जाईए। अब चौधरी ई वर सिंह बोलेंगे।(व्यवधान)

चौधरी ई वर सिंह(गुलहा-अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब, 16 मार्च को हमारे वित्त मन्त्री चौधरी खुरीद अहमद ने जो बजट सदन में पेश किया, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। स्पीकर साहब, यह बजट हरियाणा के इतिहास में पहला बजट है, जिस में समाज के नकारा और पिछड़े हुए वर्ग को ऊपर उठाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे रखा है। यह सदियों से पिछड़ा हुआ और लताड़ा हुआ वर्ग है, आज तक इसकी ओर किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया था। इतना अच्छा बजट होने के बावजूद भी लोक दल के भाई अखबारों में ब्यान देते हैं कि हरिजन मरवा दिये, इस सरकार ने हरिजनों का भला नहीं सोया, यह कर दिया, वह कर दिया। आप सब भाई जानते हैं कि बजट में हरिजनों के लिए कितना प्रोवीजन किया है। जो कुछ इस सरकार ने किया है उसको सारी दुनियां जानती हैं और सराहना कर रही हैं। लेकिन ओपोजिशन में बैठे हुए लोक दल के भाई बजट में अच्छी बातों को नजरअन्दाज करने की कोशिश करते हैं। मैं इन्हे बता देना चाहता हूँ कि जनता की नजरे बड़ी तीखी है, उसको धोखा देना इतना आसान नहीं, जितना ये समझते हैं।
(व्यवधान)

चौधरी सन्त कंवर: आप चौधरी चांद राम और जगजीवन दोनो को ही धोखा दे गये है।(व्यवधान)

Mr. Speaker: No interruptions Please.

चौधरी ई वर सिंह: स्पीकर साहब, जब मलिक साहब बोल रहे थे तो इन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि बजट हरिजन विरोधी बजट है। ये ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि जब चे मन्त्रिमण्डल में थे और फाईनैस मिनिस्टर थें तो हरिजनों के लिए बजट में फण्डज एलोकेट करने तो अलग रहे, इनके दरबार में आये हुए हरिजनो इनके कमरे में घुस भी नहीं सकते थें। ये हरिजनों से इतनी नफरत करते थें।(व्यवधान)

श्री कंवल सिंह: आपको हर रोज इनकी कोठी पर देखा जाता था। (व्यवधान)

चौधरी उदय सिंह दलाल: ये तो वही चक्कर लगाया करते थे। (व्यवधान)

चौधरी ई वर सिंह: दलाल साहब, आप क्या बात करते हैं, आप तो सर्विस से डिसमिस होकर आये थे। (व्यवधान एव भाोर)

Mr. Speaker: No interruptions please.

वैयक्तिक स्पष्टीकरण

चौधरी उदय सिंह दलाल द्वारा

चौधरी उदय सिंह दलाल: आन ए प्वायंट आफ एक्सप्लेनेशन। (व्यवधान) स्पीकर साहब, श्री ई वर सिंह जी मेरे भाई है, मेरे अजीज हैं मैं इन्हें बताना चाहता हूँ कि इन्हे मेरे खिलाफ एक गलतफहमी हो गई है। इन्हे ही नहीं, कई भाई गलतफहमी के शिकार हो रहे हैं। (व्यवधान) मैं हिसार में सर्विस करता था और बा-इज्जत सर्विस छोड़ कर आया था। अगर किसी को डाउट हो तो मैं चैलेंज करता अगर बा-इज्जत ना छोड़ कर आया हूँगा तो मैं अस्तीफा दे दूँगा। अगर ये साबित कर देगे कि मैं डिसमिस होकर आया हूँ तो मैं अस्तीफा दे दूँगा अगर नहीं साबित कर सके तो ये अस्तीफा दे दे। (व्यवधान) इनको बात सोच कर कहनी चाहिए। जब ये हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन थे तो * * * * *

*

Finance Minister (Chaudhri Khurshid Ahmed):

These words should be expunged as they are not relevant.

श्री अध्यक्ष: मकान वाली बात रिकार्ड न की जाए। (व्यवधान)

चौधरी ई वर सिंह: स्पीकर साहब, मैं इनके चैलेंज को एक्सप्लेनेट करता हूँ, जो जो बातें इन्होंने कही हैं, मैं एक एक का एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ। (व्यवधान)

चौधरी उदय सिंह दलाल: स्पीकर साहब, ये साबित कर दें अगर मुझे काई सजा हुई हो।(व्यवधान एवं भाोर)

वर्ष 1981-82 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्ष: ई वर सिंह जी, आप बजट पर बोलें।(व्यवधान) दलाल साहब, आप इन्द्र न करें और कोई पर्सनल बात न करें।(व्यवधान)

चौधरी ई वर सिंह: मै बजट पर ही बोलूगा। स्पीकर साहब, सरकार ने हरिजन कल्याण निगम के लिए पिछले साल की निस्बत इस साल 5 करोड़ रूपया और बढा दिया। यह हिन्दुस्तान की पहली स्टेट सरकार हैं, जिसने हरिजनो का इतना ध्यान रखा है और इसकी मिसाल सारे हिन्दुस्तान मे कही नही मिलेतीं। यह हरिजनों की हितकर और वफादार सरकार है जिसन पिछडी जातियों के लिए निगम बना दिया। सरकार चाहती है कि छोटे छोटे नगरो में जो छोटे दुकानदार और मजदूर काम करते हैं, उनका किसी न किसी तरह से भला हो और हर आदमी को अपने अपने फिल्ड मे तरक्की करके, अपना कर्तव्य निभाने का मौका मिले। सरकार ने इनके लिए बिजली को प्रबन्ध कर दिया है। सरप्लस जमीन का बटवारा करने के लिए यह सरकार दृढ संकल्प हैं। यह पिछली सरकार है जिसने 31 मार्च तक सारी सरप्लस जमीन, जिसको पिछली सरकार आज तक बांट नही सकी, उसको

बाटने को फ़ैसला ही नहीं किया बल्कि ऐलान किया है कि 31 मार्च तक फिजीकली कब्जे भी दे दिये जायेंगे सरकार ने हरिजनो के लिए बिजली का पर्याप्त प्रबन्ध किया है और सरकार की नीती है कि पिछड़े वर्ग को बिजली की कमी के कारण कोई नुकसान न हो। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से एक बात माननीय सदस्यों के नोटिस में लाना चाहता हूँ कि सरकार ने हरिजनो को मकान देने के लिए 20 परसेन्ट कोटा अलाट कर दिया है। जिस हरिजन भाई को मकान की जरूरत है वह बुकिंग करवा सकता है और यह बुकिंग छः महिने तक खुली रहेगी। इस दौरान किसी वक्त भी हरिजन मकान के लिए या जमीन लेने के लिए बुकिंग करवा सकता है। सरकार ने हरिजनों के लिए 8,000 मकान बनाने के लिए आवासन दिया है। आत अपोजी उन मे बैठे हुए लोक दल के भाई नारा लगाते है कि गरीब हरिजनो के लिए बजट में कुछ नहीं रखा है। मैं इन्हे बता देना चाहता हूँ कि पहले व अपने दिल को टटोल कर सोचे कि जिस वक्त उनकी सरकार थी और वे मिनिस्टरी मे थे उस वक्त इनको हरिजनो की भलाई करने का वक्त मिला था तो वे हरिजनों के कितने वफादार थे और हरिजनो के लिए इन्होने कितने मकान बनाये थे? क्या उस वक्त मकान नहीं बन सकते थे? जिस वक्त इन्होने बजट बनाया था क्या उस वक्त हरिजनों के मकान बनाने के लिए प्रोविजन नहीं रख सकते थे। स्पीकर साहब, इस सरकार ने यही नहीं किया, जो व्यक्ति आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए है, उनके लिए सरकार निगम बना रही है। ये चीजे बताती है कि सरकार पिछड़े वर्ग के लिए और गरीबों के

लिए कितनी वफादार हैं। स्पीकर साहब, हुड्डा द्वारा जहां तक प्लाट अलाट करने को संबंध है, इसमें छोटी सी भूल हो गई है। मैं मुख्य मंत्री जी से अपील करूंगा कि 20 परसेंट का कोटा तो संवैधानिक रूप से हरिजनों के लिए है ही लेकिन अगर इसे 30 परसेंट कर दिया जाए तो दुसरे गरीब लोग भी इस सहूलियत से मैक्सिमम फायदा उठा सकेंगे। आज तक जिस आदमी को समाज ने लताड़ दिया था। जिसकी भलाई किसी सरकार ने कोई बात नहीं सोची थी, उसको ऊपर उठाने के लिए इस सरकार ने समुचित कदम उठाये हैं।

13.00 बजें

स्पीकर साहब, इसके बाद मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अन्धे, लंगड़े और लूले लोगों के लिए, जिनका कोई सहारा नहीं, जो अपंग है, उनके लिए बजट के कुछ न कुछ प्रोविजन रखा जाना चाहिए था। मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि जो आदमी 50 वर्ष की उमर से ऊपर के है, जिनका कोई सहारा नहीं, औलाद नहीं, उनके लिए इन्हे 50 या 100 रुपये की पेंशन मुकर्रर कर देनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो मैं समझता हूं कि यह इस बजट का बहुत ही प्रसिनीय पहलू होगा।

अढाई सौ आदमीयों की आबादी वाले गांव मे सड़क का पहुचना, बिजली का होना और स्कूल का बनना काबिले तारिफ काम हैं। मेरा हल्का जो सदियों से पिछड़ा हुआ था और जहां

केवल सात स्कूल थे वहां अब 13 साल के बाद 9 स्कूल अपग्रेड हुए हैं। 13 साल में वहां कोई स्कूल अपग्रेड नहीं हुआ था। यह चौधरी भजन लाल जी की सरकार है जिसने इस तरह के पिछड़े हुए इलाके की तरफ भी ध्यान दिया है। बोर्डर से लगते हुए इस इलाके में सब-डिविजन बनाना, 132 कै0वी0 का बिजली घर बनाना और 'हैफेड' द्वारा भौलर लगाया जाना इस प्रकार का पिछड़े हुए इलाके ओर गरीब लोगों के साथ हमदर्दी को एक नमूना है। यही नहीं वही 30 बैड का एक हस्पताल भी बनाया जा रहा है। मेरे ख्याल में इस सरकार के दिल से कोई भी पिछड़ा हुआ इलाका छुपा हुआ नहीं है। (विघ्न) स्पीकर साहब, केवल जात का नार लगा कर कोई सरकार चल नहीं सकती। हम तो समानता चाहते हैं। चौधरी देवी लाल जी जब मुख्य मंत्री थे तो क्लकसे लेकर हैड क्लैक तक के एस0एस0बोर्ड से जो भी कर्मचारी लगे वे एक ही जात से एक ही वर्ग से लिए गए। (विघ्न) उस समय हरिजनो का कोटा पूरा नहीं हुआ। मैं मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे अब को कोटा तो पूरा करेंगे ही लेकिन पिछला कोटा भी पूरा करने की कृपा करें। स्पीकर साहब, हरिजन एक ऐसी जमात है जिसको सदियों से पिछड़ा रखा गया है हालांकि इस जमात के लोगों ने बड़ी-बड़ी कुरबानियां दी है। गुरु गोबिन्द सिंह जी से लेकर अब तक का इतिहास अगर हम देखे तो पांच प्यारे जो भाहीद हुए उनमें भी हरिजन थे। डा0 अम्बेदकर जिन्होंने भारत का सविधान बनाया, वे भी हरिजन थे। (विघ्न) मैं मलिक हरिजनों के लिए कितना प्रोविजन किया था? स्पीकर साहब, पोहलू

साहब के बारे में एक बार मेरे हल्के के अन्दर वे गए और इन्होंने हरिजनों को गालियों दी। (गोर) इस बिनाह पर उनके विरुद्ध दफा 376 का मुकदमा दायर हुआ था जो कि रिकार्ड की बात है (गोर)

डा० मंगल सैन: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहब, ये दल बदलू यहां दफा 376 के मुकदमें का जिक्र कर रहे हैं। क्या यह बात ठीक है?

Mr. Speaker: I did not hear what he has said. If there is anything objectionable I will expunge it.

चौधरी ई वर सिंह: स्पीकर साहब यह तो रिकार्ड की बात है। डा० साहब को हम इसलिए कुछ नहीं कहते क्योंकि हम सोचते हैं कि हम तो नए आए हैं और य काफी पुराने सदस्य हैं। लेकिन डा० साहब जब भी खड़े होते हैं तो दल बदल की बात करते हैं। क्या डा० साहब मुझे बताएंगे कि उन्होंने दल नहीं बदला है? क्या ये अब उसी पार्टी में हैं जिसमें पहले थे। इन्हें सोच कर बात करनी चाहिए।

डा० मंगल सैन: हम जहां थे वही आज हैं। हमने न चौधरी चांद राम जी को छोड़ा है और न किसी और से दगा किया है। (गोर)

मास्टर जोगी राम: अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्र न है। ये पहले जनता पार्टी में थे और अब भारतीय जनता

पार्टी में हैं। वे भाई पहले जनता पार्टी में थे लेकिन अब लोकदल में हैं। इसलिए अगर हम जनता पार्टी से कांग्रेस में आ गए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं हुई।(विघ्न)

चौधरी ई वर सिंह: डा० साहब ने तो आज तक कभी किसी हरिजन के घर में चाय भी नहीं पी होगी।

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, यह कहना कष्ट तक रैलेवैन्ट है कि डा० साहब ने कभी किसी हरिजन के घर में चाय नहीं पी होगी? हम तो चाय रोज हरिजनों की ही पीते हैं। मेरी गाड़ी का ड्राईवर भी हरिजन हैं। (विघ्न)

चौधरी ई वर सिंह: स्पीकर साहब, डा० साहब जब वजीन थे तो मोम का कोटा देने का काम इनके हाथ में था। क्या डा० साहब बताएंगे कि इन्होंने अपने वक्त में कितने हरिजनों को परमिट दिए? ये आकड़े निकाल कर देखे ले और हरिजनो का नाम भी बता दें। (विघ्न)

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, इन्हे समझा दीजिए कि रूरल इंडस्ट्री स्कीम चौधरी देवी लाल ने ही स्वीकार की थी।

लोक निर्माण मंत्री(कंवर राम पाल सिंह): आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर अध्यक्ष महोदय, मैम्बर साहब बोल रहे हैं लेकिन डा० मंगल सैन जी बगैर आप की परमिशन के जब जी करता है बोलने के खड़े हो जाते हैं। उन्हें चाहिए की वे आनरेबल मैम्बर को बोलने दें। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: नो इंट्रपान पलीज। ई वर सिंह जी आप सिर्फ बजट पर बोलें।

चौधरी ई वर सिंह: स्पीकर साहब मै बजट पर ही बोल रहा था। मै बता रहा था कि इन्होंने अपने समय में हरिजनों के लिए क्या कुछ किया था।

श्री अध्यक्ष: आप अब वाईन्ड-अप कीजिए। आप को बोलते हुए 17 मिनअ हो गये है।

चौधरी ई वर सिंह: स्पीकर साहब, चौकिदारों की तरफ आज तक किसी सरकार का ध्यान रही गया था लेकिन यह चौधरी भजन लाल की सरकार है जिसने बिना किसी रिप्रैजेन्टान के, बिना किसी डैपुटेन के उनाक वेतन 50 रूपये बढ़ा कर 100 रूपये किया हैं। इसी तरह से इस सरकार ने बाल्मीकी भाईयो के भी 50 रूपये बढ़ाए है। (गोर)

श्री अध्यक्ष: ई वर सिंह जी, अब आप समाप्त किजिए।

चौधरी ई वर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मै अपने मंत्री जी और अपनी सरकार से यह भी प्रार्थना करूंगा कि हरिजनों की क्लास वन ओर क्लास टू में भी रिजर्वेन होनी चाहिए। (विघ्न) स्पीकर साहब, आरक्षण विरोधी कुछ तत्व हैं। इन आदमियों को चाहिए था कि पिछडे लोगो से जब पहले समय में बेगार ली जाती थी तो उसका विरोध करते। गांव मे पटवारी, सिपाही यानि चपडासी से लेकर अफसर तक हरिजनों का स्वीपरो के सिवाए

किसी भी कटौतरी में कोटा पूरा नहीं हैं। स्वीपर का कोटा पूरा करने के लिए दुसरा कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हैं। अगर पूरा 20 परसेन्ट कोटा है तो केवल स्वीपरों में ही पूरा है। (गोर) इसलिए मैं यह चाहूंगा कि ऐसे तत्व जो पिछड़े हुए वर्गों, चाहे वे हरिजन हैं या अन्य जातियां हैं, उनका विरोध करते हैं उसका भी प्रबन्ध किया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आजकल रिजर्वेशन के विरोध में एक लहर चल रही है। सरकार ने बैकवर्ड निगम बनाई है और उसके लिए दो करोड़ रुपये का प्रबन्ध किया है। लेकिन इतने से उस का काम चलने वाला नहीं हैं। जितनी प्रगति की आवश्यकता है उतनी नहीं हो सकेगी। (गोर)

इन भावों के साथ मैं इस बजट की पुरजोर तार्किक करता हूँ।

श्री अध्यक्ष: श्री हरफूल सिंह। वे हाजिर नहीं हैं। श्री देवी दास। वे भी बैठे नहीं हैं। इसलिए अब मैं राव बंसी सिंह को बोलने के लिए काल अपॉन करता हूँ।

राव बंसी सिंह(अटेंली): अध्यक्ष महोदय, दो दिनों से चौधरी खुरीद अहमद द्वारा पेश किए गए वर्ष 1981-82 के बजट पर बहस हो रही है। (गोर)

नेमिंग आफ मैम्बरज

स्वामी अग्निवेश: स्पीकर साहब, अब अपोजिशन की टर्न है इसलिए मुझे बोलने का समय दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: अब मैं राव बंसी सिंह जी को काल अपोन कर चुका हूँ और उन्होंने बोलना भी शुरू कर दिया है। उनके बाद आप को समय दूंगा।

स्वामी अग्निवे I: स्पीकर साहब, अब हमारी बारी है, इसलिए मुझे बोलने दिया जाए। ये अपनी टर्न पर बोल सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: स्वामी जी मैंने अपोजी इन के दो मैम्बर्ज को बोलन के लिए काल अपोन किया था लेकिन वे हाजिर नहीं हैं। अब इधर से राव बंसी सिंह जी बोल रहे हैं। इनको खतप कर लेने दो, उसके बाद आपको समय दूंगा।

स्वामी अग्निवे I: अध्यक्ष महोदय, अगर अब मुझे समय नहीं दिया जाता है तो मैं वाक आउट करता हूँ। यह पक्षपात किया जा रहा है।(गोर)

Mr. Speaker: I take strong objection to these words. (Interruptions and noise) I name Swami Agnivesh.

स्वामी अग्निवे I: मैं तो खुद वाक-आउट कर रहा हूँ।(व्यवधान एव गोर)

श्री अध्यक्ष: जनता पार्टी के चार सदस्य हैं जिनमे से तीन सदस्य बोल चुके हैं यानी 75 परसेन्ट बोल चुके हैं। फिर भी अगर ऐसे भाब्द इस्तेमाल करेंगे तो मैं स्ट्रिक्ट एव इन लूंगा। You may please withdraw from the House.

स्वामी अग्निवे T: मै जा ही रहा हूं।

Mr. Speaker: All right] you kindly leave the house.

स्वामी अग्निवे T: मै तो जा ही रहा हूं। (गोर एव
विघ्न)

(The Hon. Member did not withdraw from the House)

Mr. Speaker: Marshal, Please take him out of the
House.

स्वामी अग्निवे T: मा ल की कोई जरूरत नहीं है। मै
तो खुद ही जा रहा हूं।

Mr. Speaker: If anybody accuses me of partiality, I
will not tolerate it (Interruptions and noise).

(At this stage the Sermeant at Arms went to the
Hon. Member, Swami Agnivesh).

श्रीमति सुशमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय ये तो खुद ही
हाउस से बाहर जा रहे हैं।

Mr. Speaker: He should kindly leave the House.

श्रीमति सुशमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, आप इतने
नाराज न हो।(गोर)

Mr. Speaker: I will not tolerate any such comments
where a member accuses me of partiality. Kindly leave the
House. (Noise and Interruptions).

स्वामी अग्निवे 1: मै जा रहा हूँ।

(At this stage Swami Agnivesh Left the House)

श्रीमति सुशमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर हैं।

Mr. Speaker: Please take your seat.

देखिए मैम्बर साहबान, जनता पार्टी के सदस्यों को मैंने मैक्सीमम टाईम दिया है। ये चार सदस्य हैं जिनमे से तीन बोल चुके हैं। बजट पर डिस्कान को केवल दो या अढाई दिन ही हुए हैं। तीन सदस्य बोल चुके हैं यानी 75 परसेन्ट बोल चुके हैं। उनके लीडर श्री बलदेव तायल मेरे पास आये थे। मैंने उनसे कहा था कि आपके दो सदस्य पहले दिन बोल चूके हैं, दूसरे दिन मैं पहले अग्निवे 1 जी को बुलवाऊगां, फिर भांकर लाल जी को बुलवाऊगां। इन्होने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि नह, पहले कापरेड भांकर लाल जी को बुलवायें। गवर्नर ऐड्रेस की बात थी। उस पर भी इनको इनके टाईम से ज्यादा टाईम दिया। इसके बावजूद भी अगर ऐसी बातें कही जाएं तो मेरे को बड़ा दुख होता है। स्वामी अग्निवे 1 अपने आपको महात्मा और साधु कहते हैं, उसके बावजूद भी उन्होने ये भाब्द इस्तेमाल किये कि चैयर पार्लियामेण्ट इस्तेमाल कर रही है। बड़े दुख की बात है। मैं समझता हूँ ऐसी बात पुरे हाउस को कन्डैम करनी चाहिए।

श्रीमति सुशमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय,-----

Mr. Speaker: No Please. I will not tolerat any such thing.

(At this stage some members, insluding shri Baldev Tayal, stood up) (Noise)

Shri Baldev Tayal: We will not tolerate any such thing. (Interruptions and Noise).

Mr. Speaker: Please take your seat. (Interruptions and Noise)

Shri Baldev Tayal: No, we will not tolerate any such thing.

Mr. Speaker : I name Shri Baldev Tayal. He May please leave the House.

(इस समय श्री बलदेव तायल हाउस से बाहर चले गये)

श्रीमति सुशमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, आन ए प्वायंट आफ आर्डर। मेरा कहना यह है * * * * * (तोर)

Mr. Speaker: I Will not accept any reflection on the chair.

Shrimati Sushma Swaraj: On a point of order, sir.

श्री मूल चन्द जैन: स्पीकर साहब, जहां तक स्वामी जी ने पक्षपात वाली बात कही * * * * * (भाोर एव व्यवधान)

Mr. Speaker: I was accused of partiality inspite of the fact that I have already given the time to speak to 75% of the Janata Party members.

Shrimati Sushma Swaraj: I have to make one submission, Sir.....

श्री अध्यक्ष: भारतीय जनता पार्टी के मेरे ख्याल मे तीन या चार मैम्बर बोल चुके है। भायद दो या तीन लोक दल के बोले हैं। जनता पार्टी के भी 75 प्रति त मैम्बर्ज बोल चुके है।

चोधरी हुक्म सिंह: हमारी पार्टी को सिर्फ एक बोला है।

श्री अध्यक्ष: नही मेरे पास रिकार्ड है। श्री रण सिंह मान बोल चुके हैं और बाबू मूलचन्द जैन बोल चुके है। तीन या चार आपकी तरफ से बोल चुके है और चार-पांच उनकी तरफ से बोल चुके हैं। दो या तीन जनता पार्टी के बोल चुके हैं।

श्रीमति सुशमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, हमारी तरफ से केवल भांकर लाल जी ही बोले हैं। (गोर एव व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नही, आम अपने मैथेमैटिक्स को सुधारिए। कृपया आप बैठिए।

श्रीमति सुशमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, आप जरा गुस्सा कम करके रिकार्ड तो देखें।

श्री मूल चन्द जैन: स्पीकर साहब, मै यह बात कह रहा था कि ये लोग गवर्नर ऐड्रैस पर बोले है।

श्रीमति सुशमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, आप जरा गुस्सा कम करके रिकार्ड तो देखें, कल बजट पर कामरेड भांकर

लाल जी बोल है। मैं और श्री बलदेव तायल गवर्नर ऐंड्रैस पर बोले है। बजट पवल भांकर लाल ही बोले है।(विघ्न) अध्यक्ष महोदय, पहले आप मेरी बात सुन ले। आप बिना वजह नाराज क्यों हो रहे हैं? अगर आप मेरी एक मिनट बात सुन लेंगे जो बिल्कुल सही हो जाएगा।

Mr. Speaker: If I am accused of partiality, I will not tolerate any such thing. I will resign from this chair. I am not interested in it. I will maintain discipline and will not tolerate of being accused of partiality when it is against facts. I can resign today from this Chair. I say it from the bottom of my heart.

श्रीमति सुशमा स्वराज : इसमें रिजाइन करने की क्या बात है?

श्री अध्यक्ष: मैं धर्म से कह सकता हूँ कि वक्त वे वक्त मैं ट्रेजरी बैचिंग को दबाता हूँ और ओपीजी इन को ज्यादा महत्व देता हूँ।

श्रीमति सुशमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, आपके पास मिस-इन्फॉर्मे इन हैं। मैं आपसे यह कह रही हूँ कि जो आप बार-बार कह रहे हैं कि जनता पार्टी के तीन सदस्य बोले हैं, जनता पार्टी का केवल एक सदस्य बजट पर बोला है। यह मिस-इन्फॉर्मे इन है जो आप यह कह रहे हैं कि हम तीन लोग बोले हैं।

श्री अध्यक्ष : मैंने वायदा किया था कि आपके चारों
मैम्बरो को दोनो मौको पर बुलवा दूंगा। But you cannot be the
first to speak on every occasion.

Shrimati Sushma Sawraj: Of Course, I may not be
the first, but he too can not be the first to speak.
(Interruptions and Noise).

श्रीमति सुशमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, हमने आपके
चैम्बर में दरखास्त की थी। आपने कहा था कि हमारी पार्टी के
मैम्बर्ज को टाईम मिलेगा (गोर)

श्री अध्यक्ष : क्या आप चाहती है कि आपकी पार्टी के
हंडर्ड परसेन्ट मैम्बर बोले ओर इधर से ये 25 परसेन्ट बोले।

श्रीमति सुशमा स्वराज : हम 100 परसेन्ट तो नहीं बोले
है। अगर स्वामी अग्निवे 1 जी बोल लेते हो पच्चास परसेन्ट हो
जाते।

Mr. Speaker: No, if you had counted both the
occasions और अगर स्वामी जी को बुलवा लेते तो 100 प्रति 100
हो जाता। Since your group is small, I wanted to give you
maximum time.

श्रीमति सुशमा स्वराज: मैं आपसे दरखास्त करूंगी, आप
नाराज न हों

Mr. Speaker: If anybody uses the word “partiality”
for me, I will not tolerate it. (Interruptions)

श्रीमति सुशमा स्वराज: आप पहले कम करके मेरी बात सुनें। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट यह है कि अगर कोई सदस्य वाक आउट करने की बात करता है और वह पहले ही यह कहता है कि मैं वाक आउट कर रहा हूँ तो क्या आप उसे नेम कर सकते हैं ?

Mr. Speaker: I have heard your point. Please sit down.

Smt. Sushma Swaraj: I want your ruling, Sir.

Mr. Speaker: Yes, the Speaker can name him. This is my ruling. (Interruptions and noise)

Smt. Sushma Swaraj: Under what Rule?

Mr. Speaker: Please don't contest my ruling. I am warning you. (Interruptions and noise) Please take your seat.

(Smt. Shushma Swaraj did not resume her seat).
(Interruptions)

Mr. Speaker: I name Smt. Shushma Swaraj. She may please leave the House.

श्रीमति सुशमा स्वराज: अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात तो सुनें (तोर एवं विघ्न)

Mr. Speaker: Marshal, please take her out of the House. (Interruptions and noise)

(At this stage the Serjeant-at-Arms went to the hon. Member, Smt. Sushma Swaraj and She withdrew from the House.)

बैठक का स्थगन

Dr. Mangal Sein: May I submit, Sir
(Interruptions and Noise).

(At this stage some other Members from the opposition rose to speak and there was noise).

Mr. Speaker: The House stands adjourned till 2.00 p.m. on Monday.

13.20 बजे

(The Sabha then adjourned till 2.00 p.m. on Monday, the 23rd March, 1981)

ANNEXURE

APPOINTMENT OF CLERKS THROUGH S.S.S. BOARD

***2048. Sh. Bhale Ram:** Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) the number of clerks appointed so far through the Subordinate Services Selection Board during the period from 1-11-1980 to-date; and

(b) the number of persons belonging to Scheduled Castes and Backward Classes out of those referred to in part (a) above together with the percentage thereof?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) 692

(ख)

| | | |
|---------------------------------------|----|----------------|
| अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित व्यक्ति | 80 | 11.56 प्रति ात |
| पिछड़ी जातियों से सम्बन्धित व्यक्ति | 71 | 10.26 प्रति ात |